चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

दोस्तों ने जॉर्ज को बचाने की अपील की

पेज 2

अब संघ के शिकंजे में है भाजपा

पेज 3

सवाल पूछो, ज़िंदगी बदलो

पेज 11

सफलता की राह में अंध विश्वास बाधा है

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 1 मार्च-7 मार्च 2010

आरुषि की हत्या फाइल बंद

कमरे में आरुषि की लाश, सीढ़ियों पर घिसटने से बने ख़ून के निशान, छत पर हेमराज की लाश. उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीआई की दो महान खोजी टीमें क़ातिल तलाशने में नाकाम. संदेह के घेरे में तीन कम पढ़े लिखे नौकर और एक संभ्रांत परिवार. क्या सीबीआई की ट्रेनिंग और अपराध शास्त्र को जानने वाले अधिकारी इनसे जाहिल माने जाने चाहिए? शर्म आनी चाहिए जांच एजेंसी को, जो आरुषि हत्याकांड की फाइल अब बंद करने जा रही है.

अरे.........!
कमाल की बात करती हैं आप?
क्या कहना चाहती हैं?
जब सीबीआई को ठोस सबूत मिले ही नहीं तो वह कोर्ट में भला क्या पेश करती?
क्या फ़र्ज़ी सबूत पैदा करती?
अब इस देश का जूडिश्यिरी सिस्टम ही ऐसा है कि वह नारको एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत नहीं मानता तो भला सीबीआई क्या कर सकती है?

रूबी अरुण

भड़क उठते हैं. देश में सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के एक बड़े अधिकारी. जब उनसे हज़ार बार पहले भी पूछा गया सवाल एक बार फिर किया जाता है कि नोएडा के आरुषि हेमराज के हत्यारों का पकड़ने में क्यों नाकाम रही सीबीआई? अगर ऐसा है कि नारको टेस्ट कराने से सीबीआई को कुछ ख़ास हासिल नहीं होता, तो फिर ज़रूरत क्या थी कि वारदात के इतने दिनों बाद, तमाम फज़ीहतों, सवालों और आरोपों को झेलने के बाद, सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता के नारको टेस्ट कराए? वह भी तब, जबकि डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नुपुर तलवार ने तो पहले भी कहा था कि वे नारको टेस्ट के लिए तैयार हैं.

केंद्रीय जांच एजेंसी के यह बड़े साहब दबी मुस्कान के साथ फरमाते हैं कि दरअसल यह टेस्ट इस केस को लेकर लोगों के मन में उपजी ढेर सारी आशंकाओं को ख़त्म करने की गरज़ से किया गया है, ताकि लटके पड़े इस केस की फाइनल रिपोर्ट अदालत में दाख़िल की जा सके. पहले इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी. तब लगा था कि शायद ऐसा कोई सबूत मिल जाए जो आरुषि के हत्यारों को सज़ा दिलाने में मददगार हो सके. अब सीबीआई ने भी मान लिया है कि वह इस केस को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती.

वाह. बहुत ख़ूब.....!

मतलब यह कि भारी हंगामे और मीडिया के शोरशराबे के बाद आरुषि की मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार का बंगलुरु में नारको एनालिसिस टेस्ट इसलिए नहीं कराया गया कि इससे सीबीआई को इस केस के गुनहगारों को पकड़ने की दिशा में कोई लीड मिल सके, बल्कि इसलिए कि इस केस की फ़ाइल बंद कराई जा सके.

सीबीआई की यह नंगी हकीक़त यक़ीनन आपको बेहद हैरान करेगी, पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का कड़वा सच यही है. तफ़्तीश के नाम पर लोगों की आंख में धूल झोंकना. सीबीआई से न्याय की आस बांधे मज़लूमों को बेवकूफ़ बनाना. हां, अगर पीड़ित या आरोपी कोई सियासी शख्सियत है तो फिर बात अलग है. क्योंकि, तब इन्हीं सीबीआई अधिकारियों में अपनी-अपनी क़ाबिलियत साबित करने की होड़ मच जाती है. ये बातें हम किसी खुन्नस में नहीं कह रहे, बल्कि सीबीआई की हरक़तें ख़ुद ही ये बातें बयान कर रही हैं.

सबके ज़हन में अभी भी ताज़ा है नोएडा का दिल दहला देने वाला बेहद सनसनीखेज़ आरुषि हत्याकांड. इसकी जांच का ज़िम्मा बड़ी उम्मीदों के साथ सीबीआई को सौंपा गया था. उम्मीद बंधी थी कि जो काम उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर पाई, वह सीबीआई तो ज़रूर कर लेगी. आरुषि के हत्यारे पकड़े जाएंगे और इस रहस्यमय हत्याकांड की अनकही कहानी का ख़ुलासा हो पाएगा. पर सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जांच तो सीबीआई ने की, पर आज तक कोई नतीज़ा उसके हाथ नहीं लग सका. तब सीबीआई ने वही किया, जिसका अंदेशा था. बग़ैर क़ातिल को बेनक़ाब किए सीबीआई ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड के इस केस में फाइनल रिपोर्ट दाख़िल करने का फैसला कर लिया है. आरुषि की मां नुपुर तलवार और पिता राजेश तलवार का नारको टेस्ट नहीं कराने को लेकर भी सीबीआई पर उंगलियां उठ रही थीं. चूंकि आरुषि के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार पर भी अपनी बेटी की ही हत्या के आरोप लग चुके थे. इसलिए सीबीआई भी इस इल्ज़ाम से घिरी थी कि वह उन्हें बचाना चाहती है. लिहाज़ा उनका यह टेस्ट करा कर सीबीआई ने इस कलंक से मुक्त होने का भी एक आधार बना लिया है. दोनों के नारको टेस्ट के बाद भी सीबीआई को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिसके दम पर वह इस सबसे चर्चित मर्डर-मिस्ट्री के सुलझ जाने का एतबार लोगों को दिला सके. हालांकि जो हालात रहे हैं, उनमें एक बात आईने की तरह साफ़ रही है कि सीबीआई ने कभी चाहा ही नहीं कि वह आरुषि के हत्यारों को सज़ा दिलाए.

दरअसल देखा जाए तो शुरू से ही इस केस में सीबीआई के आला अधिकारियों का रवैया विवादास्पद रहा. उनकी तफ़्तीश में कभी भी इस केस की तह तक जाने की गंभीरता नहीं दिखी. छानबीन का नतीज़ा तो अजीबोग़रीब रहा ही, तफ़्तीश के तरीक़े को लेकर भी आपस में अधिकारियों की खींचतान ख़ूब रही. इस केस के बारे में सबकी अलग-अलग राय थी. हत्याकांड की जांच के लिए जिन अधिकारियों की टीमें बनाई गईं, उनके बीच भी मतभेद रहा. कुछ कयासों के दम पर अपनी अवधारणा बनाते रहे तो कुछ सबूत पाने में नाकाम रहने की वज़ह से उत्तर प्रदेश की पुलिस को कोसते रहे. कोसने के इस नेक काम में तत्कालीन सीबीआई निदेशक विजय शंकर तिवारी भी पीछे नहीं रहे. जब भी उनसे हम यह सवाल करते कि आख़िरकार कब पकड़ा जाएगा आरुषि का क़ातिल? तो वह बड़ी अदा से जवाब देते कि अगर नोएडा पुलिस ने इस केस के सबूतों के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता तो सीबीआई महज़ चौबीस घंटों में ही इस गुत्थी को सुलझा लेती. पर क़ातिल कौन है? इस सवाल के जवाब में वह अपनी मूछों पर ताव तो ज़रूर देते, पर जवाब कतई नहीं. इस मामले की छानबीन को लेकर एक और दुखद बात रही. जांच में लगे अधिकारियों को उनके विवेक के आधार पर काम करने की स्वतंत्रता नहीं रही. जिसने भी कर्तव्य से वशीभूत होकर ऐसा करना चाहा तो उसे किसी न किसी बहाने टीम से बाहर निकलना पड़ा.

अश्विनी कुमार, *सीबीआई निदेशक*

पहले इस केस की तहक़ीक़ात ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार के निर्देशन में डीआईजी ज़की अहमद कर रहे थे. ज़की अहमद की छानबीन में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जो तत्कालीन सीबीआई निदेशक विजय शंकर तिवारी को नहीं भाए. इस मुद्दे पर ख़ूब बहस भी हुई. आख़िरकार ज़की अहमद को इस केस से अलग होना पड़ा. वज़ह पूछने पर बताया गया कि घरेलू कारण से उन्होंने छुट्टी ले ली. पर जब ज़की अहमद से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. बहरहाल ऐसे और भी वाकए हुए. कहते हैं कि विजय शंकर की इच्छा थी कि उनके डायरेक्टर के पद पर रहते हुए ही देश के इस सबसे चर्चित केस को सुलझा लिया जाए, ताकि वह इसका श्रेय लेकर ही रिटायर हों. पर इस केस में चूंकि सभी अधिकारी अपनी- अपनी डफली बजाने में लगे थे, लिहाज़ा विजय शंकर तिवारी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी.

डीआईजी ज़की अहमद के बाद इस केस की कमान सौंपी गई डीआईजी आलोक रंजन को. अरुण कुमार तो ख़ैर बने ही हुए थे. नए निदेशक अश्विनी कुमार ने पद संभाला और सबको यक़ीन दिलाया कि जल्दी ही आरुषि का क़ातिल सबके सामने होगा. पर कुछ ही दिनों बाद वह भी अपने इस बयान से मुंह चुराते नज़र आए. अभी तक इस केस में मोड़ तो कई आए, पर नतीज़े के तौर पर कुछ भी नहीं. डॉक्टर राजेश तलवार, जो बेटी के क़त्ल के इल्ज़ाम में जेल में थे, वह अपने ख़िलाफ़ सबूत न मिलने के कारण ज़मानत पर रिहा हो चुके थे और उनका कंपाउंडर कृष्णा अपने दोस्त राजकुमार एवं विजय मंडल के साथ सीबीआई की हिरासत में था. इन सभी से सीबीआई की पूछताछ और इन सबका वैज्ञानिक परीक्षण जारी था. सीबीआई के तथाकथित कार्यकुशल और तेज़तर्रार अधिकारी कृष्णा, राजकुमार एवं विजय मंडल से राज़ उगलवाने की मशक्कत में हलकान हो गए, पर इन तीन अनपढ़ों ने अधिकारियों की पूरी टीम को अपने शातिरपने से पानी पिला दिया. आख़िरकार एक रात छह घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अपनी सेल में लौटते कृष्णा ने केंद्रीय जांच एजेंसी के बड़े-बड़े अधिकारियों की नाकामी पर तरस खाकर हंसते हुए कहा कि पहले मैंने बेटी को मार कर उसके बाप को फंसा कर अपना बदला ले लिया और अब मैंने आप लोगों के पसीने छुड़ा दिए. कर लीजिए जो कुछ करना है, पर सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा.

बिल्कुल यही हुआ भी. एक नौकर, जो हत्या के आरोप में सीबीआई के घाघ अधिकारियों की सख्त गिरफ़्त में है, वह उन्हें खुलेआम ललकारता है और सीबीआई के उच्च प्रशिक्षित अधिकारी लाचार-बेबस बने उसका मुंह ताकते रह जाते हैं. इन नौकरों का नारको एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है. डॉ. राजेश तलवार के दोस्त प्रफुल्ल दुर्रानी का कंपाउंडर राजकुमार यहां भी सीबीआई को गच्चा दे जाता है. उसे बेहोशी के लिए जो ट्रूथ सीरम दिया जाता है, उस पर असर ही नहीं करता. दोबारा उसका टेस्ट करना पड़ता है. कृष्णा टेस्ट में यह स्वीकार कर लेता है कि उसने राजकुमार के साथ मिलकर आरुषि का क़त्ल किया था. फिर भी सीबीआई उसे गुनहगार साबित नहीं कर पाती. न ही हत्या में इस्तेमाल हथियार ही बरामद कर सकी?

आरुषि और हेमराज का मोबाइल फोन भी सीबीआई के हाथ नहीं लग सका. न ही वारदात की जगह से पाए गए ख़ून के धब्बों से ही वह कुछ पता लगा सकी. आरुषि के बिस्तर पर पड़े दाग, सीढ़ियों पर पड़े निशान, छत पर दीवारों पर पड़े ख़ून के बड़े-बड़े धब्बे, छत पर रखे कूलर के पानी में घुला ख़ून, राजेश तलवार के घर में मिली खाली शराब की बोतल पर पड़े क़ातिलों की उंगलियों के निशान, कृष्णा के कमरे से मिली खुखरी, राजकुमार का ख़ून लगा टी शर्ट, इन सारी चीज़ों के वैज्ञानिक परीक्षण के नाम पर सीबीआई ने बखेड़ा तो बहुत खड़ा किया, पर सबूत कुछ नहीं जुटा सकी. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को ज़मानत दे दी. पर इस केस की जांच में लगे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार बस एक ही राग अलापते रहे कि आला-ए-क़त्ल की बरामदगी की कोशिश की जा रही है. टीम दर टीम बनती रही. छानबीन का नाटक चलता रहा. सरकारी पैसों को साइंटिफिक टेस्ट के नाम पर फूंका जाता रहा. इंसाफ़ की आस में बैठे लोग सीबीआई पर अपना भरोसा जताते रहे. आरुषि को न्याय दिलाने के लिए धरना-प्रदर्शन किया जाता रहा. बस, जो नहीं हुआ, वह यह कि सीबीआई के बड़े-बड़े तुर्रम खां अधिकारी भी इस केस को सुलझा नहीं सके.

ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब तो सीबीआई के बड़े-बड़े हाक़िम ही दे सकते हैं. पर एक आम आदमी की समझ में यह बात नहीं आ रही है कि ऐसी क्या-क्या मुश्किलें थीं, जिनकी वज़ह से यह मामला अनसुलझा रह गया. दो लाशें मिलीं. इतने सारे सबूत मिले. नालियां, पानी की टंकियां, पार्क, छत, कूड़ेदान, सभी कुछ छान मारा गया. कई-कई बार. वह भी आरोपियों के बयान के आधार पर. फिर भी सीबीआई के दिग्गज़ों को मुंह की खानी पड़ी? जबकि आरोपी के तौर पर उसकी गिरफ़्त में आरुषि के पिता सहित तीनों नौकर भी थे. बकौल सीबीआई, उसके पास नारको टेस्ट की सीडी में कृष्णा का क़बूलनामा भी मौज़ूद है. बावज़ूद इसके वह लाचार और बेबस है.

देखा जाए तो सीबीआई से कहीं बेहतर और निर्णायक काम नोएडा पुलिस ने किया था. हालांकि उसकी हड़बड़ी और कार्यशैली को लेकर विवाद भी हुए. इस वज़ह से मेरठ रेंज के डीआईजी गुरशरण सिंह पर भी गाज़ गिरी. मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री मायावती को भी मैदान में कूदना पड़ा. सबको लगा कि नोएडा पुलिस मामले के साथ न्याय नहीं कर पाएगी, इसलिए सीबीआई ही इसकी जांच करे, तभी इंसाफ़ हो पाएगा. पर सीबीआई ने तो पूरे मामले को ही दफ़न कर दिया.

कितनी हैरानी और तक़लीफ़ की बात है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर तीन कथित गंवार नौकर भारी पड़ गए और जिन्होंने पूरी सीबीआई को हिलाकर रख दिया? ऐसे में भला क्या औचित्य रह जाता है सीबीआई के होने का? क्या यह सब इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि सीबीआई का मूल मक़सद इस फ़ाइल को बंद करना ही हो गया है!

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ने अपने पिछले दो अंकों में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था कि कैसे तीमारदारी के नाम पर जॉर्ज का तथाकथित परिवार उन्हें अपनों से, उनके दोस्तों से और यहां तक कि उनकी जिंदगी से भी दूर करने की साजिश कर रहा है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

परंपरा की अनदेखी

हाल में जब कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा हुई तो एम के नारायणन के कोलकाता पहुंचने को सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियां मिलीं. लेकिन, जानकार लोगों की मानें तो विवादास्पद श्रेणी में आने वाली यह अकेली नियुक्ति नहीं है. पूर्व रक्षा सचिव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार रहे शेखर दत्ता को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया जाना अभी भी कई लोगों को चौंका रहा है. इन लोगों का मानना है कि दत्ता को रायपुर भेज कर केंद्र सरकार ने एक बड़ी पुरानी परंपरा का उल्लंघन किया है. इस परंपरा के मुताबिक़, किसी राज्य के निवासी या नौकरशाह के रूप में कार्य कर चुके लोगों को वहां का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है.

इस परंपरा के पीछे स्पष्ट कारण हैं. राज्यपाल का पद स्थानीय राजनीतिक उठापटक से ऊपर की चीज़ है. ग़ौरतलब है कि शेखर दत्ता मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ इसी राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, कैडर के ही आईएएस अधिकारी हैं. माना जाता है कि दत्ता के छत्तीसगढ़ में पुराने और प्रभावशाली संपर्क हैं. उनकी नियुक्ति के पीछे किसी छुपी हुई ताक़त या उनके पारिवारिक संपर्कों की भूमिका से इंकार करने वाले लोगों का तर्क है कि छत्तीसगढ़ से दत्ता का पुराना जुड़ाव ही राज्य के राज्यपाल के रूप में उनकी नई भूमिका में सबसे ज़्यादा मददगार हो सकता है. छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या के मद्देनज़र सुरक्षा मामलों में लंबे अनुभव ने भी दत्ता के पक्ष में माहौल बनाया

और सरकार बरसों पुरानी परंपरा को सिरहाने रखने के लिए तैयार हो गई. लेकिन, लाख टके का सवाल तो यह है कि आख़िर उनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था!

शरण राज्यमंत्री होंगे!

अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है कि पूर्व विदेश सचिव और क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि श्याम शरण को केंद्रीय राज्यमंत्री का दर्ज़ा मिल सकता है. जानकारों की राय में इसकी वजह शरण से कनिष्ठ रहे शिवशंकर मेनन की राज्यमंत्री के दर्ज़े के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति है. रोचक तथ्य यह है कि यदि शरण को राज्यमंत्री का दर्ज़ा मिल जाता है तो वह पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश के समकक्ष हो जाएंगे. और, पर्यावरण से संबंधित मामलों पर दोनों के मतभेद जगज़ाहिर हैं.

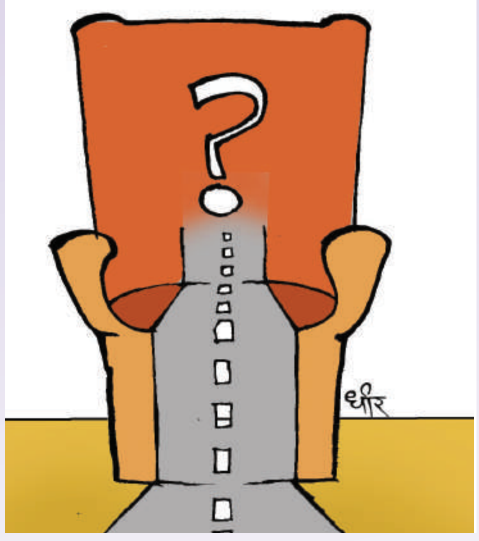

कुर्सी के लिए मारामारी

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) शायद आजकल देश के सबसे व्यस्त सरकारी संगठनों में से एक है. इसकी वजह केवल देश भर में चल रहे राजमार्ग निर्माण और विकास कार्य ही नहीं हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कमलनाथ की इच्छा के मुताबिक़, एनएचएआई आंतरिक पुनर्संरचना के दौर से गुज़र रहा है. रोचक बात यह है कि एनएचएआई के नए मुखिया की नियुक्ति होनी है और इसके लिए कई उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें प्राधिकरण के मौजूदा चेयरमैन बृजेश्वर सिंह और सड़क परिवहन मंत्रालय के वर्तमान सचिव ब्रह्मदत्त भी शामिल हैं. ताज्जुब की बात यह है कि दत्त उस कमिटी के भी सदस्य हैं, जो भावी उम्मीदवारों की जांच-परख कर रही है. लेकिन, मंत्रालय में इसे लेकर किसी के कान पर जूं रेंगती नहीं दिख रही.

सूत्रों की मानें तो एनएचएआई के मुखिया की कुर्सी के लिए मची होड़ की सबसे बड़ी वजह इसकी योग्यता-शर्तों में किया गया बदलाव है.

एक ओर मंत्रालय ने यह शर्त रखी है कि उम्मीदवार को केंद्र में सचिव या राज्य में प्रधान सचिव के पद पर तीन सालों का अनुभव होना चाहिए. दूसरी ओर कैबिनेट ने सेवानिवृत्ति की आयु को 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया है. यही वजह है कि सेवानिवृत्ति की बाट जोह रहे कई वरिष्ठ अधिकारी इस पद के दावेदार बन गए हैं. इन दावेदारों में एनएचएआई के पूर्व सदस्य के एस मणि, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एस एस खुराना, फॉरेन ट्रेड के महानिदेशक आर एस गुजराल एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य (इंजीनियरिंग) राकेश चोपड़ा शामिल हैं. इस सबसे अलग नौकरशाही मामलों पर नज़र रखने वाले लोग दुआएं कर रहे हैं कि प्राधिकरण के नए मुखिया का कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा होगा. ग़ौरतलब है कि पिछले चार सालों में एनएचएआई के मुखिया की कुर्सी पर पांच लोगों की ताज़पोशी और विदाई हो चुकी है.

दोस्तों ने जॉर्ज को बचाने की अपील की

अपीलकर्ताओं में अजय सिंह के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एन वेंकटचलैया, जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री फारुख़ अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्य लॉर्ड मेघनाद देसाई, पायोनियर के संपादक एवं पूर्व सांसद चंदन मित्रा, एस्सार समूह के वायस चेयरमैन रवि रुइया, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सहित कई गणमान्य लोग शामिल हैं.

जॉर्ज फर्नांडिस. एक ऐसा नाम, जो ग़रीब मज़दूरों, दलितों, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, मानवाधिकारों और हर तरह के अन्याय के ख़िलाफ़ संघर्ष में पिछले क़रीब तीन दशकों से हमेशा सबसे आगे रहा, आज ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष को मजबूर है. अथवा यूं कहें कि ज़िंदगी नहीं, जॉर्ज अपनी मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उम्र के इस आख़िरी पड़ाव और अल्जाइमर की छठी स्टेज में पहुंच चुका मरीज़ भला इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता है. लेकिन, ताज्जुब की बात तो यह है कि तमाम उम्र लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले जॉर्ज को इस हालत में अपनों से दूर कर दिया गया है. वह अपने घर से दूर हैं, अपनी किताबों, अपने पालतू पशुओं और यहां तक कि दशकों से साथ रहे अपने दोस्तों से दूर हैं. बरसों से उनकी चिकित्सा कर रहे डॉक्टर तक उनके साथ नहीं हैं. और, यह सब हो रहा है उनके परिवार के इशारे पर. उस परिवार के इशारे पर, जिसने पिछले पच्चीस सालों से उनकी कोई सुध नहीं ली. लेकिन, आज जब जॉर्ज के पास करोड़ों की संपत्ति होने की बात सामने आई तो यह परिवार अचानक उनका हमदर्द हो गया है. पत्नी लैला कबीर और बेटा श्यान फर्नांडिस आज उनकी खिदमत के लिए अमेरिका से भारत आ चुके हैं और उनकी तीमारदारी में जी-जान से लगे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है.

चौथी दुनिया ने अपने पिछले दो अंकों में इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया था कि कैसे तीमारदारी के नाम पर जॉर्ज का तथाकथित परिवार उन्हें अपनों से, उनके दोस्तों से और यहां तक कि उनकी ज़िंदगी से भी दूर करने की साज़िश कर रहा है. एक ओर डॉक्टरों का मानना है कि उन्हें ऐसे माहौल में और स्थान पर रहना चाहिए, जहां से उनकी पहचान हो. ऐसे लोग उनके आसपास हों, जिन्हें वह अच्छी तरह जानते हों. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा. इलाज के नाम पर उन्हें बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम ले जाया गया. वहां जाकर उनकी हालत में सुधार आया या नहीं, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का मानना है कि लैला कबीर संपत्ति के लालच में उन्हें अपने क़ब्ज़े में रखने का प्रयास कर रही हैं.

यह सच है कि लैला कानून की नज़रों में जॉर्ज की पत्नी हैं, लेकिन पिछले क़रीब तीन दशकों से उनका अपने पति के साथ कोई संपर्क नहीं रहा है. जॉर्ज को जानने वाले यह बात भलीभांति जानते हैं कि वह लैला को पसंद नहीं

करते. वैसे भी जॉर्ज की बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन इससे पहले तक लैला का उनसे कोई सरोकार नहीं था. वह तो अपने बेटे श्यान के साथ अमेरिका में आराम की ज़िंदगी गुज़ार रही थीं. जबकि जॉर्ज यहां हर पल घुट-घुटकर जीने को मजबूर थे. परिणाम यह है कि सारी उम्र हर तरह की गुलामी के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले जॉर्ज आज अपनों के ही गुलाम बनकर रह गए हैं.

अपने संपादकीय लेख में हमने अपील की थी कि जॉर्ज की हालत पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपनी बाकी बची ज़िंदगी आराम से गुज़ार सकें. अब यही काम जॉर्ज के कुछ दोस्तों ने किया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं फिजी में भारत के राजदूत रहे अजय सिंह के नेतृत्व में क़रीब 20 लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यही अपील की है. उनकी मांग है कि सरकार जॉर्ज की हालत को ध्यान में रखते हुए उनकी चिकित्सा और देखभाल के लिए उचित व्यवस्था करे.

इन लोगों में जॉर्ज के पुराने मित्र और उनके प्रशंसक शामिल हैं. इन्होंने मांग की है कि जॉर्ज की देखभाल के लिए एक पैनल का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों के अलावा उनके मित्र और परिवार के लोग शामिल हों. इनका मानना है कि जॉर्ज अभी जिन लोगों के साथ हैं, उन्हें न तो इस वयोवृद्ध नेता की बीमारी के बारे में ख़ास पता है और न ही उनका इससे कुछ विशेष लेना-देना है. वे तो बस अपने स्वार्थ के चलते उन्हें दुनिया की नज़रों से दूर करना चाहते हैं.

अपीलकर्ताओं में अजय सिंह के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एन वेंकटचलैया, जम्मू- कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, डायनामाइट कांड में जॉर्ज के साथ जेल में रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल वीरेन जे शाह, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक यू आर अनंत कृष्णमूर्ति, समाजसेविका एवं पर्यावरणविद वंदना शिवा, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के सदस्य लॉर्ड मेघनाद देसाई, पायोनियर के संपादक एवं पूर्व सांसद चंदन मित्रा, बजाज समूह के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य राहुल बजाज, पद्मश्री लीला सैमसन, बीट्रिक्स डिसूजा, लेखक किश्वर देसाई, लीला होटल समूह के अध्यक्ष कैप्टन सी पी कृष्णन नायर, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष राजेश जे शाह, एस्सार समूह के वायस चेयरमैन रवि रुइया, कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सहित कई गणमान्य लोग शामिल हैं. अपनी अपील में इन लोगों ने यह भी मांग की है कि मीडिया में आ रही तमाम तरह की ख़बरों को दरकिनार करते हुए सरकार और क़ानून जल्द से जल्द जॉर्ज की हालत पर ग़ौर करे.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 1 अंक 51,
दिल्ली, 1 मार्च–7 मार्च 2010

संपादक

संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–47839990/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इंदौर में देश भर से आए भाजपा नेताओं का जमावड़ा था. मीडिया के लोग थे. तीन दिनों तक चली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्सुकता थी.

अब संघ के शिकंजे में है भाजपा

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राह पर चलेगी. भाजपा पहले भी संघ के इशारे पर ही चलती थी, लेकिन थोड़ा पर्दा था. नए अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यह पर्दा भी उठा दिया है. पहले संघ के लोग कहते थे कि भाजपा के क्रियाकलापों में संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है और भाजपा के नेता कहते थे कि संघ उनके लिए वैचारिक प्रेरणास्रोत है, भाजपा के काम में संघ की कोई दख़लअंदाज़ी नहीं है. ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा के किसी अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यक्रम में संघ के अधिकारियों की हिस्सेदारी की बात कही है. पार्टी को मज़बूत करने की राह पर निकली भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मक़सद एक था, भाजपा को संघ के साए में लाना और संघ विरोधी भाजपा नेताओं को पार्टी की दुर्दशा के लिए ज़िम्मेदार बताना. इसके अलावा नए अध्यक्ष नितिन गडकरी ने राम मंदिर का राग अलाप कर भाजपा की ओर से यह संदेश दिया है कि पार्टी देश में सांप्रदायिक राजनीति को हवा देगी.

इंदौर में देश भर से आए भाजपा नेताओं का जमावड़ा था. देश- विदेश के मीडिया के लोग थे. तीन दिनों तक चली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्सुकता थी. वहां की हर पल की ख़बर न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आ रही थी. भाजपा के समर्थक एवं विरोधियों की नज़र इस बैठक पर टिकी थी. अपेक्षा यह थी कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यकारिणी के बाद नए अंदाज़ और नए तेवर के साथ उभरेगी. लेकिन, इस बैठक से भाजपा ने जो संदेश दिया है, वह न सिर्फ़ चौंकाने वाला है, बल्कि भाजपा समर्थकों के लिए निराशाजनक है. नितिन गडकरी पहली बार अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने थे. गडकरी के पास पार्टी में नई सोच, नई ऊर्जा और नई कार्य प्रणाली लागू करने का अवसर था. पार्टी को सही रास्ते पर लाने का सुनहरा मौक़ा था. यह मौक़ा बेकार चला गया. नितिन गडकरी अग्नि परीक्षा में खरे नहीं उतरे.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद गडकरी और नरेंद्र मोदी

नितिन गडकरी जब भी बोले, ऐसा लगा कि उनके मुंह से संघ बोल रहा है. नितिन गडकरी के सामने भाजपा को मज़बूत करने की चुनौती है. नितिन गडकरी भाजपा का नवनिर्माण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह करना चाहते हैं. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान नितिन गडकरी ने जितनी भी बातें कहीं, उनसे यही संकेत मिलते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर पार्टी बनाना चाहते हैं और उसके मुख्य पदों पर संघ के पूर्णकालिक एवं समर्पित कार्यकर्ता होंगे. कार्यकर्ताओं के निर्माण, विचारधारा, कार्यशैली और नैतिक आचरण के लिए भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से ही प्रेरणा ली जाएगी. गडकरी ने यह भी संदेश दिया कि जिस तरह संघ कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होता है, उसी तर्ज पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे.

फोटो-पीटीआई

संघ ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना शिकंजा कैसे कसा है, यह गडकरी के पूरे भाषण में झलक रहा था. राम मंदिर के बारे में जो बयान गडकरी ने दिया है, वही राग संघ और भाजपा पिछले कई सालों से अलाप रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. गडकरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वह अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सहयोग दे. उनका कहना था कि अगर मुस्लिम विवादित भूमि पर दावा छोड़ देते हैं तो मंदिर के पास ही मस्जिद बनाई जाएगी. ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गडकरी की बातों पर विश्वास करने वाला कोई मुस्लिम संगठन नज़र नहीं आ रहा है. नए अध्यक्ष ने ऐसा कोई काम भी नहीं किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय यह भरोसा करे कि पहले मंदिर बन जाने दो, फिर संघ और भाजपा के लोग वहां मस्जिद बनाने में मदद करेंगे. संघ और भाजपा के लोग भी यह जानते हैं कि उनकी बातों पर कोई मुस्लिम संगठन विश्वास नहीं करने वाला है. फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाने के पीछे क्या देश में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल तैयार करने का इरादा है. याद रहे कि यह मामला फ़िलहाल अदालत में है और इस साल ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं.

भाजपा हो या कांग्रेस, अगर उन्हें दलितों का समर्थन लेना है तो राहुल गांधी या नितिन गडकरी द्वारा दलितों के यहां जाने और खाने से कुछ नहीं होने वाला है. राष्ट्रीय पार्टियों का यह दायित्व है कि दलितों और आदिवासियों को वह अपने यहां नेतृत्व का मौक़ा दें. दलित समाज की समस्या, उसकी ग़रीबी और उसके शोषण के ख़िलाफ़ आंदोलन करें. अफ़सोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी मुख्य मुद्दे की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ़ राम मंदिर, धारा 370, यूनिफार्म सिविल कोड और गोवंश संरक्षण की बात होती है. इनमें दलितों के हिस्से का कुछ भी नहीं है. अगर भाजपा वाकई में दलितों का समर्थन लेना चाहती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गडकरी को दलितों के लिए किसी योजना की घोषणा करनी चाहिए थी. इसके अलावा दलितों के लिए पार्टी संगठन में आरक्षण या फिर दलितों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता तो बेहतर होता. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. नितिन गडकरी ने दलित के घर खाना खाया, मीडिया में इसका काफ़ी प्रचार भी हुआ. अब नितिन गडकरी ने अगले तीन सालों में भाजपा के वोट में दस फ़ीसदी बढ़ोत्तरी का वायदा तो किया है, लेकिन इसे अंजाम कैसे दिया जाएगा, इसका रोडमैप भाजपा के किसी भी नेता के सामने साफ़ नहीं है.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास आत्मनिरीक्षण करने का मौक़ा था. पिछले चुनाव में हार की वजह और ज़िम्मेदारी को तय करने का अवसर था. आज पार्टी की सबसे बड़ी समस्या वैचारिक और सांगठनिक है, जिसकी वजह से आज भाजपा पहचान के संकट से जूझ रही है. हैरानी की बात यह है कि भाजपा उन राज्यों में सांगठनिक चुनाव नहीं करा सकी, जिनके दम पर पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी. अगर पार्टी को मज़बूत करना है तो जिन मुख्य राज्यों में भाजपा के सांगठनिक चुनाव नहीं हो सके हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए थी. जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके कारणों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी. पार्टी को आपसी फूट और नेताओं के स्वार्थ से कैसे निजात दिलाई जाए, उस पर विचार होना चाहिए था. जिन राज्यों में भाजपा अब तक कुछ नहीं कर सकी है, उन राज्यों में पार्टी को मज़बूत करने के लिए मंथन होना चाहिए था. भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष से यह अपेक्षा थी कि वह एक सर्जन की तरह पार्टी का ऑपरेशन करके बीमारी दूर करते, लेकिन पूरे भाषण में वह एक मरीज की तरह पार्टी की बीमारियों को ही बताते नज़र आए.

आज भाजपा कार्यकर्ता जब यह देखता है कि पार्टी के नेता अपने-अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो यह सोचता है कि वह पार्टी के लिए क्यों काम करे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान कार्यकर्ताओं के मन में उठे इस सवाल का जवाब पार्टी को ढूंढना चाहिए. लेकिन इस दौरान उन्होंने उन बातों को दोहराया, जो पहले से ही भाजपा कार्यकर्ताओं को मालूम हैं कि पार्टी की दुर्दशा दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं की वजह से है. अच्छा होता कि गडकरी वरिष्ठ नेताओं की ग़लतियां गिनने के बजाय उन ग़लतियों को सुधारने का कोई फॉर्मूला बताते.

manish@chauthiduniya.com

इस्लाम न्याय और समानता के ख़िलाफ़ नहीं : परवीन अबीदी

ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमडब्लूपीएलबी) की स्थापना 2005 में की गई थी. ऐसा माना जाता है कि इस संस्था का गठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महिला विरोधी रुख़ और इस्लाम की आधारहीन पितृसत्तात्मक व्याख्या की प्रतिक्रिया में किया गया. लखनऊ निवासिनी परवीन अबीदी इस बोर्ड की अध्यक्ष हैं. एआईएमडब्लूपीएलबी भले ही बहुत ज़्यादा सुर्ख़ियों में न आया हो या इसकी उपलब्धियां साधारण हों, लेकिन इसकी स्थापना से ही भारतीय मुस्लिम महिलाओं के एक स्वायत्त आंदोलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें इस्लामिक दलील का ही सहारा लेकर लिंग आधारित न्याय (लैंगिक भेदभाव के ख़िलाफ़) की बात की जा रही है. ज़ाहिर है, एआईएमडब्लूपीएलबी की दलीलें मौलवियों के बेबुनियाद दावों की मुख़ालफ़त करती हैं. चौथी दुनिया के लिए **योगिंदर सिकंद** *ने परवीन अबीदी से बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:*

आख़िर ऐसी क्या वजह थी, जिसने आपको एआईएमडब्लूपीएलबी की स्थापना के लिए प्रेरित किया. निश्चित तौर पर यह एक ऐसा निर्णय था, जिसका बहुत से मौलवियों एवं अन्य मुस्लिम पुरुषों ने मज़ाक बनाया था?

जिन महिलाओं ने एआईएमडब्लूपीएलबी की स्थापना की, वे सभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये से परेशान थीं. वे इस बात से हैरान थीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने भी मौलवी थे, उनमें से ज़्यादातर ने लिंग आधारित न्याय की जोरदार मुख़ालफ़त की थी और यहां तक कि इस्लाम में जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, उनका भी विरोध किया. हमने महसूस किया कि मुस्लिम महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख़ हानि पहुंचाने वाला ही रहा. बावजूद इसके हम जैसी महिलाओं के पास, जो सीधे-सीधे ऐसी बातों से प्रभावित थीं, ऐसा कोई मंच या फोरम नहीं था, जहां हम अपनी बात रख सकें. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी दबी-कुचली मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर आंख बंद किए हुए है. बोर्ड ने शरिया की व्याख्या ग़लत ढंग से की है. इसमें पुरुष को विशेषाधिकार और महिलाओं को नीचे रखा गया. बोर्ड में कुछ महिलाएं हैं, लेकिन सिर्फ़ चेहरा दिखाने के लिए. उनकी आवाज़ को कोई महत्व नहीं मिलता. ये महिलाएं मौलवियों की राय के ख़िलाफ़ तक नहीं बोल सकतीं. कुछ ऐसी ही वजहें रहीं, जिनके चलते हमने एक अलग बोर्ड यानी एआईएमडब्लूपीएलबी के बारे में सोचा, जहां हम मुस्लिम औरतें अपनी बात रख सकें, अपना प्रतिनिधित्व दे सकें. जनवरी 2005 में लखनऊ में हमारे घर में शादी थी, जहां भारत के अलग-अलग हिस्सों से महिलाओं का एक समूह वहां पहुंचा था. इन्हीं महिलाओं को लेकर हम लोगों ने एआईएमडब्लूपीएलबी की स्थापना की. हम में से कुछ महिलाओं के पति और कुछ अन्य पुरुष उस नाम से ख़ुश नहीं थे, जो नाम हमने अपनी संस्था को दिया था. वे सोच रहे थे कि हम लोग उन लोगों को जानबूझ कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवियों की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं. फिर भी हमने उसी नाम को रखने का फ़ैसला किया.

लेकिन मौलवियों के बारे में इस तरह की आम धारणा बनाई जाए, इसे आप ठीक समझती हैं? निश्चित तौर पर इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो सचमुच महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो.

सही कहा आपने. कोई किसी व्यक्ति के समूह के बारे में आम धारणा नहीं बना सकता. हमारी संस्था में महिला उलेमा हैं, जिन्होंने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पाई है. उनमें से एक लखनऊ की नदवात-उल-उलेमा (बालिका शाखा) से ग्रेजुएट हैं. एक और शिया महिला हैं, जो विद्वान हैं. हमारी संस्था का दरवाज़ा सबके लिए खुला है. इसमें शिया और सुन्नी सदस्य भी हैं. शियाओं में इमामी, बोहरा और यहां तक कि खोजा भी हैं. सुन्नी सदस्यों में से कुछ बरेली परिवार से हैं, कुछ देवबंदी भी हैं. हम हिंदू या अन्य पृष्ठभूमि से आने वाली महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी काम करते हैं.

एआईएमडब्लूपीएलबी किस तरह के कार्यों से जुड़ा है?

सामान्यत: हमारा काम अनौपचारिक है. वास्तव में यह भारत के विभिन्न भागों की मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं का एक खुला हुआ नेटवर्क है. निकाहनामा, अब तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है. इसे हमने तैयार किया था. निकाहनामा में मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है. ख़ासकर, तलाक और बहु-विवाह के संबंध में. हमारी संस्था के सदस्य मुस्लिम इलाक़ों में ग़रीब मुस्लिम महिलाओं को क़ानून के बारे में जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं. हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पति आपको मारते हैं तो इसे मत सहन करो. यह सोचना कि पति कुछ भी कर सकता है और यह अल्लाह की मर्ज़ी है, ग़लत है. हम उनसे कहते हैं कि अगर आपके पति अपनी इच्छा से तलाक देते हैं तो यह इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है. चाहे मुल्ला कितना भी शोरशराबा क्यों न मचा ले. हम उन्हें बताते हैं कि कोई आदमी अगर अपने बच्चों या बीवी की देखभाल नहीं करता है तो यह ग़ैर इस्लामिक है. और, इस तरह से ग्रास रूट से जुड़ी महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है. हालांकि अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. हम मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ और समस्याओं, विवादित फतवों, मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दों पर आए निर्णय, जो सीधे-सीधे मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित करते हैं, पर भी अपनी बात रखते हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो रूढ़िवादी मौलवी इसी तरह इस्लाम की ग़लत व्याख्या करते रहेंगे, ताकि मुस्लिम महिलाओं को दबाकर रखा जा सके. इनका ज़्यादातर दिखावा पाखंड है और ख़ुद के हित के लिए है. उदाहरण के लिए, मुहम्मद अली जिन्ना की पत्नी फातिमा जिन्ना ने जब पाकिस्तान में चुनाव लड़ा तो जमात-ए-इस्लामी ने उनका समर्थन किया, लेकिन अब भारत में कुछ मुल्लाओं ने फतवा जारी किया कि मुस्लिम महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकतीं. कोई भी आदमी इस तरह के ऊलजलूल फतवों के बारे में बता सकता है. मुख्य मुद्दा यह है कि मौलवी आमतौर पर महिलाओं को अपने अधीन बनाए रखना चाहते हैं. और, जब यही महिलाएं जागरूक हो रही हैं तो मौलवियों को यह डर सता रहा है कि अब वे किस पर अपना हुक्म चलाएंगे.

लेकिन मैं अपनी पिछली बात दोहराऊं तो, निश्चित तौर पर सभी मौलवी इस मामले में एक समान नहीं हैं?

नहीं, मेरा मतलब वह सलाह देना नहीं है. लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अधिकांश लोग इस बात से ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं. मैं इस मामले में एक अपवाद बता सकती हूं. मौलाना कल्बे सादिक़ लखनऊ के मशहूर शिया विद्वान हैं. उन्होंने हमारे काम को तहे दिल से और बदस्तूर सहयोग दिया है. लेकिन, साथ ही मैं उन मुल्लाओं को भी जानती हूं, जिन्होंने हमारी आलोचना पथभ्रष्ट के तौर पर की. उन्होंने हम पर यह भी आरोप लगाया कि हम भूली-भटकी महिलाओं का नेतृत्व करना चाहते हैं. हमारे कार्यकर्ता झुग्गी-झोपड़ियों में मुस्लिम महिलाओं से मिलते हैं. उन महिलाओं से, जिनका जीवन बस बच्चे पैदा करने और उनके पालन पोषण में गुज़रता है. दरअसल, हम उन्हें यह बताते हैं कि इस्लाम एक ख़ास तरह के परिवार नियोजन की इजाज़त देता है, लेकिन मुल्ला तुरंत हमारा प्रचार इस्लाम के दुश्मन के एजेंट के तौर पर करने लगते हैं. हमारी विचारधारा को वे सरकारी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा बताने लगते हैं. हमारे कुछ विरोधी तो हमारी तुलना बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन से करने लगते हैं. वे हमारे डराने लगते हैं कि हमारा भी वही हाल होगा, जो उनका हुआ.

एआईएमपीएलबी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे पर्सनल लॉ संबंधी विवाद शरिया कोर्ट में निपटाएं. इसीलिए वह दावा करता है कि उसने इस कोर्ट को पूरे देश में गठित किया है. इस सलाह पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए. हमें राज्य न्याय पालिका का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दारूल-कज़ास में महिलाएं उन्हीं फ़ैसलों को मानने के लिए मजबूर होती हैं, जो उनके ख़िलाफ़ होते हैं. इसकी वजह यह है कि जो लोग और मदरसों के मौलवी महिलाओं की मदद करते हैं, वे ख़ुद पुरुष प्रधान समाज के कट्टर समर्थक हैं.

लेकिन मौलवियों को इस्लाम का अधिकृत प्रवक्ता माना जाता है या वे ऐसा दावा करते हैं, क्या ऐसा नहीं है?

एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं उनके दावों को मानने से इंकार करती हूं. फतवा और उनके कई लेखों के ज़रिए कोई भी अपना प्रभाव जमा सकता है कि इस्लाम महिलाओं को चुप रहने या पुरुषों की बात मानने की सीख देता है. लेकिन, मैं नहीं मानती कि यह इस्लाम का स्वरूप है. जैसा कि मैं मानती हूं, इस्लाम न्याय और महिलाओं की समानता के रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाता है. जबकि अधिकतर मौलवी ठीक इसके विपरीत बात कहते हैं. इस्लाम घृणा और दुश्मनी का संदेश नहीं देता है. जबकि अतिवादी इस्लामिक, तालिबान और ओसामा बिन लादेन जैसे लोग ठीक इसके विपरीत सोचते हैं. जहां तक मेरा सवाल है, यदि कुछ मुल्ला इस्लाम की व्याख्या इस तरह से करें, जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता हो तो मैं उनकी इस्लाम की उस व्याख्या को कतई मानने को तैयार नहीं हूं. यह बिल्कुल ही सरल बात है. महिलाओं से नफ़रत करने वाली इस्लाम की उनकी व्याख्या को चुनौती देने और उसका विरोध करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम की सही जानकारी हो और वह स्वयं इस्लाम की व्याख्या करें. यह भी ज़रूरी है कि वे ख़ुद अपने लिए आवाज़ बुलंद करें. मौलवियों द्वारा अब तक की गई इस्लाम की व्याख्या कतई इस्लामिक नहीं है.

(योगिंदर सिकंद नेशनल लॉ स्कूल बंगलुरू से जुड़े हैं)

मोरारका फाउंडेशन के इस अभिनव प्रयास ने शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक सुंदरता को विश्व पटल पर ख्याति दिलाने में सफलता पाई है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 1 मार्च–7 मार्च 2010

शेखावाटी उत्सव 2010

मोरारका की हवेली

राजस्थान के अर्द्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र का भू-भाग शेखावाटी. ह इलाका सेठों की जन्मस्थली और वीरों की कर्मभूमि रहा है. रेतीले धारों के बीच यहां की हवेलियां और उन पर बने भित्ति चित्रों की भव्यता बेमिसाल है. इस क्षेत्र की प्रचलित लोक कलाएं, हस्तशिल्प और जीवनशैली पूरे देश में अपनी अमिट छाप रखती हैं. शेखावाटी की इसी कला, संस्कृति एवं परंपरा को पोषित और मशहूर करने के मक़सद से मोरारका फाउंडेशन पिछले पंद्रह वर्षों से शेखावाटी उत्सव का आयोजन करता आ रहा है. मोरारका फाउंडेशन के इस अभिनव प्रयास ने शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक सुंदरता को विश्व पटल पर ख्याति दिलाने में सफलता पाई है. इस साल भी यह उत्सव नवलगढ़ के सूर्यमंडल स्टेडियम में 12 से 14 फरवरी को आयोजित हुआ, जिसमें विविध सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों का अद्धितीय संगम देखने को मिला. गणमान्य अतिथियों और हज़ारों देशी-विदेशी दर्शकों की मौज़ूदगी में जैसलमेर के प्रसिद्ध कलाकारों द्धारा पेश सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिताएं, शेखावाटी की मशहूर हवेलियां, भित्ति चित्रों, कुएं, बावड़ी और ग्रामीण परिवेश की फोटो प्रदर्शनी के आयोजनों ने सभी का मन मोह लिया. ख़ासकर ऑर्गेनिक फूड बाज़ार ने लोगों को बेहद आकर्षित किया. मोरारका फाउंडेशन द्धारा संचालित ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्यक्रम के तहत बिना ज़हर और रसायनों के पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को मेले में आए लोगों ने ख़ूब सराहा. विशेषकर किसानों ने इसका लाभ उठाया. अगर यह कहा जाए कि शेखावाटी उत्सव ने आज इस क्षेत्र की सूरत बदल दी है तो ग़लत नहीं होगा. आज से दस साल पहले यहां की तमाम हवेलियों में ताला जड़ा रहता था. इनका संरक्षण करने की गरज से मोरारका फाउंडेशन ने मोरारका हवेली के माध्यम से इनका बचाव शुरू किया. इसे देख दूसरे उद्योगपतियों ने भी अपनी-अपनी हवेलियों के संरक्षण का सिलसिला शुरू कर दिया. कभी वीरानी में गुम ये हवेलियां आज शेखावाटी उत्सव की वज़ह से गुलज़ार हो चुकी हैं. इनकी ख़ूबसूरती को निहारने के लिए सालों भर देशी-विदेशी पर्यटकों का हुज़ूम उमड़ता है. शेखावाटी में ग्रामीण पर्यटन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है. विदेशी आते हैं, किसानों के साथ घरों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं और भारत की ख़ूबसूरत तस्वीर लेकर वापस लौट जाते हैं. यक़ीनन शेखावाटी उत्सव ने इस क्षेत्र को नई पहचान और नया आयाम दिया है.

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

विजय कलंत्री, किशोर रूंगटा, कमल मोरारका, पराग मेहता

(पीछे) महेश सहगल, अजय मोदी, जयंत गांधी. (आगे) शकुंतला गांधी, सुनीता सेक्सरिया, भारती मोरारका.

मोरारका फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश गुप्ता विजेताओं को सम्मानित करते हुए

महेश सहगल नृत्य करते हुए

समारोह के उद्घाटनकर्ता चिकित्सा राज्यमंत्री राजकुमार शर्मा कमल मोरारका के साथ

रमेश सेक्सरिया, डॉ. अशोक अवस्थी, कमल मोरारका, कैलाश चोटिया, संतोष भारतीय

केंद्रीय राज्य मंत्री महादेव सिंह खंडेला और अमेरिका की वनसई कंपनी के निदेशक श्री सैम्युअल

समारोह के समापनकर्ता राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को तिलक लगाती फाउंडेशन की कार्यकर्ता.

भारत में बाघों को बचाने के लिए 17 प्रदेशों में 23 संरक्षित क्षेत्र बनाए गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 1411 बाघ होने का दावा किया गया है.

जनसंघर्ष मोर्चा देगा राजनीतिक विकल्प

जनसंघर्ष मोर्चा देश की लोकतांत्रिक और बदलाव चाहने वाली ताक़तों का राष्ट्रीय मंच है. इसमें समाजवादी, दलित, आदिवासी–वनवासी और वामपंथी आंदोलन से जुड़ी ताक़तें शामिल हैं. इसका सबसे प्रमुख आंदोलन है, दाम बांधो–काम दो अभियान. राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह पिछले दिनों दिल्ली में थे. *चौथी दुनिया* ने उनसे जनसंघर्ष मोर्चा के एजेंडे, आंदोलन, स्वरूप और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश :

आपने कई सालों तक वामपंथ की राजनीति की है. फिर अलग से जनसंघर्ष मोर्चा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई?

हिंसक रास्ता अपना कर व्यवस्था बदलने में मेरा विश्वास नहीं है. और, यह संभव भी नहीं है. मैं चाहता हूं कि एक मज़बूत जनतांत्रिक आंदोलन खड़ा किया जाए. इसी के ज़रिए मुख्यधारा की राजनीति में हस्तक्षेप भी हमारा लक्ष्य है. रोज़गार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है. जनसंघर्ष मोर्चा इन्हीं जन समस्याओं पर एक जनतांत्रिक आंदोलन खड़ा करेगा.

आज देश में महंगाई, रोज़गार के साथ जंगल और ज़मीन का मुद्दा आम आदमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है. जनसंघर्ष मोर्चा इन समस्याओं को किस रूप में देखता है?

अगर सरकार नरेगा को ईमानदारी से लागू कराती तो लोगों को साल में महज़ सात आठ दिनों का ही रोज़गार नहीं मिलता. वनवासियों–आदिवासियों के लिए भी जो क़ानून बनाया गया था, उसे भी लागू कराने को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है. उत्तर प्रदेश की हालत और ख़राब है. वहां मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद और चित्रकूट में आदिवासियों की कोल एवं पनिका जाति के लोगों की संख्या अच्छी–खासी है, लेकिन 60 सालों बाद भी उन्हें आदिवासी (एसटी) का दर्ज़ा नहीं मिला है. कुल मिलाकर सामाजिक न्याय का मुद्दा अब तक पूरा नहीं हुआ है. इन्हीं सवालों को लेकर पिछले साल अक्टूबर में हमने दिल्ली में एक रैली की थी. हमारे समर्थन में कुलदीप नैय्यर, राजेंद्र सच्चर जैसे लोग आए. हमने दाम बांधो–काम दो अभियान की शुरुआत की. केंद्र सरकार को इससे अवगत भी कराया, लेकिन अब तक इस पर कोई क़दम नहीं उठाया गया है.

> **जनता के गुस्से को अगर एक लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जाए तो एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का निर्माण हो सकता है, जो वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और भाजपा का राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है.**

आख़िर इन सबकी आप क्या वजह मानते हैं, सरकार ऐसी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं देती?

भारतीय राजनीति आज कांग्रेस और भाजपा के इर्द–गिर्द केंद्रित होती जा रही है. जो अन्य वामपंथी–जनवादी ताक़तें हैं, उनकी तरफ़ से जनता के लिए किसी ठोस और अर्थपूर्ण अभियान का अभाव दिखता है. हमारी कोशिश है कि ऐसी वामपंथी–जनवादी ताक़तें एक मंच पर आएं, ताकि हम न सिर्फ़ एक सशक्त जनांदोलन खड़ा कर सकें, बल्कि एक मज़बूत राजनीतिक विकल्प भी बन सकें. हम लोग बिहार में राष्ट्रीय समता पार्टी, झारखंड में झारखंड पीपुल्स फ्रंट, उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवर्तन दल, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हमने सीपीएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा.

अखिलेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय संयोजक, जनसंघर्ष मोर्चा.

देश भर में कई छोटे–मोटे आंदोलन चल रहे हैं. आख़िर ऐसे आंदोलन राजनीतिक विकल्प क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं?

ऐसे आंदोलनों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उनमें राजनीतिक पहलू का अभाव. ऐसे आंदोलन ग़ैर राजनीतिक या अर्द्ध राजनीतिक भूमिका में हैं. मुख्यधारा की राजनीति में एक राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश नहीं दिखती इन आंदोलनों में.

आप राजनीतिक विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे का विकल्प तो कई बार आजमाया जा चुका है और उसके मिले–जुले परिणाम देखने को मिले हैं.

अब तक तीसरा मोर्चा बनाने की जो कोशिश हुई है, वह जैसे–तैसे हुई है. वे कोशिशें कार्यक्रम आधारित नहीं थीं. हालांकि उत्तर प्रदेश में वी पी सिंह की अगुवाई में बने जनमोर्चा ने लोगों में विश्वास जगाया था कि यह सपा, बसपा और कांग्रेस से अलग होगा. तीसरे मोर्चे का प्रयोग इसलिए भी असफल हुआ, क्योंकि इसके घटक दल नीतियों के आधार पर कांग्रेस या भाजपा से अलग नहीं थे. आज हालात थोड़े बदल चुके हैं. यूपी में मुलायम सिंह और बिहार में लालू यादव अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं. कांग्रेस इसका विकल्प बनने की कोशिश कर रही है. यहां अगर हम एक लोकतांत्रिक विकल्प खड़ा करें तो लोग समर्थन देंगे.

आज की राजनीति की जो दशा, दिशा और चरित्र है, उसमें बिना धनबल और बाहुबल के राजनीति की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है.

यह राजनीति की पूरी सच्चाई नहीं है. दरअसल, जनता के लिए सटीक राजनीतिक एजेंडा हो तो जनता ख़ुद धन–बल निर्मित कर सकती है. और, जो जन बल होता है, वह धन बल और माफ़िया पर भारी पड़ता है. हमने अपने छात्र जीवन में ऐसा होते हुए देखा है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन का मैं प्रेसीडेंट बना, बिना किसी राजनीतिक समर्थन के. आम छात्रों ने हमें सपोर्ट किया.

आज देश का बहुत बड़ा हिस्सा नक्सल समस्या की गिरफ़्त में है. बड़ी संख्या में युवा माओवाद की राह पर जा चुके हैं. जनसंघर्ष मोर्चा में इन जैसे लोगों की क्या भूमिका आप देखते हैं?

देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं चंदौली में अब माओवाद की चर्चा नहीं होती. मैं इन इलाक़ों में सरकारी दमन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ. दूसरी तरफ़ हमने माओवादी राजनीति को अराजक नीति कहकर विरोध किया. आदिवासियों–वनवासियों को समझाया कि हथियार उठाने से न व्यवस्था बदलेगी और न ही आपको आपके अधिकार मिलेंगे. इन ज़िलों से माओवाद सरकारी दमन की वजह से नहीं हटा, बल्कि हमारे सशक्त लोकतांत्रिक आंदोलन की वजह से नक्सली युवा हमसे जुड़े.

भारतीय राजनीति में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प खड़ा करने में मध्य वर्ग, शहरी वर्ग और युवाओं की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? ख़ासकर आप अपने मोर्चे के लिए इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?

पिछले 20 सालों से देश में रोज़गार की हालत ख़राब है. आज राहुल गांधी देश के यूथ आइकॉन बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वह रोज़गार का अधिकार क़ानून लागू करा सकते हैं? शहरों में काम करने वाले युवाओं को कम से कम वेतन दिया जा रहा है. इस मुद्दे को कौन उठाएगा? जनता के गुस्से को अगर एक लोकतांत्रिक स्वरूप दिया जाए तो एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का निर्माण हो सकता है, जो वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस और भाजपा का एक राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है. हम ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

बाघों की जान ख़तरे में

राष्ट्रीय पशु बाघ का जीवन तस्करों की गतिविधियों के चलते संकट में है. हालांकि 2010 को टाइगर वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन एक माह के भीतर चार बाघों की मौत राज्य सरकार की उदासीनता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है.

राजकुमार शर्मा

एक माह के भीतर चार बाघों की मौत ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव सुरक्षित नहीं हैं. उक्त घटनाएं नैनीताल के रामनगर स्थित कार्बेट नेशनल रिज़र्व टाइगर पार्क में घटीं. एक तरफ़ केंद्र सरकार 2010 को बाघ वर्ष (टाइगर इयर) के रूप में मनाने का मन बना रही है, दूसरी ओर नया साल होते ही चार बाघों की मौत ने राज्य सरकार की नाकामी साबित करने के साथ ही केंद्र सरकार की योजना पर पानी फेर दिया है. देवभूमि के पर्यावरणविदों एवं वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि इसका प्रमुख कारण अट्टालिकाओं की चौहद्दी मांद के मुंह तक पहुंचना है.

विगत वर्ष भी नौ बाघों की असामयिक मौत हुई थी. इस पर केंद्र सरकार ने बाघों को बचाने के लिए गंभीर पहल की और वर्ष 2010 को टाइगर इयर ही घोषित कर दिया. सरकार की पहल को चुनौती की तरह लेते हुए वन्यजीवों के दुश्मनों ने वर्ष की शुरुआत में ही चार बाघों को मौत के घाट उतार दिया. पहली घटना 13 दिसंबर को हुई, दूसरी 16 दिसंबर, तीसरी पांच जनवरी और चौथी 11 जनवरी को हुई. चार बाघों की मौत ने जनमानस को हिलाकर रख दिया. पांच जनवरी को हुई घटना में बाघ की मौत को कार्बेट पार्क प्रशासन नेचुरल डेथ बताकर ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा है. 11 जनवरी को हुई चौथी घटना प्रशासन के गले की हड्डी बन गई है. प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि इस बाघ को शिकारियों ने साजिश करके मौत के घाट उतारा. पहले जिस गाय को उसके सामने परोसा गया, उसे ज़हर का इंजेक्शन दिया गया. उसका शिकार करते ही बाघ मौत के मुंह में समा गया. मृत बाघ के शरीर पर कहीं भी किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए. पार्क प्रशासन के निदेशक की मौजूदगी में बाघ के शव का परीक्षण कराया गया और उसके बिसरे को प्रिज़र्व करके मौत के कारणों की जांच के लिए भेजा गया. निदेशक रंजन मिश्र ख़ुद को पार्क का चौकीदार बताते हुए बाघ की मौत को अपनी असफलता मानते हैं. टाइगर कंसरवेशन अथार्टी के सचिव डॉ. राजेश गोपाल ने भी टीम सहित घटनास्थल का निरीक्षण किया. इलाक़े के जानकारों का कहना है कि वन प्रशासन की मिलीभगत से विषधारी पशुओं को शिकार के रूप में परोस कर बाघों को मार दिया जाता है. फिर वन्य जीव तस्कर अपने प्रभाव से रिपोर्ट बदलवा कर बाघों की मौत को प्राकृतिक सिद्ध कर देते हैं.

पत्रकार श्यामलाल एवं चंचल गोला का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीवों के लिए बनाए गए प्राणी उद्यान एवं अभयारण्य मात्र दिखावा सिद्ध हो रहे हैं. बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में चल रहा प्रोजेक्ट टाइगर असफलता का पर्याय बन गया है. जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पांच वर्ष में ही 155 के क़रीब रही बाघों की संख्या अब 100 के आसपास सिमट चुकी है. भ्रष्टाचार के कारण तस्करों को वनों, उद्यानों एवं पार्कों में प्रवेश मिल जाता है. उत्तराखंड में शिकार करने वाले तस्कर मारे गए बाघों के अंग चीन एवं ताइवान जैसे देशों को ऊंचे दामों में बेच देते हैं, जिनका इस्तेमाल दक्षिण एशिया के अनेक देश बलवर्द्धक एवं कामोत्तेजक औषधियों के निर्माण में करते हैं.

> **कार्बेट टाइगर रिज़र्व के आसपास कुल 77 होटल एवं रिज़ॉर्ट हैं, जिनमें कुल 3197 आवासीय कमरे हैं. डेढ़ दर्ज़न अभी निर्माणाधीन हैं, जिनका क्षेत्रफल एक से सत्रह एकड़ तक है. जबकि कार्बेट नेशनल पार्क में एक दिन में सिर्फ़ 600 पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति है. बाक़ी 2600 कमरों में क्या होता है? यह एक विचारणीय सवाल है.**

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि इस नेशनल कार्बेट टाइगर रिज़र्व के आसपास कुल 77 होटल एवं रिज़ॉर्ट हैं, जिनमें कुल 3197 आवासीय कमरे हैं. डेढ़ दर्ज़न अभी निर्माणाधीन हैं, जिनका क्षेत्रफल एक से सत्रह एकड़ तक है. जबकि कार्बेट नेशनल पार्क में एक दिन में सिर्फ़ 600 पर्यटकों के प्रवेश की अनुमति है. बाक़ी 2600 कमरों में क्या होता है? यह एक विचारणीय सवाल है. इन कमरों में मनोरंजन से लेकर शादी, पार्टी, डिस्को और अन्य कई तरह के मनोरंजन से जुड़े खेल खेले जाते हैं, जिसमें जायज़ एवं नाजायज़ कृत्य भी शामिल हैं. पर्यटन सचिव सुजित बनर्जी को हैरानी इस बात से है कि सरकार की ग़लत नीतियों के चलते ही यह सब हो रहा है. बनर्जी का मानना है कि इन ग़ैर क़ानूनी होटलों के चलते राष्ट्रीय उद्यान के बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. पार्क के आसपास स्थित सभी होटल कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से बने हुए हैं, जिनकी अवांछनीय हरक़तों के चलते वन्यजीवों पर आफ़त आ गई है. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पत्र लिखकर इस गंभीर संकट की ओर उत्तराखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है. इसके बावजूद राज्य सरकार के कानों में जूं न रेंगना चिंता का विषय बना हुआ है. वन्यजीवों से जुड़े नेशनल पार्क के पास किसी भी तरह के निर्माण से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति अवश्य लेनी चाहिए. इन पार्कों के पास इस तरह के अवैध निर्माण रोकना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. केंद्र सरकार राज्य सरकार के असहयोगात्मक रवैये के चलते इसे मुश्किल कार्य मानती है. इसके लिए अब वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय को संयुक्त रूप से ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश कहा है कि बाघों को बचाने के लिए सरकार गंभीर पहल करेगी. अब बाघों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ी जा सकती.

भारत में बाघों को बचाने के लिए 17 प्रदेशों में 23 संरक्षित क्षेत्र बनाए गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 1411 बाघ होने का दावा किया गया था. 1973 में इन बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया. तब बाघों की संख्या लगभग दो हज़ार थी. 2002 में यह संख्या बढ़कर 3622 तक पहुंच गई. आज़ादी के बाद वन्यजीवों को बचाने एवं बढ़ाने का सबसे सार्थक प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने किया. इन दोनों नेताओं के असामयिक निधन के बाद पूरे देश में वन एवं वन्यजीवों, ख़ासकर बाघों पर आफत आ गई. वैसे तो भारत सहित विश्व के एक दर्ज़न देशों में बाघ सुरक्षित नहीं हैं. भारत में वन्यजीवों से जुड़ी संस्था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता वी एस चतुर्वेदी बाघों की निर्मम हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु बाघ की हत्या करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया चाहिए.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार फिर भारत की शान बाघ को बचाना चाहते हैं. उन्होंने एक ईमानदार कोशिश के तहत वर्ष 2010 को टाइगर वर्ष घोषित किया है. लेकिन, देवभूमि में चार सप्ताह के अंदर चार बाघों की मौत ने प्रधानमंत्री की उस ईमानदार कोशिश पर ग्रहण लगाने का काम किया है. जंगलों में पूरी तरह जंगलराज क़ायम है. वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव–जंतु संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जमकर अनदेखी की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

जरा संभल कर होली मनाएं

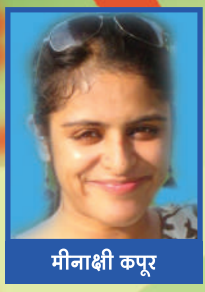

मीनाक्षी कपूर

यह साल का वह समय है, जबकि लोग होली की तैयारियों में व्यस्त हैं. कुछ लोग इस त्योहार के लिए विभिन्न प्रकार के रंग एकत्र करने में लगे हैं तो कई लोग रंगों से बचने के लिए शहर से दूर जाने की योजना बना रहे हैं. कुछ लोग तो अपने घरों के अंदर ही कैद रहकर रंगों से बचने की सोच रहे हैं. हालांकि, सच यह है कि लोग रंगों से उतना नहीं डरते, जितना रंग के नाम पर चेहरे पर लगाई जाने वाली ख़तरनाक चीज़ों से, जिनका होली के मौक़े पर इस्तेमाल किया जाता है और कई बार नुक़सानदायक साबित होता है.

हम यदि अपने आसपास देखें तो यह समझते देर नहीं लगती कि यह साल का वह समय होता है, जब रंगीनियां अपने शबाब पर होती हैं. पतझड़ के बाद पेड़-पौधे नए फूल-पत्तों से लदे होते हैं. ठंड के कुहासे की जगह साफ़ आसमान से सूरज की किरणों की लालिमा देखने लायक़ होती है. ठंडी और हाड़ कंपा देने वाली हवा की जगह वसंती हवा हमारा मन मोह लेती है. कुल मिलाकर पूरा वातावरण ख़ुशगवार लगता है. यह वसंत का महीना है. ठंड की विदाई के बाद गर्मियों की आमद और उसकी तैयारी का समय.

इस नज़रिए से देखें तो होली का त्योहार प्रकृति के पटल पर विविध रंगों के फूलों की आमद से पूरी तरह मेल खाता है. यह प्रकृति की रंग-बिरंगी ख़ूबसूरती को हमारे जीवन में परिलक्षित करता है. ऐसा लगता है, जैसे हमारे पूर्वज वसंत की प्राकृतिक ख़ूबसूरती से इतने प्रभावित हो गए कि उसे उन्होंने होली के रूप में अपने जीवन में उतार लिया. लेकिन उन दिनों होली में उन रंगों का इस्तेमाल होता था, जो इस मौसम में खिलने वाले फूलों से बने होते थे. इन रंगों से नुक़सान की बात तो दूर, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिहाज़ से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते थे. इनमें मौजूद गुण त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद होते थे.

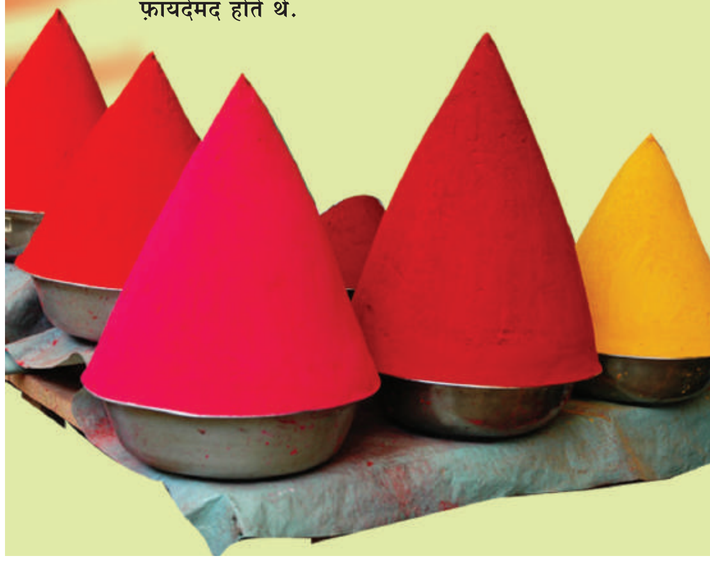

लेकिन समय के साथ प्राकृतिक रंगों की जगह कृत्रिम डाई ने ले ली है. आजकल बाज़ारों में ऐसे रंगों की भरमार नज़र आती है, जो आंखों को तो सुहावने दिखते हैं, लेकिन ख़ासा नुक़सान पहुंचा सकते हैं. रंगों के तीन अलग-अलग रूप बाज़ारों में मिलते हैं सूखे, पानी मिले और पेस्ट. इन सभी में एक कलरेंट होता है, जिसे किसी आधारभूत तत्व (बेस मैटीरियल) के साथ मिलाया जाता है. कलरेंट में तांबा, सीसा, पारा और एल्युमिनियम जैसे कई रासायनिक तत्व मिले होते हैं, जो हमारी त्वचा के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं. इनके इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां जैसे त्वचा में ख़ुरदरापन, खुजलाहट और श्वास संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

इतना ही नहीं, इन रासायनिक तत्वों को जिस आधारभूत तत्व (बेस मैटीरियल) में मिलाया जाता है, वे भी सुरक्षित नहीं होते. अधिकांश पाउडर या सूखे रंगों में आधारभूत तत्व के रूप में एस्बेस्टस, चॉक पाउडर या सिलिका का उपयोग होता है. हम सभी जानते हैं कि एस्बेस्टस मानव शरीर में कैंसर का कारण होता है. शरीर में जमा इसकी छोटी मात्रा भी कैंसर के विकास का कारण बन सकती है. सिलिका त्वचा को शुष्क और कमज़ोर बनाता है. रंगों में दिखने वाली चमक की वजह इसमें मिला हुआ शीशे का चूर्ण या माइका होता है. कई वाटर कलर्स में मिले आधारभूत तत्व अल्कलाइन या क्षारीय होते हैं, जो वास्तव में ख़तरनाक होते हैं. यदि यह आंखों में प्रवेश कर जाएं तो नज़र संबंधी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. पेस्ट के रूप में तैयार किए गए रंगों में कई बार इंजन ऑयल या अन्य घटिया क्वॉलिटी के तैलीय पदार्थों के साथ विषाक्त यौगिक मिले होते हैं, जिनसे एलर्जी या तात्कालिक अंधेपन जैसी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

(स्रोत: टॉक्सिक लिंक्स एंड वातावरण)

केवल रंग ही नहीं, आजकल होली खेलने का तरीक़ा भी असुरक्षित हो चुका है. रंग भरे गुब्बारे और अंडे फेंकने का चलन काफ़ी आम है, जो आंखों और कानों के लिए नुक़सानदायक हो सकता है. होली के दौरान छेड़खानी और अन्य असामाजिक गतिविधियां भी काफ़ी आम हो चुकी हैं. एक समय था, जब होलिका दहन में आसपास के सभी लोग एक साथ जमा होते थे, लेकिन आधुनिक दौर में यह एक व्यक्तिगत जलसे में तब्दील होता जा रहा है. इन सब चीज़ों से न केवल स्वास्थ्य और सुंदरता पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि वातावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है. सफाई के बाद रंग और गुब्बारों के टुकड़े हमारे जल स्रोतों में प्रवेश कर उसे प्रदूषित और विषाक्त बनाते हैं. जबकि जगह-जगह होलिका दहन के आयोजन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है.

होली ऐसा त्योहार है, जो लोगों को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है. किसी भी इंसान के चेहरे पर रंग लगाने से उसकी सभी व्यक्तिगत पहचान जैसे धर्म, जाति, सामाजिक हैसियत आदि गौण होकर रह जाते हैं. वह तो केवल प्यार और आत्मीयता के रंग में रंगा होता है. ऐसी सभी सीमाएं, जो उसे दूसरे इंसान से अलग करती हैं, गुम हो जाती हैं. इन सीमाओं से दूर हर कोई एक जैसा ही दिखता है. एकता की यह भावना सारी दूरियां ख़त्म कर देती है और प्रकृति की ख़ूबसूरती का आनंद लेने के लिए सभी एक साथ होते हैं. लेकिन हालत यह है कि आजकल अधिकतर लोग रंगों के इस त्योहार से अलग रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं. ऐसे लोगों को दोबारा होली के साथ जोड़ने की ज़रूरत है. इसके लिए आवश्यक है कि हम होली के प्राकृतिक स्वरूप को अपनाएं, जिससे लोग डरें नहीं. हमें ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो ख़ुद हमारे और वातावरण के लिए सुरक्षित हों. ऐसे रंग हम अपने घरों में भी आसानी से बना सकते हैं. आइए, जानते हैं इसके कुछ तरीक़ों के बारे में :

हरा

- सूखा हरा रंग तैयार करने के लिए हिना या मेहंदी में आटा मिलाएं. ध्यान रहे कि इसे धोने के लिए पानी का इस्तेमाल न करें. इसके लिए ब्रश का उपयोग करें.
- गुलमोहर के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बनाने से भी हरा रंग तैयार होता है.
- पालक के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे पानी में मिलाने से गीला हरा रंग तैयार किया जा सकता है.

लाल

- लाल चाइना रोज फ्लावर को सुखाकर उसका चूरा तैयार करें और उसे आटे में मिलाने से सूखा लाल रंग बनता है.
- लाल चंदन को भी सूखे लाल रंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
- रतन ज्योत को पहले पानी में उबालें. फिर उसे ठंडा कर उसमें पानी मिलाने से गीला लाल रंग तैयार होता है.
- अनार के छिलके को पानी के साथ उबाल कर उसे लाल रंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
- जब हल्दी के ऊपर नींबू का रस गिराया जाता है तो वह लाल हो जाता है. इसे पानी के साथ मिलाकर गीले लाल रंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है.
- टमाटर या गाजर के पेस्ट को पानी के साथ मिलाकर भी लाल रंग तैयार किया जा सकता है.

पीला

- हल्दी पाउडर में बेसन मिलाने से सूखा पीला रंग बनता है.
- अमलतास के फूलों को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बनाएं. फिर उसमें बेसन या आटा मिलाकर उसे पीले रंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.
- बेल के ऊपरी छिलके को सुखाकर उसका चूरा बनाएं. इससे पीले रंग का पाउडर तैयार होता है.
- गीले पीले रंग के लिए अमलतास के फूलों को पानी में डालकर उबालें और उसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें. सुबह तक रंग तैयार हो जाएगा.
- हल्दी को पानी में मिलाकर भी पीला रंग तैयार किया जा सकता है. यदि इसे उबाल दें तो रंग और भी गहरा होता है.

मैजेंटा (लाल और बैंगनी का मिश्रण)

- चुकंदर के पेड़ की जड़ को टुकड़ों में काट लें और उसे पानी में डालकर छोड़ दें. इसे उबाल कर रात भर ऐसे ही छोड़ देने से रंग और भी गहरा होता है.
- 10-15 गुलाबी प्याज के छिलकों को आधा लीटर पानी में उबालने से गुलाबी रंग तैयार होता है. इस्तेमाल से पहले इन छिलकों को हटा देने से प्याज की गंध भी नहीं रहती.
- गुलाबी कचनार के फूलों को पानी में डालकर उबालने या रात भर ऐसे ही छोड़ देने से भी गुलाबी रंग तैयार होता है.

केसरिया

- टेसू, पलाश या ढाक के फूलों को छाया में सुखाकर उसका चूरा तैयार करें.
- इन फूलों को पानी के साथ उबाल कर रात भर ऐसे ही छोड़ देने से केसरिया रंग का पानी तैयार होता है.
- केसर के कुछ टुकड़ों को दो चम्मच पानी में डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. फिर उसे पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी मिला दें. हालांकि यह महंगा होता है, लेकिन हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है.

भूरा

- पान के साथ खाए जाने वाले कत्थे में पानी मिलाने से भूरा रंग तैयार होता है.
- चाय या कॉफी के पत्ते को पानी में उबालें. फिर इसे ठंडा कर भूरे रंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

काला

- सूखे आंवले को किसी लोहे के बर्तन में उबाल कर उसे रात भर वैसे ही छोड़ दें. सुबह उसमें उचित मात्रा में पानी मिलाकर उसे काले रंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.
- काले अंगूर का जूस निकाल कर उसमें पानी मिलाने से भी काला रंग तैयार होता है. (स्रोत: क्लीनइंडिया.ओआरजी)

हालांकि यह सारे रंग ख़रीदे भी जा सकते हैं. होली के लिए प्राकृतिक कलर्स बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं. आप यह रंग अपने घर में तैयार करें या बाज़ार से ख़रीदें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि इस बार हम होली अपने स्वास्थ्य या वातावरण की क़ीमत पर नहीं खेलेंगे. होली का त्योहार, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो गेहूं की नई फ़सल के उपलक्ष्य और वसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है, को एक बार फिर से ख़ूबसूरत बनाने की ज़रूरत है. आइए, हम सब मिलकर होली के वास्तविक स्वरूप और इसके पुराने उत्साह को दोबारा लाने के लिए कोशिश करें.

feedback@chauthiduniya.com

चार फरवरी को सिलीगुड़ी में विद्यार्थी मोर्चे के कॉडरों पर लाठीचार्ज के बाद पहाड़ आग की लपटों से झुलसने लगा.

स्वायत्त परिषद पर गोरखा मान जाएंगे?

बिमल राय

गोरखा जन मुक्ति मोर्चे के मुखिया विमल गुरुंग अपने आंदोलन को गांधीवादी करार देते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर वह सुभाषपंथी होने में देर नहीं करते. ऐसा एक बार नहीं, बार-बार दिखा है. पहाड़ पर चलने वाले वाहनों में गोरखालैंड की नंबर प्लेट लगाने, अपने इलाक़े में समानांतर पुलिस व्यवस्था बहाल करने और हाल में दार्जिलिंग में डीएम एवं तीन अनुमंडल अधिकारियों को उनके कमरों में बंद करने की हरक़तों में उनका गांधीवाद लाठीतंत्र में बदलता प्रतीत होता है. आठ फरवरी को कालिंपोंग के पास डेलो में एक जनसभा में गुरुंग ने ऐलान किया कि अगले दौर की त्रिपक्षीय वार्ता में वह ख़ुद तभी शामिल होंगे, जब केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम और राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य शिरकत करेंगे. मालूम हो कि अब तक किसी भी त्रिपक्षीय वार्ता में गुरुंग नहीं शामिल हुए हैं. इस रैली में ही गुरुंग ने केंद्र को भेजे गए गोपनीय प्रस्ताव के बारे में खुलासा किया. त्रिपक्षीय वार्ता के एक दिन पहले वह इसकी घोषणा करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक़, नई परिषद का नाम गोरखालैंड स्वायत्त परिषद हो सकता है और इसमें पर्वतीय इलाक़े के विकास की कई योजनाओं का खाका रखा जाएगा. गोरखा नेताओं के मुताबिक़, यह व्यवस्था भी कुछ महीनों के लिए होगी, क्योंकि गुरुंग 2011 के विधानसभा चुनावों के पहले गोरखालैंड का गठन चाहते हैं. राज्य के नगर विकास मंत्री एवं उत्तर बंगाल के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अशोक भट्टाचार्य गुरुंग को फूटी आंख भी नहीं सुहाते. जनसभा में गुरुंग ने यह भी कहा कि वह उन लोगों से बात नहीं करना चाहते, जो सीमा की बाड़ फांद कर बांग्लादेश से आए हैं. इसी जनसभा में मोर्चे के महासचिव रोशन गिरि ने कहा कि अगले दौर की त्रिपक्षीय वार्ता में हमारे प्रस्ताव को अगर हूबहू नहीं माना गया तो हम पहाड़ से डीएम, एसपी, डीएसपी और अनुमंडल अधिकारियों को भागने पर मजबूर कर देंगे.

चार फरवरी को सिलीगुड़ी में विद्यार्थी मोर्चे के कॉडरों पर लाठीचार्ज के बाद पहाड़ आग की लपटों से झुलसने लगा. सिलीगुड़ी में बस फूंकी गई तो दार्जिलिंग में पुलिस जीप जला दी गई. भीड़ ने दार्जिलिंग, कालिंपोंग और कर्सियांग थानों को घेर लिया. उसी दिन शाम तीन बजे से मोर्चे के कॉडरों ने ज़िला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र गुप्ता और तीनों अनुमंडलों के प्रमुखों को कार्यालयों में पूरे 24 घंटे तक कैद रहने पर मजबूर कर दिया. डीएम पर गुस्सा इस वजह से था कि प्रशासन ने सिलीगुड़ी के पास डागापुर और जलपाईगुड़ी ज़िले के वीरपाड़ा में विद्यार्थी मोर्चे को जनसभा करने की इजाज़त नहीं दी. इन रैलियों को विमल गुरुंग संबोधित करने वाले थे. सभा करने की इजाज़त न मिलने पर विद्यार्थी मोर्चे के कॉडर दार्जिलिंग मोड़ पर धरने पर बैठ गए. प्रशासन के सामने भी मजबूरियां हैं. सिलीगुड़ी में इस तरह के किसी आंदोलन की अनुमति देने का मतलब ही हिंसा होगा, क्योंकि वहां आमरा बंगाली एवं जन जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का जोर है. सिलीगुड़ी कई बार जातीय संघर्ष का गवाह बना है. गोजमुमो के अलावा दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग में शामिल आल इंडिया गोरखा लीग ने राज्य सरकार की भेदभाव वाली नीतियों का विरोध जताने के लिए छह फरवरी को 24 घंटे के बंद का पालन किया. आठ फरवरी को वीरपाड़ा में गोरखा नेताओं द्वारा जनसभा करने की घोषणा से टकराव की नौबत आई, पर पुलिस ने 500 गोजमुमो कॉडरों को हिरासत में ले लिया और बाक़ी को खदेड़ दिया. गोजमुमो पिछले साल सात फरवरी को मारे गए अपने कार्यकर्ता अकबर लामा की याद में शहीद दिवस मनाना चाहता था. इसे विफल करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने बंद बुलाया था.

गोरखा नेताओं को भी लगने लगा है कि गोरखालैंड का सपना पूरा होने में काफ़ी दिक़्क़तें हैं और फ़िलहाल ज़्यादा अधिकारों वाली स्वायत्त परिषद लेकर अलग राज्य की लड़ाई जारी रखनी चाहिए. विमल गुरुंग राज्य की मुख्य धारा की राजनीति से भी जुड़ना चाहते हैं. पिछले साल जलपाईगुड़ी ज़िले की राजगंज विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में मोर्चे ने तृणमूल का समर्थन किया था. वैसे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुभाष घीसिंग ने सत्तारूढ़ दल वाममोर्चे से तालमेल रखने में ही भलाई समझी थी, पर 2011 के विधानसभा चुनावों के परिणामों के बारे में असमंजस होने के कारण गुरुंग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि तालमेल माकपा से हो या तृणमूल से. लोकसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, पर विधानसभा चुनावों में उनकी रणनीति अलग होगी. गुरुंग बीच-बीच में विकास की बात करते हैं, पर गोरखालैंड आंदोलन के कारण दार्जिलिंग पांच साल पीछे चला गया है, इसमें कोई शक़ नहीं. ज़िला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र गुप्ता के मुताबिक़, नरेगा और आइला तूफ़ान के बाद पहाड़ पर आई प्राकृतिक विपदा के कारण टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का काम महीनों से ठप पड़ा हुआ है. डीएम और अनुमंडल अधिकारियों को ताले में बंद रखने से सरकारी मशीनरी का मनोबल टूटता दिख रहा है. दार्जिलिंग में वाहनों की आवाजाही न होने से सरकारी कामकाज भी प्रभावित है. गुरुंग के असहयोग आंदोलन के तहत पिछले साल सात नवंबर से पहाड़ पर सरकारी कार्यालय बंद हैं. हालांकि 21 दिसंबर को दार्जिलिंग में हुई चौथे दौर की त्रिपक्षीय वार्ता को देखते हुए इसमें दो दिन की ढील दी गई थी.

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत अलग स्वायत्त परिषद पर राजी होकर फ़िलहाल गुरुंग ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है. वह जानते हैं कि तेलंगाना का मामला भी धीमे-धीमे आगे बढ़ रहा है और वह आगे भी अपना असहयोग आंदोलन जारी रखकर लोगों को परेशान करने के पक्ष में नहीं हैं. प्रतीकात्मक रूप से ही सही सत्ता में आकर वह अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं. सुभाष घीसिंग ने तो लिखकर दे दिया था कि वह कभी गोरखालैंड का समर्थन नहीं करेंगे. गुरुंग गोरखाओं को यह समझाने में कामयाब हुए हैं कि वह गोरखालैंड की लड़ाई जारी रखेंगे. वैसे उनकी स्वायत्त परिषद का जब तक पूरा खाका सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा. हालांकि गोजमुमो के नेता अभी भी स्वायत्त परिषद के बारे में खुलकर नहीं बोल रहे हैं. मोर्चे के महासचिव रोशन गिरि ने चौथी दुनिया को बताया कि हमें गोरखालैंड से कम कुछ भी नहीं चाहिए और इसके लिए हमारा भूख हड़ताल आंदोलन जारी रहेगा. आदिवासियों के विरोध के संबंध में उन्होंने कहा कि वे भी उपेक्षित हैं और देर-सबेर वे गोरखालैंड की सीमा में रहने के लिए राजी हो जाएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

आदिवासियों ने बदला सुर

उत्तर बंगाल में अलगाव और स्वायत्तता के रूप में आज़ादी की लौ और लहक उठी है. आदिवासी इलाक़ों को गोरखालैंड की सीमा से दूर रखने के बारे में भले ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेता आश्वस्त हो गए हों, पर राज्य सरकार के विकास के वादे पर उन्हें शक़ है. तभी तो वे अब इन इलाक़ों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता देने की मांग कर रहे हैं. अभी पिछले दिनों चौथी दुनिया से बातचीत में परिषद के राज्य अध्यक्ष बिरसा तिर्की ने कहा था कि आदिवासियों के विकास की गारंटी हमें संविधान देता है, फिर वे अलग राज्य की मांग क्यों करें? आदिवासी नेताओं के रुख़ में बदलाव का कारण गोरखा जन मुक्ति मोर्चा है, जिसने गोरखालैंड बनने से पहले स्वायत्त परिषद की गोपनीय मांग केंद्र के पास भेज दी है. इन नेताओं का कहना है कि दार्जिलिंग के एक लाख गोरखाओं के लिए जब छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद दी जा सकती है तो उत्तर बंगाल के 30 लाख आदिवासियों के लिए क्यों नहीं?

फरवरी के पहले सप्ताह में परिषद ने सिलीगुड़ी अनुमंडल कोर्ट के बाहर अपनी मांग के समर्थन में धरना दिया और 10 फरवरी से 12 फरवरी तक दिल्ली में उसके छह नेताओं ने कई केंद्रीय मंत्रियों एवं अनुसूचित जाति आयुक्त से मुलाक़ात कर आदिवासियों की समस्याएं उनके सामने रखीं. प्रतिनिधिमंडल के नेता तिर्की ने बताया कि हमने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, वित्त राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा एवं अन्य नेताओं से मुलाक़ात की और अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपा. सांगठनिक सचिव राजू बारा ने बताया कि परिषद की मांगों में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग ज़िलों के कुमारग्राम, कालचीनी, मदारीहाट, वानरहाट, नागराकाटा, मालबाज़ार, फासीदेवा और मेटेली प्रखंडों को मिलाकर स्वायत्त परिषद का गठन, डुआर्स तराई क्षेत्र में हिंदी स्कूलों, कॉलेजों और एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं फोरलेन सड़क का निर्माण, चाय बागानों की ज़मीन का पट्टा, बागान श्रमिकों को बीपीएल सूची में शामिल करना, परिषद के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर दायर झूठे मुक़दमे वापस लेना और सिलीगुड़ी के पास स्थित सेवक पुल की तरह तिस्ता पर भी पुल बनाना आदि शामिल हैं. आदिवासी नेताओं का आरोप है कि चाय बागानों में बीपीएल सूची तैयार करने में बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया. यह सुविधा उन्हीं को हासिल है, जो वाम यूनियनों से जुड़े हैं. इस तरह आदिवासी नेता भी स्वायत्तता की मांग कर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं, ताकि वह उनकी उपेक्षा न करे.

मुआवज़ा नहीं, गोरखालैंड चाहिए

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के पास सालिदा में 15 फरवरी को माओवादियों के हमले में मारे गए ईस्टर्न राइफल्स के 24 जवानों में से 13 दार्जिलिंग, कालिंपोंग, कर्सियांग, मिरिक एवं सिलीगुड़ी के गोरखा थे. बर्बर गोलीबारी के बाद जब राज्य के वित्तमंत्री असीम दासगुप्त जब सालुआ में शहीद जवानों के परिवार वालों को सांत्वना देने पहुंचे तो उन्हें जनाक्रोश का सामना करना पड़ा. लखन राम बहादुर के साले साम थापा ने कहा कि हमें यह दिन इसलिए देखना पड़ रहा है कि गोरखालैंड की हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है. हम मुआवज़ा लेने से इंकार करते हैं. सरकार ने हमेशा हमारी उपेक्षा की है. अब उसे मुआवज़ा देने के बदले हमारी मांग मान लेनी चाहिए. शहीद अजय थापा की विधवा रीता थापा ने कहा कि सरकार ने मध्य आयु के जवानों को लड़ाई के मैदान में भेजकर नियमों का उल्लंघन किया है. हमारे ज़्यादातर शहीद जवानों की उम्र 45 से ज़्यादा थी. सरकार को ऐसे हालात में युवा सैनिकों को भेजना चाहिए था और मध्य आयु के जवानों को सुरक्षित ड्यूटी पर. मालूम हो कि हमला शाम पांच बजे के आसपास हुआ, जब जवान भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे.

माओवादियों का हमला इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद जवानों को संभलने का मौक़ा नहीं मिला और वे जवाबी फायरिंग तक नहीं कर पाए. शहीद अजय की पत्नी रीता थापा ने एक और खुलासा किया कि उनके पति बराबर यह शिक़ायत करते थे कि चौकी में कोई वाच टावर नहीं है और कोई भी चाहरदीवारी फांद कर हम तक पहुंच सकता है. शहीद हुए 13 जवानों के नाम हैं मिकमार तामांग, नीमती शेरपा, मुनाल छेत्री, विमान राई, प्रदीप प्रधान, दौलत राई, तेशरिंग भूटिया, मधुकर सुब्बा, शांति कुमार राई, डी बी छेत्री, प्रेम तेशरिंग लेप्चा और 60 वर्षीय लांस नायक सुरेश राई.

17 फरवरी को जैसे ही इन जवानों के शव बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे, पूरे पहाड़ पर हर तरफ मातम छा गया. इस बर्बर हत्याकांड के ख़िलाफ़ बीती 17 फरवरी को गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने पहाड़ पर बंद का ऐलान किया, जो पूर्णत: सफल रहा. 19 फरवरी को पार्टी के झंडे झुका दिए गए.

चौथी दुनिया

मृत्यु दंड का प्रावधान न केवल जघन्य अपराधों को रोकने में निवारक का काम करता है, बल्कि समाज द्वारा ऐसे अपराधों की तीव्र मुख़ालफ़त का सूचक भी है.

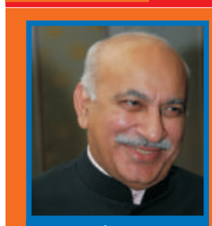

एम जे अकबर

गणतंत्र दिवस और पद्म पुरस्कारों का विवाद

उदासी की कई वजहों के चलते मौलाना आज़ाद का ख़याल अक्सर मेरे जेहन में आता है. हम उनकी यादों को नज़रअंदाज़ करते हैं. इसकी दुखद मिसाल दिल्ली की जामा मस्जिद के पास उर्दू पार्क में दिख जाती है. यह बेहद दयनीय स्थिति है कि हम उस निराश बहादुर शाह ज़फ़र को आदर्श मानते हैं, जिसने भारतीय साम्राज्य को अंग्रेज़ों के हाथों गंवा दिया. और, उस शख्स की कद्र नहीं करते, जिसने अपने दर्ज़नों साथियों के साथ ब्रिटिश हुकूमत को नेस्तनाबूद किया. एकतरफ़ा आस्था आज़ाद की राजनीति की पहचान थी. जबकि उनके महान हमवतनों ने अपने समुदाय का साथ दिया था. आज़ाद उन सबसे दूर तो रहे, लेकिन वह भी दृढ़ता और बहादुरी के साथ समाज में पनप रहे विद्वेष के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए. मौलाना आज़ाद के राजनीतिक साहस को कई बुद्धिजीवियों द्वारा सराहा गया. सरोजिनी नायडू ने एक बार कहा था कि आज़ाद ने 50 साल के अनुभवी के तौर पर जन्म लिया. आज़ाद को यदि समझना हो तो इन दो पंक्तियों से समझा जा सकता है, जिसे ख़ुद उन्होंने 14 साल की उम्र में लिखा था, आज़ाद बेख़ुदी के नशेबोफराज़ देख पूछी ज़मीन की तो कहीं आसमान की.

(सवाल धरती का था, तो जवाब आसमान का) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे. इस पद पर वह अपनी मृत्यु यानी 1958 तक बने रहे. नेहरू इस महान शख़्सियत को सबसे बड़े अवार्ड पद्म पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते थे. आज़ाद इस बात पर हंस पड़े. उन्होंने पूछा कि भला एक सरकार ख़ुद को कैसे पुरस्कृत कर सकती है. आज़ाद ने राजनीतिक हथकंडों के ज़रिए अपनी उपयोगिता साबित नहीं की. अभी कुछ लोगों ने अवार्ड लेने से इंकार कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी आज़ादी पर सरकार के उपहार द्वारा सेंध लगाई जाए. आप बेहद भोले ही होंगे कि इस बात पर यक़ीन करें कि अवार्ड देने की प्रक्रिया में सरकार का कोई दख़ल नहीं होता है. आपको या तो बेहद चिंतित या पाखंड के आवरण की ज़रूरत होगी, ताकि आप पद्म पुरस्कारों के लिए लॉबी, याचना और मान-मनुहार कर सकें. आपको पुरस्कृत तो किया जाए, लेकिन आपको इसका पता ही न चले. देखा गया है कि अभी भी पचास फ़ीसदी मामलों में ऐसा ही होता है. बाक़ी आधा रैकेटबाज़ों के लिए यह एक अवसर की तरह है. ऐसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की धोखेबाज़ी और छल-कपट के बाद पद्म पुरस्कारों को एक उपलब्धि प्रमाणपत्र के तौर पर दिखाते हैं. इन पुरस्कारों का यही विकृत मक़सद है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों ने ही अपने दिलों में इस सनक को मान्यता दे दी है. और, यही कारण है कि वे इसके बारे में कोई परवाह नहीं करते हैं. यदि एक मायने में देखें तो अवार्ड दो संभ्रांतों के बीच साझा सहयोग है. सैफ़ अली ख़ान अचानक पद्मश्री बन गए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी टिकट ख़रीद कर उनकी मूवी देखने की जल्दबाज़ी नहीं दिखा रहा है. यदि स्पष्ट तौर पर कहें तो जब यह सम्मान सैफ़ को दिए जाने का ऐलान हुआ तो वह ख़ुद उलझन में थे. सैफ़ बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. और, वह लगभग उसी तरह नाचते हैं, जैसे उनकी प्रेमिका नाचती है. लेकिन, यदि उन्हें कोई लीजेंड समझने लगे तो किसी को भी इस बात पर शक़ होगा.

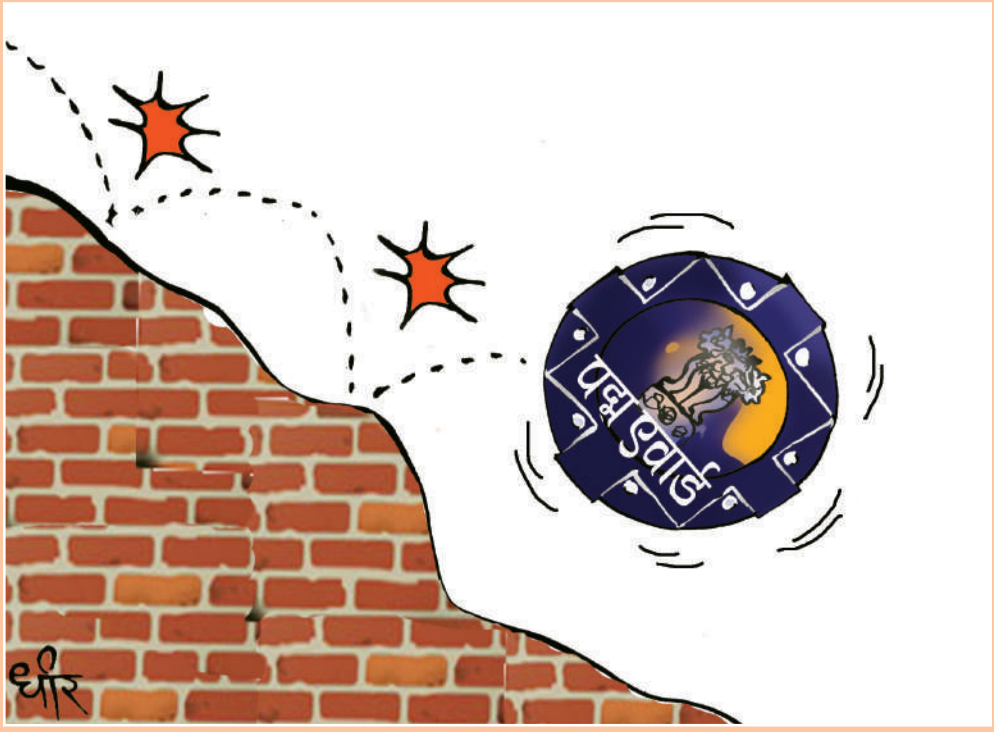

अवार्ड के बारे में सबसे दिलचस्प किस्सा मुझे एक बेहतरीन इंसान ने बताया. वह एच वाई शारदा प्रसाद हैं. यह मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एच वाई शारदा प्रसाद को या उनके बारे में जानता था. वह इंदिरा गांधी के सबसे विश्वस्त क़रीबियों में थे. ईमानदारी उनकी विशेष ख़ासियत थी, लेकिन उनकी ख़ास संपत्ति उनकी बुद्धिमत्ता थी, जिसे उन्होंने सीखने की प्रक्रिया और अनुभव से हासिल किया था. शारदा प्रसाद अच्छे और बुरे दोनों वक़्त में एक समान रहे. जब वह सत्ता के गलियारों में वनवास (1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद) झेल रहे थे तब, और जब प्रधानमंत्री कार्यालय में थे तब, दोनों ही समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते थे. वह डी जी तेंदुलकर के मित्र थे. इनकी नौ खंडों वाली इंदिरा गांधी की जीवनी बेतरतीब लिखी हो सकती है, लेकिन वह आधुनिक भारतीय इतिहास की महान कृतियों में एक है. आज यह प्रकाशन विभाग की शेल्फ में भुला दी गई है. इसे पुस्तकालयों द्वारा सम्मानित सूची के तहत ख़रीदा गया, क्योंकि इसे कोई नहीं पढ़ता है. तेंदुलकर मुंबई के एक साधारण किराए के मकान में रहते थे. वहां उनका सबसे बेहतर साथी उनका कुत्ता था. हर सुबह यह कुत्ता इस लेखक को जगाता और फिर दोनों एक साथ मरीन ड्राइव टहलने के लिए जाते थे. घर लौटने पर तेंदुलकर थोड़ी देर आराम करते थे. एक दिन जब तेंदुलकर सोए हुए थे तो उनका कुत्ता तेज़ी से आया, उन्हें बिछावन से उठाया और बाहर गली में ले आया. जैसे ही वह ख़ुली हवा में बाहर पहुंचे, भूकंप का एक झटका आया और उनका मकान नष्ट हो गया. लेकिन, वास्तव में कहानी यह नहीं है. जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तब तेंदुलकर को पद्मभूषण दिया गया था. उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया स्वरूप राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम भेजा. उसमें उन्होंने कहा था कि क्या उन्हें इस पुरस्कार की जगह एक घड़ी दी जा सकती है. उस वक़्त उन्हें सबसे अधिक जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी घड़ी. न कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला काग़ज़ का एक टुकड़ा. तेंदुलकर को घड़ी और पद्म दोनों मिले.

तेंदुलकर से लेकर तेल व्यापारी तक यह गणतंत्र के लिए एक तीव्र पतन है.

feedback@chauthiduniya.com

मृत्यु दंड : अमानवीय या ज़रूरत

रवि किशोर

कैपिटल पनिशमेंट, जिसे मृत्यु दंड या फांसी के नाम से भी जाना जाता है, का मुद्दा उसके समर्थकों और विरोधियों के बीच अक्सर गर्मागर्म बहस का कारण बनता रहा है. मृत्यु दंड के ख़िलाफ़ तर्क देते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है, मृत्यु दंड मानवाधिकारों के उल्लंघन की पराकाष्ठा है. वास्तव में यह न्याय के नाम पर व्यवस्था द्वारा किसी इंसान की सुनियोजित हत्या का एक तरीक़ा है. यह जीने के अधिकार के विरुद्ध है... यह न्याय का सबसे क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक तरीक़ा है. यातना या क्रूरता को किसी लिहाज़ से न्यायोचित नहीं माना जा सकता.

मृत्यु दंड के समर्थकों का तर्क है कि मानव जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और निर्दोषों की रक्षा करना समाज का अधिकार ही नहीं, उसका कर्तव्य भी है. निर्दोषों की रक्षा का एक तरीक़ा यह है कि जघन्य अपराध के आरोपियों को ऐसी सजा मिले, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण हो, उन्हें ऐसे अपराध करने से रोकने का काम करे. पूरे देश में फिरौती के लिए अपहरण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को अपहरणकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा देने की सलाह दी थी. न्यायालय ने कहा था कि क़ानून फिरौती के लिए अपहरण की कुछ ख़ास स्थितियों में मृत्यु दंड तक की इजाज़त देता है और इसके लिए अपहृत व्यक्ति की हत्या कोई आवश्यक शर्त नहीं है. न्यायमूर्तिद्वय एच एस बेदी एवं जे एम पांचाल की खंडपीठ ने कहा था, आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरौती के लिए अपहरण सारे देश में एक लाभदायक उद्योग का रूप लेता जा रहा है और इसके ख़िलाफ़ कड़े से कड़े क़दम उठाने की ज़रूरत है तथा इसकी कुछ ज़िम्मेदारी अदालतों के ऊपर भी है. सर्वोच्च न्यायालय की इस सलाह के बाद अपहरणकर्ताओं के ख़िलाफ़ कड़े दंड के प्रावधानों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि न्यायालय ने दो ऐसे अपराधियों की मृत्यु दंड की सजा बरक़रार रखी, जिन्होंने होशियारपुर में एक 16 वर्षीय छात्र का फिरौती के लिए अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

न जाने कब से मृत्यु दंड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसका कोई आख़िरी परिणाम नहीं निकल पाया है. विचारक, न्यायाधीश, न्यायविद और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग इस मुद्दे पर एकमत नहीं है. वह भी तब, जबकि सदियों से मृत्यु दंड का प्रावधान कई देशों की न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग रहा है. हालांकि भौगोलिक और ऐतिहासिक वजहों से इसके स्वरूप में भिन्नता देखने को मिलती है. भारतीय न्याय व्यवस्था न्याय के सुधारक और निवारक सिद्धांतों का मिश्रण है. दंड विधान का एक लक्ष्य जहां अपराधियों को अपराध करने से रोकना है, वहीं इसका दूसरा लक्ष्य उन्हें सुधरने का मौक़ा देना भी है. इन्हीं मूलभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने अपराध दंड संहिता में धारा 354(3) को जगह दी है. यह उपधारा वास्तव में मृत्यु दंड की सजा सुनाने की हालत में न्यायालय द्वारा इसकी ख़ास वजहों को स्पष्ट करने की एक आवश्यक शर्त बताती है. इस तरह 1973 के बाद से दंड संहिता में संगीन अपराधों की हालत में आजीवन कारावास का प्रावधान है, जबकि विशेष परिस्थितियों में मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है.

वर्ष 1983 में बच्चन सिंह मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि मृत्यु दंड की सजा को संगीनतम अपराधों तक ही सीमित रखना चाहिए और इसे एक अपवाद की तरह ही देखा जाना चाहिए. अर्थात संगीन अपराधों की अति विशेष परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए. हत्या, सामूहिक डकैती के साथ हत्या, किसी बच्चे या मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना और किसी सैन्य विद्रोह में शामिल होने जैसे अपराध संगीनतम अपराधों की श्रेणी में आते हैं. सच यह है कि भारत में कुछेक जघन्य और राजनीतिक अहमियत वाले मामलों में ही मृत्यु दंड की सजा अपराधियों को दी गई है. पिछले 60 सालों के इतिहास पर नज़र डालें तो महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने के मामले हमारी नज़रों के सामने आते हैं.

हाल के वर्षों में आतंकवाद के ख़िलाफ़ क़ानून के तहत आतंकी गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को फांसी की सजा देने का चलन बढ़ा है. स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड के प्रावधान को और कड़ा कर दिया. अपने फ़ैसले में न्यायालय ने माना कि बच्चन सिंह मामले में मृत्यु दंड को अपवाद मानने का प्रावधान मच्छी सिंह मामले में कमज़ोर पड़ गया. निर्णय में यह भी कहा गया कि अपवाद या अपराध की संगीनता को मानने का पैमाना केवल गुणात्मक ही न हो, बल्कि संख्यात्मक भी होना चाहिए. इस तरह जहां मच्छी सिंह मामले में फ़ैसले के बाद एक ओर अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, वहीं संगीनतम अपराधों के दायरे में भी बदलाव अपेक्षित है. इस निर्णय के बाद यह देखना रोचक होगा कि ऐसे अपराधों के मामलों में न्यायालयों का क्या रुख़ रहता है.

भारत में मृत्यु दंड की सजा पर विवाद तब और गहरा हो गया, जब स्वामी श्रद्धानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश फांसी की सजा की हालत में अपनाए जाने वाले मानकों पर एकमत नहीं हो पाए और मामले को एक बड़ी खंडपीठ के सामने रखना पड़ा. इस मामले में तीन सदस्यीय खंडपीठ के फ़ैसले को मृत्यु दंड की सजा समाप्त करने की दिशा में न्याय व्यवस्था की एक बड़ी पहल माना जा सकता है. इसके ठीक बाद संतोष कुमार बरियार के मामले में न्यायमूर्ति सिन्हा के फ़ैसले से इस पहल को और मज़बूती मिली. इन मामलों के अध्ययन से जो बात उभर कर सामने आती है, वह यह है कि अलग-अलग मामलों में समान तथ्यों को अलग-अलग अंदाज़ में देखा जाता है. और, फांसी दी जाए या नहीं, यह अक्सर ही न्यायाधीशों की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद पर निर्भर होकर रह जाता है. यह परिस्थिति, ख़ासकर मृत्यु दंड जैसे अहम फ़ैसलों के लिहाज़ से उचित नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों के ख़िलाफ़ भी है. बरियार ने इस मुद्दे पर ख़ासा ज़ोर दिया था और फ़ैसले से पहले सुनवाई के प्रावधान की वकालत भी की थी, जिससे यह साबित किया जा सके कि आरोपी में सुधार की कोई संभावना नहीं है.

भारतीय संसद पर हमले के आरोपी आतंकी मोहम्मद अफजल गुरु की क्षमा प्रार्थना अर्जी को मीडिया में काफ़ी सुर्ख़ियां मिलीं. जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने उसकी इस अर्जी का समर्थन किया. कश्मीर घाटी में इस मुद्दे पर लोगों ने ज़ोरदार प्रदर्शन किए और हालत यह हो गई कि पूरा देश दो धड़ों में बंटा हुआ नज़र आने लगा. एक ओर कश्मीरी जनता थी तो दूसरी ओर बाक़ी देश. इस विवाद ने मृत्यु दंड के फ़ैसले से संबंधित मुद्दों को फिर से सतह पर ला दिया. जैसे, क्या मृत्यु दंड की सजा ख़त्म कर देनी चाहिए? क्या अफजल गुरु का मामला मृत्यु दंड के मानकों और इससे संबंधित अन्य न्यायिक फ़ैसलों पर खरा उतरता है? धारा 302 के तहत हत्या के मामलों में फांसी की सजा लोकहित में है या नहीं? क्या धारा 302 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के ख़िलाफ़ तो नहीं है? आदि.

मृत्यु दंड की सजा समाप्त करने के लिए विधायिका के सभी प्रयास अब तक असफल रहे हैं. इस दिशा में स्वतंत्रता से पहले ही 1931 में संसद के सामने एक प्राइवेट बिल पेश किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के तत्कालीन गृहमंत्री ने इसे मानने से इंकार कर दिया. स्वतंत्रता के बाद पहली लोकसभा के कार्यकाल में भारत सरकार ने भी ऐसे ही एक बिल को नामंजूर कर दिया था. फांसी की सजा समाप्त करने के लिए राज्यसभा में भी 1958 और 1962 में प्रयास किए गए, लेकिन थोड़ी-बहुत चर्चा के बाद इसे वापस ले लिया गया. विधि आयोग ने भी 1967 में सरकार और 1971 में लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्टों में मृत्यु दंड के प्रावधान को बनाए रखने की अनुशंसा की. और, यह भी कहा कि कार्यपालिका (राष्ट्रपति) के पास माफ़ी का अधिकार बरक़रार रहना चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय ने जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश मामले में धारा 302 की वैधानिकता पर विचार किया. उसने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों सहित अन्य देशों में मौजूद परिस्थितियों, भारतीय अपराध क़ानून की संरचना, न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की सीमा जैसे मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों पर जमकर विचार-विमर्श किया. आख़िर में शीर्ष न्यायालय ने अपने फ़ैसले में कहा कि मृत्यु दंड का प्रावधान न केवल जघन्य अपराधों को रोकने में निवारक का काम करता है, बल्कि समाज द्वारा ऐसे अपराधों की तीव्र मुख़ालफ़त का सूचक भी है. एक ऐसे समाज में, जहां हत्या जैसे अपराधों को पाशविक और क्रूर माना जाता है. पश्चिमी देशों में मौजूद प्रावधानों को भारत में लागू करने की संभावना को इस आधार पर नकार दिया गया कि दोनों की सामाजिक हालत और लोगों की समझ के स्तर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. अदालत ने विधि आयोग की 25वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत फांसी की सजा ख़त्म करने का ख़तरा उठाने की हालत में नहीं है. निचली अदालतों से ऐसे फ़ैसले सुनाने में हुई चूक को उच्चस्तरीय अदालतों में अपील कर सुधारा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी अपना भरोसा बनाए रखा.

फांसी की सजा सुनाने के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का रवैया सावधानी भरा और प्रतिबंधात्मक रहा है, जो आधुनिक न्याय व्यवस्था के उदारवादी रवैये से मेल खाता है. शीर्ष अदालत द्वारा संगीनतम अपराधों और अपवाद की विचारधारा न्याय व्यवस्था के मानवीय पहलू को उजागर करती है. ऐसे कई मामले हैं, जिनमें अदालत ने इस श्रेणी में आने वाले अपराधों की हालत में भी आरोपी को मृत्यु दंड देने से इंकार कर दिया है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

एक गंभीर आलेख

08-14 फरवरी के अंक में बिमल राय का आलेख-रिक्शा वाले धीमी मौत मर रहे हैं, अच्छा लगा. लेखक ने बहुत ही सटीक तरीक़े से इशारा किया कि हम ऐसे मानवीय मुद्दों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं. सरकार का रवैया भी संतोषजनक नहीं है. ऐसे गंभीर आलेख प्रकाशित करने के लिए चौथी दुनिया परिवार को बधाई.

बनवारी लाल, *कोरबा, मध्य प्रदेश.*

बनते-बिगड़ते रिश्ते

आलेख नाज़ुक मोड़ पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध के अंतर्गत लेखक ने दूसरे देशों के साथ भारत के बनते-बिगड़ते रिश्तों का जायज़ा आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है. विषय के साथ भरपूर न्याय हुआ है. आशा है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से हमें मिलती रहेंगी.

कर्ण कुमार, *साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश.*

अंतरराष्ट्रीय मामलों को प्रमुखता

चौथी दुनिया का मैं कोई पुराना नियमित पाठक नहीं हूं, लेकिन थोड़े ही दिनों में इसने मुझे अपना मुरीद बना लिया है. रंग-बिरंगी तस्वीरों के साथ सुंदर आलेख मन पर अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं. राजनीतिक विश्लेषण हो या सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई मुद्दा, उसकी गहराई में जाकर विविध पक्षों की विवेचना का आपका अंदाज़ वास्तव में क़ाबिले तारीफ़ है. अंतरराष्ट्रीय मामलों को थोड़ी और प्रमुखता मिले तो शायद अच्छा होगा.

मुकेश कुमार, *सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश.*

मेरी दुनिया और धीर जी

मैं आपका अख़बार तक़रीबन हर सप्ताह पढ़ता हूं. वेब इश्यू देखकर बहुत प्रसन्न हूं. अख़बार की रिपोर्टिंग और लेख क़ाबिले तारीफ़ हैं. लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह है मेरी दुनिया. मैं धीर से बहुत प्रेरित होकर यह प्रतिक्रिया लिख रहा हूं. उनके कार्टून न केवल व्यंग्य से भरपूर होते हैं, बल्कि देश के राजनीतिक माहौल की सही बानगी पेश करते हैं. आजकल ऐसे कार्टून कम ही देखने को मिलते हैं. मैं चौथी दुनिया को बधाई देना चाहता हूं.

अखिल चंद्रा, *ई-मेल से.*

जज़्बे को सलाम

खेल जगत दिनोदिन नेताओं के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है. आलेख-हॉकी के सहारे राजनीति की कोशिश, नेताओं की साजिश को उजागर करते हुए कई सच्चाइयों से रू-ब-रू कराता है. नेताओं को सीधे-सीधे कठघरे में खड़ा करने के आपके जज़्बे को दिल से सलाम करता हूं. उम्मीद है, ऐसे लेख बार-बार पढ़ने को मिलेंगे.

सुधीर कनौजिया, *सागर, मध्य प्रदेश.*

आतंकवाद के प्रति अमेरिकी रवैया

वरिष्ठ पत्रकार आयशा सिद्दीका ने अपने लेख में आतंकवाद के प्रति अमेरिकी नीतियों एवं उसके वास्तविक चरित्र को उजागर किया है. पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है, वह किसी से भी छिपा नहीं है. ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि विश्व समुदाय अपनी आंख खुली रखे और सतत सावधान रहे.

सुजाता, *दरियागंज, दिल्ली.*

बुज़ुर्ग बोझ नहीं हैं

चौथी दुनिया का 8-14 फरवरी का अंक पढ़ा. डी आर आहूजा का लेख बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की ज़रूरत अच्छा लगा. यह वाकई एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है. आज की पीढ़ी बुज़ुर्गों को बोझ समझने लगी है. जबकि सच यह है कि वृद्ध अनुभवों का खजाना एवं मार्गदर्शक होते हैं. सरकार को मेंटीनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2007 को तुरंत लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए.

अरुण सरोहा, *छात्र-हिंदी पत्रकारिता, दिल्ली विश्वविद्यालय.*

ज़रूरत से ज़्यादा रंग

मैं चौथी दुनिया की नियमित पाठक हूं. इसकी हर स्टोरी अच्छी होती है. लेकिन, कभी-कभी इसमें रंगों का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है कि आलेख का प्रभाव कम हो जाता है. ख़ासकर, ख़बरों पर नज़र रखने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लिए यह आंखों में चुभने जैसा है. कृपया रंगों का कम इस्तेमाल करें और फोटो की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

नीलम शुक्ला, *बहादुरगढ़, हरियाणा.*

सरल-सहज भाषा

चौथी दुनिया अखबार मुझे पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. फोटो और ख़बरों के लिहाज से यह बेहद अलग है. तोप मुक़ाबिल की भाषा सरल और सहज है, यह बात आम पाठकों के लिए उचित है. साथ ही, इसमें उठाए जाने वाले मुद्दों का सरोकार हमेशा ही आम आदमी से होता है.आम आदमी की बात आम भाषा में ही होनी चाहिए.

रमेश कुमार, *गोविंद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

होली पर ख़ुशियों के रंग बिखरें

ईद पर हमने प्रार्थना की थी कि सभी के घर ख़ुशियां दस्तक दें, लेकिन दस्तक महंगाई ने दी, दरवाज़ा नफ़रत ने खटखटाया, यहां तक कि देश में होने वाले कॉमन वेल्थ खेलों को न होने देने की धमकी बाहर से भी मिली और अंदर से भी. अब होली आई है. इच्छा हो रही है कि भगवान, अल्लाह, गॉड और वाहे गुरु से हाथ जोड़ कर कहें कि इस देश के आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ी ख़ुशियों के रंग बिखरें. कम से कम हमें मालूम तो हो कि हमारे अल्लाह, भगवान, गॉड और वाहे गुरु हमारी ओर से लापरवाह नहीं हैं. देखें क्या होता है, पर दुआ तो अच्छे के लिए ही करनी चाहिए.

दिल्ली में पिछले दिनों कुछ मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई और उन्होंने रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन करने की बात कही. हमें अच्छा लगा, क्योंकि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट संसद में रखवाने में चौथी दुनिया की बड़ी भूमिका थी. लेकिन एक डर भी लगा कि कहीं इसका परिणाम कुछ और न निकले. हमारा अनुरोध उन सभी मुस्लिम जमातों से है, जो रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफ़ारिशें लागू कराना चाहती हैं कि वे इसकी अगुआई न करें. उन्हें चाहिए कि वे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान सहित वामपंथी दलों पर दबाव डालें कि वे इसे लागू करने की मुहिम की अगुआई करें. यह आवश्यक है.

अगर मुस्लिम संगठन इसकी अगुआई करेंगे तो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कुछ ताक़तें कर सकती हैं. ये ताक़तें सिर्फ़ इंतज़ार ही इस बात का कर रही हैं कि कब मुस्लिम संगठन आवाज़ उठाएं और वे चिल्लाना शुरू करें. धर्म निरपेक्ष शक्तियों की भी यह परीक्षा है. रंगनाथ मिश्र कमीशन को यह काम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह जैसे आदेश के बाद दिया था. सरकार को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, पर सरकार अगर आगे नहीं बढ़ती तो कांग्रेस समेत सभी ऐसे दलों को आगे आना चाहिए, जिन्होंने इसका समर्थन किया है.

यह होली आई ऐसे मौक़े पर है, जब कुछ घटनाएं घटने या न घटने का इंतज़ार कर रही हैं. हरिद्वार में कुंभ हो रहा है. मार्च के दूसरे हफ़्ते में यहां विश्व हिंदू परिषद कोशिश करने वाली है कि राम मंदिर के लिए पुनः कुछ उग्र आंदोलन की भूमिका बने और कुंभ का इस्तेमाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा सके. भारतीय जनता पार्टी की इंदौर कार्यकारिणी में अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जगह मांगी है और पास में ही मस्जिद बनाने का वायदा किया है. मासूम सी दिखती इस अपील के पीछे देश को पुनः दंगों की आग में झोंकने का इशारा नज़र आ रहा है. जब देश ने भाजपा को दो बार लोकसभा चुनाव में नकार दिया तो फिर इस अपील का मतलब नहीं, क्योंकि दोनों बार भाजपा ने मंदिर निर्माण की बात उठाई थी. भाजपा के सामने देश के निर्माण का कोई नक्शा है ही नहीं. उसके पास ग़रीबी, बेकारी, बीमारी, महंगाई का मुक़ाबला करने की इच्छा शक्ति भी नहीं है. भाजपा शासित राज्यों में कोई नई पहल भी नहीं है. पहल तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी नहीं है, पर भाजपा का ज़िक्र इसलिए, क्योंकि उनके पास तो सोच भी नहीं है. वे बार-बार राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, रामराज्य का नहीं. रामराज्य में कोई बेकार नहीं था, भूखा नहीं था, सबके पास समान अवसर था. काश इस होली पर भाजपा ख़ुशियों के रंग बिखेरने का फ़ैसला लेती.

सनातन धर्म ने ही सिखाया है कि सब अपने हैं. सारी दुनिया एक कुटुंब है, सब सुखी रहें, सब साथ-साथ जिएं, सभी अपने से कमज़ोर का ध्यान रखें. सनातन धर्म की इस शिक्षा के विपरीत हिंदू नाम से चलाए जाने वाले धर्म ने हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिंदुओं को सिखों के ख़िलाफ़, हिंदुओं को ईसाइयों के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है. परिणाम यह निकल रहा है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी तक अपने को हिंदुओं से अलग मानने लगे हैं. इतना ही नहीं, देश की बहुसंख्या इन तथाकथित हिंदूवादियों के ख़िलाफ़ है और समय-समय पर अपना रुझान बताती रहती है.

होली ख़ुशियों का त्योहार है, पर ख़ुशियां मनाएं कैसे. एक बड़ी आबादी अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रही है और सरकार उन्हें नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रही है. अपने देश के लोग अगर रोटी, रोज़ी, विकास की मांग करें और अब तक इसे पूरा न करने की कमी पर गुस्सा ज़ाहिर करें तो क्या सरकार को गोलियां और बम आधारित नीति पर चलना चाहिए या सारे देश में एक नई संतुलित विकास नीति पर चलना चाहिए. छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में सरकार से नाराज़गी प्रगट करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है.

होली ख़ुशियों का त्योहार है, पर ख़ुशियां मनाएं कैसे. एक बड़ी आबादी अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रही है और सरकार उन्हें नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रही है. अपने देश के लोग अगर रोटी, रोज़ी, विकास की मांग करें और अब तक इसे पूरा न करने की कमी पर गुस्सा ज़ाहिर करें तो क्या सरकार को गोलियां और बम आधारित नीति पर चलना चाहिए या सारे देश में एक नई संतुलित विकास नीति पर चलना चाहिए.

यह नाराज़गी अब केवल सरकार से नहीं है, बल्कि पूरे राजनैतिक परिदृश्य से है, क्योंकि कोई भी राजनैतिक दल आम आदमी की तक़लीफ़ को अपना मुद्दा नहीं बना रहा. चुनाव होंगे और कोई जीतेगा भी, लेकिन जीतकर भी अपनी जान की चिंता करे, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. जो लोग सरकार से कह रहे हैं कि इसे क़ानून व्यवस्था की समस्या न मान विकास और भ्रष्टाचार की समस्या मानें, उन्हें सरकार नक्सल या माओवादी समर्थक मान रही है. ज़िले स्तर पर जो पत्रकार इस स्थिति पर लिख रहे हैं, उन्हें कई प्रदेशों में पुलिस प्रताड़ित कर रही है और कई जगहों पर जेल भी भेज रही है. कई हैं, जो सालों-महीनों से जेल में हैं और जिनकी यह होली भी जेल में ही बीतेगी. सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि सरकार चलाने वाले अपनी सोच बदलें. आज वे अकेले हैं, क्योंकि बड़े अख़बारों के पत्रकारों और संपादकों का ध्यान इस ओर है ही नहीं. उनका ध्यान जाएगा ज़रूर, जब उन पर हमला होगा.

सरकार चलाने वालों से, चाहे वे राज्य में हैं या केंद्र में, क्या इतनी आशा नहीं करनी चाहिए कि वे अपनी पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाएं. शहरों या गांवों में रहने वाले लोग चैन से अपना जीवन गुज़ार सकें. पर यह आशा दिन का सपना जैसी है. चाहे मुंबई हो या दिल्ली या लखनऊ, पटना, हैदराबाद जैसे शहर, कहीं पर भी आम लोग सुरक्षित नहीं हैं. पुलिस थाना सौ गज़ दूर, लेकिन चोरी-डकैती हो जाती है. पुलिस को अपनी जान पर ख़तरा होने का अंदेशा बताते रहिए, जान चली जाती है. अब तो पुलिस में काम करने वाले ही लुटेरे गिरोहों के सरगना निकल रहे हैं. शायद इसीलिए क़ानून व्यवस्था तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों को ही सरेआम मारपीट रहे हैं. पुलिस का डर इसलिए नहीं रहा, क्योंकि अपराधियों को पता है कि पुलिस को कैसे साधना है.

हां, किसी शरीफ आदमी से छोटी ग़लती होने दीजिए, किसी राजनेता या किसी सरकारी अधिकारी को पुलिस के चंगुल में साधारण ग़लती पर फंसने दीजिए, फिर देखिए पुलिस अपनी सारी कुशलता कैसे साबित करती है. इस स्थिति को बदलने की आशा तो नहीं करते, लेकिन चाहते ज़रूर हैं कि यह स्थिति बदले, क्योंकि इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि पुलिस वालों पर खुलेआम हमले होंगे.

राजनैतिक दल ज़िम्मेदार बनें, जनता के प्रति जवाबदेह बनें और एक सार्थक विपक्ष का रोल निबाहें, इतनी सी आशा उनसे अगर जनता करती है तो क्या गुनाह करती है. राष्ट्रीय समस्याओं और राष्ट्रीय सवालों पर वे कम से कम एक राय बनाएं. अगर यह आशा की जाती है तो क्या बुरा किया जाता है. नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ ग़रीबों को मिलें, तो क्या यह चाहना चांद चाहने जैसा है? देश में रहने वालों को सामान्य सुविधाएं मिलें, इसकी मांग क्या अपराध है? सभी धर्म, सभी वर्ग और समुदायों के लोग प्यार से साथ रहें और उन्हें आप रहने दें, इसका चाहना क्या देशद्रोह है?

देश के लोगों की ये कुछ छोटी-छोटी इच्छाएं हैं, जिनके लिए हम ईद, दीवाली और होली पर प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं. चाहते हैं कि भगवान, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड इस पर ध्यान दें, क्योंकि इंसानों की सल्तनत से तो आशाएं टूट रही हैं.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

यह किस महंगाई पर बहस है?

चंचल

हस्बे ज़ैल अर्ज कर दूं कि चौथी दुनिया पता नहीं किस-किस दुनिया से घूमते हुए हमें हमारे गांव तक आ जाती है. हुआ यूं है कि हमारे डाकघर का आदमी भी पढ़ा-लिखा है और गांव के कुछ पढ़ाकुओं के बीच उसका उठना-बैठना है. सो, जब कभी भी कोई कागद (अगर रंगीन हुआ तो) वह उसे पहले खोल-खाल कर बांचेगा, फिर रंगीन मिजाज़ पढ़ाकुओं को पढ़वाएगा. उसके बाद डाक व्यवस्था के तहत हमारे पास पहुंचाएगा. यह अच्छा है और बुरा भी. हमें देर से देखने को मिलता है. यह प्रतिक्रिया उसी देर का फल है... आपने किसी अंक में जब तोप मुक़ाबिल हो के तहत महंगाई का ज़िक्र किया है. उसमें दाल, चावल समेत तमाम सब्ज़ियों के महंगे होने पर चिंता है. यह सुलेख उसी महंगाई पर टिका है. कृपया इसे संजीदगी से पढ़िएगा और हो सके तो सुबुद्धिवादी संभ्रांत शहरियों को पढ़ाकर उन्हें उकसाइएगा कि वह भी अपनी राय दें. इस महंगाई का एक आंखन देखी क्षेपक है, उसे सुन लें.

इस (इस पर जोर दे रहा हूं) महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान हलाकान भाजपा है. एक दिन (तारीख़ याद नहीं है)जंतर-मंतर से गुज़र रहा था तो वहां हमने कमल छाप लोगों की भीड़ देखी. रुक कर देखने लगा तो कई ज़रूरी और ग़ैर ज़रूरी चीज़ें दिखाई पड़ गईं. वहां पुरुष नेता थे. महिला नेता थीं, कार्यकर्ता थे और चीख रहे थे. नेताओं की आंख पर चश्मा था. महिलाएं मेकअप में थीं और वे अजीब-अजीब चीज़ें दिखा रही थीं. महिलाएं बैगन दिखाने लगीं. पुरुषों के हाथ में लौका था, कोई मूली पकड़े खड़ा था. हमने सोचा ये हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं-कर रही हैं. पर जब पीछे पलट कर देखा तो कैमरा वाले एक आंख दाबे अपने-अपने हलबा हथियार के साथ लामबंद दिखे. दूसरे दिन अख़बारों और चैनलों में खाते-पीते घर की महिलाओं की फोटो दिखाई जाने लगी. वही हू-ब-हू, वही बैगन दिखाते हुए. गरज यह कि जो वह दिखा रही थीं-दिखा रहे थे, उसके अलावा भी उनके खीसे में, उनके बैग में कुछ सामान था, जो दिखाई पड़ रहा था. वह था बोतलबंद पानी, तरह-तरह के नमकीन...(दिल्ली की सभ्यता में यह दर्ज़ है कि अगर इस तरह का कोई जलसा-जुलूस हो तो प्यास के लिए शुद्ध (?) बंद बोतल पानी और पेट के लिए हल्दी, जीरा, कलौंजी का नमकीन ज़रूरी होता है. हमने एक देवी जी को रोका.

मिट्टी जैसा नामाकूल उत्पाद जब कारखाने में ईंट की शक्ल में पहुंचता है तो आधा किलो मिट्टी की क़ीमत चार रुपये हो जाती है (प्रति ईंट क़ीमत है चार रुपये). सीमेंट, लोहा, दवा, काग़ज़, सौंदर्य प्रसाधन, तेल वग़ैरह जब ब्रांड के लेबल से सजे-धजे पैकेट में बाहर आने लगते हैं तो आम जनता को इसकी जानकारी शाहरुख़ ख़ानों, माधुरी दीक्षितों और पता नहीं किस-किसके जरिये होती है.

आप कहां से आई हैं? करमपुरा से. कैसे आईं?

टैंपो से. यह क्या पी रही हैं? बिसलरी.

कितने की है? बारह रुपये की. क्या खा रही हैं?

नमकीन. कितने का है? दस रुपये का. कितने ग्राम है?

नहीं मालूम.

रुको बताती हूं...

संपादक जी, इस क्षेपक की कथा में ही महंगाई का निचोड़ है. ज़रा इसे ग़ौर से समझें. समूची दुनिया का उत्पाद दो मुक़ाम से निकलता है. एक खलिहान से, दूसरा कारखाने से. इस वक़्त भारत में जिस महंगाई का ज़िक्र हो रहा है, वह खलिहान के उत्पाद की है. कारखाने के उत्पाद का न तो ज़िक्र हो रहा है, न ही उस पर बहस. मज़े की बात तो यह है कि इस महंगाई का विरोध करने वाले लोग प्रत्यक्ष रूप से कारखाने के उत्पाद का समर्थन कर रहे हैं. उदाहरण के लिए भारतीय समाज में पानी पूछना तमीज और तहजीब का पुश्तैनी रवायत रहा है. वह पानी तालाब, झील, कुंआ, नल से निकल कर जब कारखाने की जद में आता है तो उस पानी की क़ीमत गांव के दूध से भी ज़्यादा हो जाती है (गांवों में दूध 10 रुपया लीटर है और शहर में एक बोतलबंद पानी की कीमत 12 से 16 रुपये तक है). इतना ही नहीं, उस पानी में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है. इस महंगाई पर राजनीति नहीं गरमाती, न ही जन संचार के माध्यमों में इसका ज़िक्र होता है. क्यों? क्योंकि, यह पानी बनाने वाले स्थापित संस्थान से आते हैं और इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा जन संचार के माध्यमों पर प्रचार में जाता है. इतना ही नहीं, मिट्टी जैसा नामाकूल उत्पाद जब कारखाने में ईंट की शक्ल में पहुंचता है तो आधा किलो मिट्टी की क़ीमत चार रुपये हो जाती है (प्रति ईंट क़ीमत है चार रुपये). सीमेंट, लोहा, दवा, काग़ज़, सौंदर्य प्रसाधन, तेल वग़ैरह जब ब्रांड के लेबल से सजे-धजे पैकेट में बाहर आने लगते हैं तो आम जनता को इसकी जानकारी शाहरुख ख़ानों, माधुरी दीक्षितों और पता नहीं किस-किसके जरिये होती है. और, गांव की लछमीना जब टीवी पर देखती है कि ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु की ख़ूबसूरती का राज फलां साबुन है तो वह दिन भर की जांगरतोड़ कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर सौदा सुलफी लेते समय वही खास साबुन ख़रीदती है. असल में दो हज़ार प्रतिशत के फ़ायदे वाला यह उत्पाद लछमीनाओं को लूटता है और उस लूट का बड़ा हिस्सा ये परदे की हसीनाएं लेती हैं और काफी कुछ जनसंचार के माध्यमों के पेट में जाता है. सवाल यह है कि इनका विरोध क्यों नहीं किया जाता!

किसान का आलू, चावल, चना औने-पौने भाव निकल कर जब कारखाने से चिप्स, कुरकुरे और भुजिया बन कर बाहर आता है तो उस पर 700 प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफ़ा लिया जाता है, क्योंकि उस कुरकुरे को माधुरी दीक्षित या रानी मुखर्जी बेचती हैं...

संपादक जी, जब आपने भी उसी महंगाई पर तोप चलाई तो हम हलाकान हुए. इसलिए कि हम व्यक्तिगत रूप से आपसे वाक़िफ़ रहे हैं. आप गांधी, जे पी की लाइन वाले रहे हैं, इसलिए यह ख़त-व-किताबत करना पड़ा. आख़िर में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं (आपके मार्फत उन तमाम संभ्रांत शहरियों से) कि आप चौबीस घंटे में कितना उत्पाद खलिहान का प्रयोग करते हैं और कितना कारखानों का? आज हमारी जीवन पद्धति ही कारखाने की गुलाम बनकर रह गई है. सुबह सोकर उठने से कारखाने की तरफ़ भागते हैं टूथपेस्ट से लेकर झागवाला तक, क्रीज से लेकर चमकदार जूते तक, कलम से लेकर फोन तक. कितना गिनाएं? अब कोई महिला बैगन दिखाती है, फोटो खिंचवाती है तो हमें हंसी आती है. हमें उस किसान का चेहरा याद आता है, जो बैगन की खेती करता है. हमने कांग्रेस से कहा है कि इस महंगाई को कम करना है तो उस महंगाई को रोको, जो कारखाने से आ रही है.

feedback@chauthiduniya.com

शोधकर्ताओं ने रिश्ते की संतुष्टि का स्तर मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पैनइर डायडिक एडजस्टमेंट स्केल का उपयोग किया. इसके लिए सेवानिवृत्ति ले चुके 511 वृद्ध जोड़ों का चयन किया गया.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सवाल पूछो, ज़िंदगी बदलो

चौथी दुनिया ने पिछले अंक से अपने पाठकों एवं आम लोगों तक सूचना का अधिकार क़ानून की जानकारी पहुंचाने के रूप में एक नई पहल की है. चौथी दुनिया आपको देगा वह ताक़त, जिससे आप पूछ सकेंगे सही सवाल. क्योंकि, एक सही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. हम आपको बताएंगे कि कैसे सूचना का अधिकार क़ानून का इस्तेमाल कर आप दिखा सकते हैं घूस को घूंसा. अगर आपको इस क़ानून के इस्तेमाल से संबंधित कोई परेशानी हो या कोई सुझाव चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं.

सूचना कौन देगा

प्रत्येक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का पद होता है. आपको अपनी अर्जी उसके पास दाख़िल करनी होगी. यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह उस विभाग के विभिन्न भागों से आप द्वारा मांगी गई जानकारी इकट्ठा करे और आपको प्रदान करे. इसके अलावा कई अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है. उनका कार्य जनता से आरटीआई आवेदन लेना और पीआईओ के पास भेजना है.

आरटीआई आवेदन कहां जमा करें

आप अपनी अर्जी–आवेदन पीआईओ या एपीआईओ के पास जमा कर सकते हैं. केंद्र सरकार के विभागों के मामलों में 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है. मतलब यह कि आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई काउंटर पर अपना आरटीआई आवेदन और शुल्क जमा करा सकते हैं. वहां आपको एक रसीद भी मिलेगी. यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वह उसे संबंधित पीआईओ के पास भेजे.

यदि पीआईओ या संबंधित विभाग आरटीआई आवेदन स्वीकार न करने पर

ऐसी स्थिति में आप अपना आवेदन डाक द्वारा भेज सकते हैं. इसकी औपचारिक शिक़ायत संबंधित सूचना आयोग को भी अनुच्छेद 18 के तहत करें. सूचना आयुक्त को उस अधिकारी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाने का अधिकार है, जिसने आवेदन लेने से मना किया था.

पीआईओ या एपीआईओ का पता न चलने पर

यदि पीआईओ या एपीआईओ का पता लगाने में कठिनाई होती है तो आप आवेदन विभागाध्यक्ष को भेज सकते हैं. विभागाध्यक्ष को वह अर्जी संबंधित पीआईओ के पास भेजनी होगी.

अगर पीआईओ आवेदन न लें

पीआईओ आरटीआई आवेदन लेने से किसी भी परिस्थिति में मना नहीं कर सकता. भले ही वह सूचना उसके विभाग/कार्यक्षेत्र में न आती हो. उसे अर्जी स्वीकार करनी होगी. यदि आवेदन–अर्जी उस पीआईओ से संबंधित न हो तो वह उसे उपायुक्त पीआईओ के पास पांच दिनों के भीतर अनुच्छेद 6(3) के तहत भेज सकता है.

क्या सरकारी दस्तावेज़ गोपनीयता क़ानून 1923 सूचना के अधिकार में बाधा है नहीं. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 22 के अनुसार सूचना का अधिकार क़ानून सभी मौजूदा क़ानूनों का स्थान ले लेगा.

अगर पीआईओ सूचना न दें

एक पीआईओ सूचना देने से मना उन 11 विषयों के लिए कर सकता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद आठ में दिए गए हैं. इनमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से हानिकारक सूचना, विधायिका के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आदि. सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन 18 अभिकरणों की सूची दी गई है, जिन पर यह लागू नहीं होता. हालांकि उन्हें भी वे सूचनाएं देनी होंगी, जो भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हों.

क्या प्रथम/द्वितीय अपील की फीस है

प्रथम अपील/द्वितीय अपील की कोई फीस नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने फीस का प्रावधान किया है.

क्या फाइल नोटिंग मिलता है

फाइलों की टिप्पणियां (फाइल नोटिंग) सरकारी फाइल का अभिन्न हिस्सा हैं और इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जा सकती हैं. केंद्रीय सूचना आयोग ने 31 जनवरी 2006 के अपने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है.

सूचना क्यों चाहिए, क्या उसका कारण बताना होगा

बिल्कुल नहीं. कोई कारण या अन्य सूचना केवल संपर्क विवरण (नाम, पता, फोन नंबर) के अतिरिक्त देने की ज़रूरत नहीं है. सूचना क़ानून स्पष्टतः कहता है कि प्रार्थी से संपर्क विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा.

यदि आपने सूचना कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना नीचे लिखे पते पर भेजें, हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेलः rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

न उम्र की सीमा हो...

वेलेंटाइन डे युवा जोड़ों के लिए हो सकता है, लेकिन प्यार उम्र के साथ-साथ और मज़बूत होता है. शायद इसीलिए कहा जाता है कि प्यार न उम्र देखता है और न मजहब. यह उस शोध का निष्कर्ष है, जिसे कनाडा में किया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ मोट्रियल के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि वृद्ध जोड़े प्यार करने में युवा जोड़ों से आगे रहते हैं. शोध के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद वृद्ध जोड़ों को अपनी लव लाइफ में समकक्षों के मुक़ाबले अधिक संतुष्टि का अनुभव होता है. शोधकर्ताओं ने रिश्ते की संतुष्टि का स्तर मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पैनइर डायडिक एडजस्टमेंट स्केल का उपयोग किया. इसके लिए सेवानिवृत्ति ले चुके 511 वृद्ध जोड़ों का चयन किया गया. शोध का नेतृत्व यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट गिल्स ट्रूडले ने किया. उन्होंने पाया कि वृद्ध जोड़ों ने 119 से 120 प्वाइंट अर्जित किए, जबकि उस स्केल पर औसतन कनाडा के लोगों ने 114 प्वाइंट ही अर्जित किए. ट्रूडले के मुताबिक़, यह विश्व में इस तरह की पहली स्टडी है, जिसमें वृद्ध जोड़ों की लव लाइफ की संतुष्टि को मापा गया.

हालांकि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई शोध हुए, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि वृद्ध जोड़े अपनी लव लाइफ से अधिक संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हाल में हुआ शोध वृद्ध जोड़ों में उच्च संतुष्टि स्तर को प्रमाणित करता है. ट्रूडले ने कहा कि वृद्ध जोड़ों में तलाक कम होना इस बात को साबित करता है कि वे अपने संबंध को लेकर युवा जोड़ों की अपेक्षा अधिक ख़ुश रहते हैं. वृद्ध जोड़े काफ़ी ख़ुश हैं और उनके बच्चे भी सेटल्ड हो चुके हैं. शोधकर्ताओं ने कहा कि कम्युनिकेशन किसी भी संबंध के लिए महत्वपूर्ण होता है.

सेक्स जीन से तय होता है

शरीर का एक जीन तय करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा नर होगा या मादा. यह कहना है जर्मनी के वैज्ञानिकों का. उन्होंने यह भी कहा कि इस जीन को सुला कर नारी को नर और जगाकर नर को नारी बनाया जा सकता है. जर्मनी में हाइडेलबेर्ग स्थित यूरोपियन मॉलेक्युलर बायोलॉजी लेबोरेट्री के वैज्ञानिकों ने पाया कि एक जीन फॉक्स एल-2, जो यदि शांत या निष्क्रिय रहे तो भ्रूण नर बनता है और यदि यही जीन सक्रिय हो जाए तो भ्रूण मादा यानी नारी बनता है. इतना ही नहीं, यदि नारी में जाग रहे इस जीन को फिर से सुला दिया जाए तो नारी भी फिर से नर बन जाएगी. एक वयस्क मादा चूहे में इस जीन को निष्क्रिय कर देने पर यही हुआ. मादा धीरे-धीरे नर बनने लगी. उसकी ओवरी यानी डिंबाशय की कोशिकाएं टेस्टीस यानी अंडकोष की कोशिकाओं में बदलने लगीं.

इस अनोखी खोज का एक और अर्थ है. प्रकृति शुरू-शुरू में हर भ्रूण को नर ही बनाती है. नारी तो वह तब बनता है, जब जीन फॉक्स एल-2 जाग जाता है और अपना जादू चलाने लगता है. हालांकि इससे अब तक की इस मान्यता का खंडन होता है कि नारी ही मनुष्य का सबसे सामान्य संस्करण है, नर बनाने के लिए प्रकृति को अलग से प्रयास करना पड़ता है. हाइडेलबेर्ग के वैज्ञानिकों की टीम के जर्मन सदस्य मथियास ट्रायर कहते हैं, हम जानते हैं कि नारी के जीनोम में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नर का बनना एक्स के साथ जुड़े वाई क्रोमोसोम द्वारा तय होता है, जो हमें पिता से मिलता है. ऐसा वाई क्रोमोसोम में एक इकलौते जीन के कारण होता है, जो भ्रूण में अंडकोष बनने की क्रिया को आरंभ करता है.

राशिफल

1 मार्च–7 मार्च 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): पारिवारिक समस्या या गृह कलह का सामना करना पड़ सकता है. रोग अथवा शत्रु से सचेत रहें. धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी. संबंधित अधिकारी के कृपापात्र बनेंगे. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): पड़ोसी या किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. कोई सुखद समाचार मिल सकता है. मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी करेंगे. व्यवसायिक प्रगति के लिए भागदौड़ रहेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून): रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. उदर विकार या त्वचा संबंधी रोग की आशंका है. व्यक्ति विशेष से तनाव मिल सकता है. यात्रा में अपनी वस्तुओं के प्रति सचेत रहें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): आपकी राशि पर शनि होने के कारण वायु विकार और पैरों में दर्द की आशंका है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. महादेव की उपासना आपके लिए हितकारी होगी. आर्थिक पक्ष में व्यस्तता रहेगी. नए अनुबंध की संभावना है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. व्यवसायिक यात्रा हो सकती है. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. भगवान शिव की उपासना लाभप्रद होगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होंगे. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. भौतिक उपलब्धि के योग हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. राजनेता का सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. निजी संबंधों में निकटता आएगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है. स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें. व्यवसायिक मामले में लाभ मिलेगा. नए अनुबंध का योग है. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. उपहार-सम्मान का लाभ मिल सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): विरोधी सक्रिय रहेंगे, परंतु परास्त होंगे. यात्रा सुखद एवं लाभदायी होगी. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. निजी सुख में वृद्धि होगी. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा. व्यर्थ की उलझनें रहेंगी. पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. संतान के व्यवहार से चिंतित रहेंगे. व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा. मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह स्थिति ख़ास मायने रखती है. शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की.

भारत-बांग्लादेश संबंध और पूर्वोत्तर का मुद्दा

दिनकर कुमार

काफ़ी उम्मीदों और ढेर सारी संभावनाओं के बावजूद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अपेक्षित सुधार नहीं आ सका है. भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से दोनों देश एक-दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहे हैं. इसके बावजूद अविश्वास और संदेह की खाई दोनों देशों के बीच हमेशा मौजूद रही. शेख हसीना वाजिद पहले भी सत्ता में थीं. तब भी उन्हें और उनकी पार्टी को लगातार पाकिस्तान समर्थित धार्मिक कट्टरपंथी ताक़तों से जूझना पड़ा था. उन ताक़तों से, जो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश करती रही हैं.

हाल में भारत दौरे पर आईं शेख हसीना वाजिद ने वादा किया कि वह अपने देश में धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद को ख़त्म करेंगी और शांति एवं न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक परिवर्तन के नए युग की शुरुआत करेंगी. हसीना का यह बयान सकारात्मक है और हाल के कुछ महीनों में उन्होंने बांग्लादेश के बदले हुए रुझान के संकेत भी दे दिए हैं. शेख हसीना बांग्लादेश की घरेलू और विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन कर रही हैं. उन्होंने वादा किया कि वह भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में विश्वास रखती हैं. दोनों देशों के बीच पांच महत्वपूर्ण समझौते हुए. इसे द्विपक्षीय संबंधों के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. शेख हसीना के रवैये से संकेत मिल रहा है कि अब बांग्लादेश सरकार शांति और विकास को प्राथमिकता दे रही है. वर्तमान शासन के तहत उग्रवाद के पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं रह गया है.

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह स्थिति ख़ास मायने रखती है. शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की. चूंकि बांग्लादेश की नीति का सबसे गहरा प्रभाव इन्हीं राज्यों पर पड़ता है. पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज़मीनी सच्चाइयों की अधिक जानकारी है और उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखने का प्रयास भी किया. मुख्यमंत्रियों ने बांग्लादेश के प्रमुख शहरों के साथ वायु, रेल एवं बस संपर्क बहाल करने पर जोर दिया. पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन से घिरे हैं. इन देशों के साथ भारत का एकमात्र संपर्क असम से होकर ही संभव हो सकता है. यह क्षेत्र दुर्गम है, जहां पहाड़ियां और जंगल हैं. बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री फारुख खान ने हाल में कहा है कि अगर भारत एवं अन्य पड़ोसी देश चटगांव बंदरगाह का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए उनकी सरकार सहर्ष अनुमति देने के लिए तैयार है. दक्षिणी त्रिपुरा से चटगांव बंदरगाह की दूरी सिर्फ़ 75 किलोमीटर है. भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देश परिवहन ख़र्च और समय बचाने के लिए इस बंदरगाह का इस्तेमाल करना चाहते हैं. भारत-बांग्लादेश के बीच जल परिवहन संबंधी संधि की अवधि 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दी गई है. इस संधि के अनुसार, चार जल परिवहन मार्गों पर दोनों देश अपने मालवाहक जहाजों का परिचालन कर सकते हैं. उक्त चार मार्ग हैं कोलकाता-पांडु, कोलकाता-करीमगंज, राजशाही-धुलियान और करीमगंज-पांडु. बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख शहरों के बीच औसत दूरी 30 किमी से 200 किमी है. शेख हसीना के साथ बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों के ख़िलाफ़ बांग्लादेश सरकार के सख्त रवैये की सराहना की और कहा कि इस तरह बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में शांति बहाली करने में मदद मिलेगी.

बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में अवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बीएनपी के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को जिस तरह भारी मतों से पराजित किया, उससे बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुआ. यह परिवर्तन भारत के पक्ष में माना जा रहा है. आम चुनाव में स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश की जनता ने स्थिर, विकसित और जवाबदेह बांग्लादेश के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जनता ने जमात को ख़ारिज़ कर दिया और उसके तमाम उम्मीदवार बुरी तरह पराजित हुए. जनता ने धार्मिक राजनीति और कट्टरपंथ को ठुकराते हुए लोकतंत्र के पक्ष में मतदान किया.

शेख हसीना की जीत भारत के नज़रिए से सकारात्मक घटना मानी गई. इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार की चुनौतियां ख़त्म नहीं हो गई हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते को पटरी पर लाना इतना आसान नहीं होगा. जहां तक बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति का सवाल है, भारत के साथ संबंध बनाना हमेशा एक संवेदनशील मसला रहा है. शेख हसीना के भारत दौरे के ठीक पहले विपक्षी दल बीएनपी की नेता खालिदा जिया ने उन्हें चेतावनी दी कि वह बांग्लादेश के हितों के साथ किसी तरह का समझौता न करें, वरना बीएनपी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी. खालिदा जिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे शेख हसीना की सरकार के ख़िलाफ़ जनांदोलन छेड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सरकार देश के हितों के साथ समझौता कर रही है. जिया और बांग्लादेश के प्रचार माध्यम जनता को बता रहे हैं कि भारत दौरे से हसीना ने कुछ भी हासिल नहीं किया. शेख हसीना के लिए कई चुनौतियां हैं. उन्हें जनता को विश्वास में लेकर द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में ठोस क़दम बढ़ाना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

सक्रिय आतंकी और उग्रवादी संगठन

बांग्लादेश में कई ऐसे आतंकी एवं उग्रवादी संगठन हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं. आतंकी वारदातों में कई बार उनकी सीधी भागीदारी होती है. कई बार वे सहयोगी की भूमिका में रहते हैं. इन संगठनों के संबंध भारत एवं बांग्लादेश में सक्रिय कई अन्य आतंकी संगठनों से भी हैं, जिनमें अलक़ायदा, तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, लश्करे तैयबा एवं उल्फा आदि प्रमुख हैं.

हूजी : इस संगठन की स्थापना 1992 में हुई थी. बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और भारत में सक्रिय हूजी पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से कई आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दे चुका है. 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हुए हमले की ज़िम्मेदारी इसने ली थी. इसके अलावा लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) से भी इसके नज़दीकी रिश्ते हैं. सूत्रों के मुताबिक़, हूजी उल्फा के लिए ट्रेनिंग कैंप का संचालन भी करता है. हाल के दिनों में इस संगठन ने इस साल भारत में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप, राष्ट्रमंडल खेलों और आईपीएल में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की धमकी दी है.

जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश: इसकी स्थापना 1998 में हुई थी. ग़ैर सरकारी संगठनों पर लगातार हमलों के बाद सरकार ने फरवरी 2005 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इसी साल अगस्त में देश के विभिन्न इलाक़ों में 500 बम विस्फोट करके इसने अपनी ताक़त का एहसास करा दिया.

द जाग्रत मुस्लिम जनता बांग्लादेश (जेएमजेबी): इस संगठन की स्थापना भी 1998 में हुई थी. इसके संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से रहे हैं. जेएमजेबी को उल्फा का सहयोगी संगठन भी माना जाता है. हालांकि अब तक इसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिल पाया है. बांग्लादेश सरकार द्वारा इसे 2004 में प्रतिबंधित कर दिया गया था. हालांकि, प्रमुख राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ इसके नज़दीकी रिश्ते हैं.

पूर्व बांग्ला कम्युनिस्ट पार्टी (पीबीसीपी): पूर्व बांग्ला कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश में सक्रिय माओवादी संगठनों में से एक है. इसका गठन 1968 में बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन के बाद हुआ था. जिया-उर-रहमान के सैन्य शासन के दिनों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था. लेकिन हाल के दिनों में, ख़ासकर 2002 के बाद इसकी गतिविधियों में एक बार फिर तेज़ी दिखाई दी है.

इस्लामी छात्र शिविर (आईसीएस): इस्लामी छात्र शिविर को जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश का छात्र संगठन माना जाता है. इसका गठन 1941 में हुआ था. यह देश में इस्लामिक शिक्षा पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिए संघर्षरत है.

अपने शिरडी प्रवास के दौरान साईं बाबा ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का कई बार पुरज़ोर खंडन किया.

साई नाम दुःखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है : सुरेश वाडकर

विकास कपूर

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे सुरेश वाडकर के पिता ने उनका नाम सुरेश यानी सुरों का ईश्वर बहुत सोच-समझ कर रखा था. उनके पिता उन्हें गायन के क्षेत्र में एक चमकता सितारा बनाना चाहते थे. दस वर्ष की छोटी सी आयु में सुरेश को प्रसिद्ध गायक पंडित जियालाल के गुरुकुल में संगीत की शिक्षा के लिए भेजा गया. 1974 में सुरेश को प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव ने फ़िल्म गुमान में सीने में जलन गीत गाने का मौक़ा दिया, लेकिन सुरेश को असली पहचान राजश्री की फ़िल्म *पहेली* में प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन द्वारा स्वर बद्ध किए गीत भिश्ती करे टिपुर-टिपर से मिली. फ़िल्म *राम तेरी गंगा मैली* के गीत गंगा हमारी कहे बात ये रोते-रोते ने सुरेश को रातोरात स्टार बना दिया. *लगी आज सावन की*...(चांदनी), *परदेसी-परदेसी जाना नहीं*...(राजा हिंदुस्तानी), *चप्पा-चप्पा चरखा चले*...(माचिस) एवं *अनार दाना-अनार दाना* ...(हिना) आदि सुरेश के प्रसिद्ध गीतों में से हैं. स्वर कोकिला लता मंगेशकर सुरेश की दिलकश आवाज़ की दिल खोलकर सराहना करती हैं. सुरेश ने लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, आर डी बर्मन, हृदय नाथ मंगेशकर, रविंद्र जैन, ए आर रहमान, विशाल शेखर एवं दिलीप सेन-समीर सेन आदि प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया. पेश है साई बाबा के सच्चे भक्त सुरेश वाडकर से बातचीत के प्रमुख अंश:

ॐ साई राम सुरेश जी..

ॐ साई राम

सुना है, आप प्रतिदिन साई बाबा की पूजा करते हैं, अपनी भक्ति के बारे में कुछ बताइए.

साई बाबा की भक्ति मन को अपार सुख देती है. यह सच है कि मैं प्रतिदिन साई बाबा की पूजा करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि दु:खों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है साई नाम. अहमद नगर ज़िले के शिरडी गांव में अवतरित साई बाबा महाराष्ट्र के आराध्य देव हैं. अब तो बाबा की भक्ति का प्रचार-प्रसार सारी दुनिया में हो गया है.

बहुत कम समय में साई बाबा शिरडी के गांव से निकल कर सारी दुनिया में छा गए. साई भक्ति के इस प्रचार-प्रसार में आप किसका योगदान मानते हैं?

फ़िल्म और टेलीविज़न के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. मनोज साहब की फ़िल्म शिरडी के साई बाबा के बाद भारत के कोने-कोने में साई महिमा का प्रचार-प्रसार हुआ. उसके बाद ऑसिम खेत्रपाल की फ़िल्म शिरडी साई बाबा ने भी लोगों को बाबा की तरफ़ आकर्षित किया. इस बीच बाबा की महिमा को जन-जन तक पहुंचाने वाले बहुत सारे एलबम भी रिलीज़ हुए. लोग साई भक्ति में गुनगुनाने लगे. लेकिन, इन सबसे अधिक भक्तों पर साई बाबा की कृपा. जो भी भक्त अपनी फ़रियाद लेकर समाधि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, वह दयालु साई बाबा की कृपा से ख़ाली हाथ नहीं लौटता. जहां जाकर भक्तों की हर आस पूरी होती है, उस स्थान का प्रचार-प्रसार होना तो स्वाभाविक है.

साई बाबा के फकीरी भरे जीवन पर आपकी क्या राय है?

आपने कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ आई हो. साई बाबा वास्तव में समुद्र के समान थे, जिन्हें दिखावे (बाढ़) की ज़रूरत ही नहीं थी. जो भी उनके समीप गया, वह झोली भरकर लौटा. फकीर ही असली बादशाह हैं. उनका फकीरी भरा जीवन, सादगी और अन्य धर्मगुरुओं की तरह लंबे-लंबे उपदेश न देना ही भक्तों को उनकी ओर आकर्षित करता है.

साई बाबा अपने भक्तों को उपदेश किस प्रकार दिया करते थे?

श्री साई सच्चरित्र में कई जगह इस बात का उल्लेख किया गया है कि साई बाबा की उपदेश शैली बिल्कुल उनकी तरह ही निराली थी. वह प्राय: किसी को उपदेश देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते थे और उनके उपदेश बहुत ही प्रैक्टिकल होते थे.

ॐ साई राम...

अगले अंक में
दीपक बलराज विज के साई अनुभव

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

पिछले सप्ताह का विषय:

श्रद्धा और सबुरी कहकर साई बाबा हमें क्या सिखाना चाहते थे?

आपके जवाब:

1. पांच हज़ार वर्ष पहले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को श्री मद्‍भागवत गीता में कर्म की शिक्षा देते हैं. आज के युग की आवश्यकता को देखते हुए इस युग के श्रीकृष्ण अर्थात साई बाबा अपने भक्तों को श्रद्धा और सबुरी की शिक्षा इसलिए देते हैं, जिससे लोग कर्म में श्रद्धा के साथ सब्र भी रखें. फल अवश्य मीठा मिलेगा.

- ***निखिल शर्मा***, गाज़ियाबाद-उत्तर प्रदेश (सर्वश्रेष्ठ विचार)

2. श्रद्धा और सबुरी कहकर साई बाबा हमें सच्चाई की राह पर चलने के साथ-साथ धैर्य का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है.

- ***पायल गुप्ता***, *रामपुर-उत्तर प्रदेश*

3. हम अपने हर कार्य को भक्ति और पूजा के समान पवित्र मानें तथा उसके फल की आशा न करके साई कृपा की प्रतीक्षा करें. इसीलिए साई बाबा ने हमें श्रद्धा और सबुरी की शिक्षा दी.

- ***राज पांडे***, *हाज़ीपुर-बिहार*

इस सप्ताह का विषय:

साई भक्ति प्रचार-प्रसार में फिल्मों का कितना योगदान है?

आप अपने विचार sai4world@gmail.com **पर अपने नाम और पते के साथ मेल करें अथवा *शिरडी साईबाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नंबर-1, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई-58 के पते* पर डाक द्वारा भेजें.**

सफलता की राह में अंध विश्वास बाधा है

अंध विश्वास जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा है. मनुष्य ने संभवत: सभ्यता के विकास से बहुत पहले ही अंध विश्वास के प्रतीकों की रचना कर ली और सभ्यता के चरम विकास के बाद भी अंध विश्वास मनुष्य जाति के साथ-साथ पहले से भी बहुत अधिक दृढ़ होकर चलने लगा. बिल्ली का रास्ता काट जाना, छींक आ जाना, घर से निकलते वक्त टोक देना, दरवाज़े पर खाली बाल्टी देख लेना आदि-आदि अंधविश्वास के न जाने कितने प्रतीक हैं. हिंदू धर्म के विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में जगह-जगह अंध विश्वास के ऐसे स्वरूपों का उल्लेख किया गया है. यहां यह कहना भी आवश्यक होगा कि विश्व के लगभग सभी प्रचलित धर्मों और धर्म पुस्तकों में अंध विश्वास के प्रतीकों को अपनी-अपनी भाषा में एवं अपने-अपने तरीक़े से गढ़ा और कहा गया है.

लेकिन शिरडी के सद्‍गुरु साई बाबा इस प्रकार के किसी भी अंध विश्वास और उसके प्रतीकों को जीवन की सफलता में बाधा मानते थे. अपने शिरडी प्रवास के दौरान साई बाबा ने कई बार इन अंधविश्वासों का पुरज़ोर खंडन किया. इसका एक उदाहरण साई बाबा के परम भक्त शामा को तब मिला, जब एक दिन अपने घर से देवा साई बाबा के दर्शन के लिए निकलते वक्त द्वार पर रखी खाली बाल्टी देखकर वह मायूस हो गए. उन्हें लगा कि अब देवा का कृपाशीष उन्हें नहीं मिलेगा. मन में गहराई से जमे अंध विश्वास की भावना से ग्रसित शामा परिवारजनों पर अपनी मायूसी और क्रोध उतारने ही वाले थे कि उन्हें शिरडी के नाथ सद्‍गुरु साई बाबा अपनी भिक्षा की टमरेल (भिक्षापात्र) उठाए आते दिखाई दिए. शामा आशीष पाने के लिए बाबा की ओर भागे. बाबा तो अंतर्यामी हैं. शामा को देखते ही पूर्व में घटी सारी घटना के बारे में जान गए. बाबा ने शामा को अपनी खाली टमरेल दिखाकर कहा, शामा! यदि भिक्षा मांगने जा रहा हूं तो भरी से खाली टमरेल अच्छी है. उसी प्रकार यदि पानी भरने जा रहे हो तो भरी से खाली बाल्टी अच्छी है. शामा को अपनी भूल का एहसास हो गया. उसने कहा, देवा! आज तक मैं अंध विश्वास के इन प्रतीकों में अपना जीवन व्यर्थ करता रहा, परंतु सच यह है कि यह सब केवल मनुष्य द्वारा स्थापित भ्रम है. आज द्वार पर खाली बाल्टी देखने के बाद भी मुझे अपने घर के द्वार पर ही अपने देवा के दर्शन हुए. इससे सिद्ध होता है कि इन अपशकुनों का कोई मायने नहीं है. आज के बाद मैं कभी इन व्यर्थ की बातों से भ्रमित नहीं होऊंगा.

मन में भीतर गहराई से जमे इन अपशकुनों के कारण कई बार हम अपने महत्वपूर्ण काम को पूरे उत्साह से नहीं कर पाते. जैसे- राजू एक बहुत मेधावी विद्यार्थी है और परीक्षा में हमेशा अव्वल रहता है, परंतु बारहवीं कक्षा की गणित की परीक्षा के लिए निकलते वक्त उसकी छोटी बहन ने छींक दिया. परीक्षा का समय हो गया था, रुकना संभव नहीं था. सशंकित और भयभीत मन के साथ राजू परीक्षा हाल पहुंचा. उसे पहले से ही इस बात का पूर्वाभास हो रहा था कि आज का पेपर अच्छा नहीं होगा. भ्रम और वहम के कारण वह प्रश्नपत्र देखकर घबरा गया और जिन सवालों को हल करने का उसने काफी अभ्यास किया था, उन्हीं के सूत्र भूल गया और पेपर ख़राब हो गया. इस वजह से बारहवीं की परीक्षा में वह अव्वल नहीं आ सका. साई बाबा की शामा को दी हुई शिक्षा को याद करके हमें अपने मन में पलते अंध विश्वास का स्थायी उपचार करना ही चाहिए. तब परिश्रम से प्राप्त सफलता के द्वार भी खुलेंगे और साई कृपा भी सदा हमारे साथ होगी.

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का साई भक्त परिवार पिछले कई वर्षों से समाज के अचेतन मन में साई की सच्ची भक्ति की चेतना जगाने का पुनीत कार्य कर रहा है. हम इस पावन यज्ञ में आपका भी आह्वान करते हैं. आइए और अपनी भक्ति की समिधा श्री साई चरणों में अर्पित करने के अधिकारी बनिए. साई भक्त परिवार में शामिल होकर अपनी साई भक्ति को और अधिक दृढ़ करने तथा सद्‍गुरु साई समर्थ की कृपा का अधिकारी बनने के लिए आप अपना नाम साई भक्त............. और फोन नंबर.......... कृपया 09999989427 पर एसएमएस करें.

असीम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj

Sai Hills

Sai Vihar Township

Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

महाशिवरात्रि भूतभावन भगवान शिव के लिंग रूप में प्राकट्य का दिन माना जाता है. इस जन मान्यता को क्षण भर के लिए अलग करके देखें तो शिव का अर्थ होता है कल्याण.

गांधी जी और बटक मियां

अनंत विजय

लंदन से दक्षिण अफ़्रीका लौटते वक़्त राष्ट्रपिता गांधी ने जो संवाद लिखा था, वह बाद में हिंद स्वराज के नाम से पुस्तकाकार भी छपा. इस पुस्तक के प्रकाशन के सौ साल पूरे होने पर बुद्धिजीवियों के बीच जमकर बहस–मुहाबिसा हुआ. हिंद स्वराज का प्रकाशन आंशिक और पूर्ण रूप से पत्र–पत्रिकाओं में हुआ और नई पीढ़ी को एक बार फिर से राष्ट्रपिता गांधी को जानने– समझने का अवसर मिला. इसके पहले राजकुमार हिरानी की फ़िल्म लगे रहो मुन्नाभाई से भी नई पीढ़ी में गांधी को पढ़ने– समझने की ललक पैदा हुई थी, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानने–समझने के इस शोरगुल के बीच एक बेहद अहम बात गुम सी गई. महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की और अपने दृढ़ नेतृत्व और लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता के बूते भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त भी करा लिया. लेकिन गांधी के संघर्ष में देश के लाखों लोगों का योगदान रहा. देश के एक ऐसे ही महान सपूत थे बटक मियां, जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी और राष्ट्रपिता की जान बचाने वाले बटक मियां को देश ने भुला दिया.

बात उन्नीस सौ सत्रह की है, जब बिहार में नील किसानों का आंदोलन अपने चरम पर था. अंग्रेज किसानों पर जमकर अत्याचार कर रहे थे. किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए गांधी जी मोतिहारी पहुंचे थे, जो उस वक़्त चंपारण ज़िले का मुख्यालय हुआ करता था. गांधी के वहां पहुंचने की ख़बर लगते ही मोतिहारी के इंडिगो प्लांटेशन के मैनेजर इरविन ने उन्हें जान से मारने की साजिश रची. इस साजिश के तहत ही गांधी जी के मोतिहारी पहुंचते ही इरविन उनके पास पहुंचा और उनसे अपने घर भोजन करने का आग्रह किया. साफ दिल और पारदर्शिता में यक़ीन रखने वाले गांधी जी ने इरविन का आग्रह स्वीकार कर लिया और उसके घर भोजन के लिए पहुंचे. इस बीच इरविन ने अपने बावर्ची बटक मियां को दूध में ज़हर मिलाकर गांधी जी के सामने पेश करने का हुक्म दिया. इरविन के ख़ौफ़ में बटक मियां ने दूध में ज़हर मिलाना तो मान लिया और ज़हर मिला दूध गांधी को देने पहुंच भी गए, लेकिन जब वह दूध का गिलास पकड़ा रहे थे तो फुसफुसा कर दूध में ज़हर होने की बात उन्होंने बापू को बता दी. इतना पता चलते ही बापू ने दूध पीने से इंकार कर दिया और गांधी को जान से मारने की इरविन की साजिश नाकाम हो गई. बटक मियां के इस क़दम से बापू की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. नौकरी जाने के बाद बटक मियां के दिन बेहद फटेहाली और तंगहाली में गुजरे. देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस पूरे वाकए के गवाह थे.

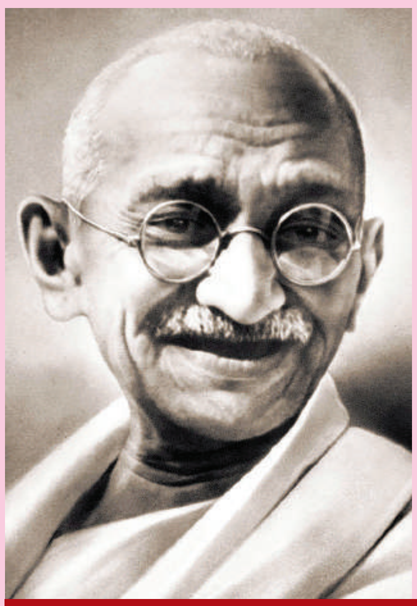

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

बटक मियां

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री–बिहार

जब देश आज़ाद हुआ और उन्नीस सौ पचास में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण पहुंचे तो लगभग तीन दशक बाद भी उन्हें बटक मियां याद थे और यह भी याद था कि बटक मियां ने बापू की जान बचाई थी. राजेंद्र बाबू ने एक जनसभा कर सार्वजनिक रूप से बटक मियां का सम्मान किया और उनकी ग़रीबी को देखते हुए चंपारण के तत्कालीन ज़िलाधिकारी को उन्हें छत्तीस बीघा ज़मीन देने का हुक्म दिया, लेकिन तामील होने के बजाय देश के राष्ट्रपति का आदेश सरकारी फाइलों में धूल चाटता रहा. बटक मियां की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें ज़मीन नहीं मिल पाई. गांधी की जान बचाने वाला देश का सपूत ज़मीन के लिए संघर्ष करता रहा और अंततः सात साल बाद उन्नीस सौ सत्तावन में उनकी मृत्यु हो गई. उनकी मृत्यु के लगभग चार साल बाद सरकार की कुंभकर्णी नींद टूटी और बटक मियां के परिवार को लगभग तीन बीघा ज़मीन पश्चिमी चंपारण और दो एकड़ ज़मीन पूर्वी चंपारण में आवंटित की गई. लगभग साठ साल बीत जाने के बाद भी अब तक देश के प्रथम राष्ट्रपति के हुक्म की पूरी तामील नहीं हो पाई है. यह मामला बिहार विधानसभा में उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद बटक मियां के परिवार को बाक़ी ज़मीन अब तक नहीं मिल सकी है.

बटक मियां का परिवार अब भी तीन दिसंबर उन्नीस सौ सत्तावन को राजेंद्र बाबू के एडिशनल प्राइवेट सेकेट्री विश्वनाथ वर्मा के खत की बिना पर उम्मीद पाले बैठा है. उस चिट्ठी में बटक मियां के बेटे जन अंसारी को यह सूचित किया गया था कि महामहिम ने बिहार सरकार को उन्हें ज़मीन देने का हुक्म दिया है. लेकिन दु:ख की बात यह है कि जन अंसारी को भी उनके जीवनकाल में यह ज़मीन हासिल नहीं हो पाई और दो हज़ार दो में उनका भी निधन हो गया. अब बटक मियां की तीसरी पीढ़ी भी ज़मीन की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी है. बिहार में इन साठ सालों में कांग्रेस, जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड से लेकर मिलीजुली सरकार भी बनी, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और सभी सरकारों ने सूबे के सपूत राजेंद्र बाबू का भी अपमान किया. आज हर साल दो अक्टूबर को हम गांधी जी को याद करते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने वाले को न हम याद करते हैं और न ही उनसे किए गए वायदे को निभाने में सरकार की कोई रुचि दिखाई देती है.

क्या अब नीतीश सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की ग़लतियां सुधारेगी या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार यूं ही दर–दर की ठोकरें खाता रहेगा और भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद के आदेश की अनदेखी उनके गृह प्रदेश में होती रहेगी?

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

गुजरात में दंगे जारी थे. नए–नए इलाक़े दंगों की आग में शामिल होते जा रहे थे. जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को भी इसकी आग ने नहीं बख्शा. अंबाजी से लेकर बलसाड तक की आदिवासी पट्टी भी झुलस गई. इस पट्टी में संघ परिवार का संगठन वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए लंबे समय से सक्रिय था. विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रमों ने भी उनके अंदर हिंसा की आग भरी थी. इतिहास में पहली बार इन दंगों में आदिवासियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया. दाहोद, उदयपुर और पंचमहल ज़िले उनकी लपेट में आ गए.

गुजरात दंगों के दौरान कहीं भी इंसानियत के पक्ष में पहल नहीं हुई, ऐसा भी नहीं था. हिंदू ब्रिगेड के आतंक के बावजूद भय से बहुत सारे हिंदुओं ने राहत में जुटी संस्थाओं और लोगों की मदद की. सघन बस्तियों में साथ–साथ रहने वाले लोगों ने मुसलमानों पर हमला करने आए लोगों को खदेड़ा भी. तलवारों के आगे अपने सीने भिड़ा दिए. कई हिंदुओं ने अपने घरों में मुसलमान साथियों को पनाह देकर उनकी ज़िंदगी बचाई. जवान मुस्लिम लड़कियों के अनाथ होने पर बहुत सारे हिंदू–मुस्लिम जवान सामने आए. उन्होंने उनके साथ शादी की पेशकश ही नहीं की, बल्कि निकाह भी रचाया. राहत शिविरों में ऐसी लड़कियों से निकाह करने वाले युवकों की तसल्ली कर शिविर के आयोजक शिविर में उनका निकाह करा देते. झुग्गी में दशकों से साथ रहे रमेश शर्मा अपने मुस्लिम पड़ोसी के शिविर में बस जाने का गम नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो वह मुसलमान बनकर शिविर में उसके साथ रहे.

औरतों ने भी हिंदू ब्रिगेड की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला. असंगठित क्षेत्र की महिलाओं ने साथ रहो, साथ काम करो और साथ पढ़ो के नारे के बीच से यह रास्ता निकाला. एक लाख दिहाड़ीदार महिलाओं ने आतंक के साए में रहकर एक साथ रहने की मिसाल क़ायम की. इन महिलाओं में लिफाफा बनाने वाली, बीड़ी बनाने वाली, बोझ ढोने वाली और घरों में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं. अहमदाबाद की आर्थिक गतिविधियों में इनका बड़ा हिस्सा है. सेवा संस्था से जुड़ी इन महिलाओं में एक तिहाई मुस्लिम महिलाएं हैं. दहशत में एक बार इनका विश्वास डिगा, लेकिन सामूहिकता ने उनमें नई रोशनी पैदा की. ऐसी चालीस हज़ार महिलाएं शिविरों में थीं. संस्था की मुखिया गांधीवादी इला रमेश भट्ट ने बताया कि सेवा से जुड़ी सारी महिलाएं दिहाड़ीदार हैं.

कर्फ़्यू के चलते इनकी आमदनी के रास्ते बंद हो गए थे. हमने शिविरों में जाकर पहल की. हमने पांच शिविरों में जाकर बीड़ी बनाने वाली, लिफाफा बनाने वाली और कपड़े सिलने वाली महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध कराया. शुरुआत में हमने उनके माल को स्वयं ख़रीदा. बाद में ठेकेदारों को खोज कर संपर्क बनाया गया. शिविरों में एक दिन में एक लाख बीड़ी का उत्पादन होने लगा था. बारहवीं की परीक्षाएं होने वाली थीं. हमने छात्राओं की पहचान की. उनको ट्यूशन दिलाया. अध्यापक भी हमें शिविरों में मिले. लोगों में विश्वास बढ़ा. हिंदू महिलाएं भी सेवा कार्य के लिए शिविरों में जाने लगीं.

दंगों के दौरान मानवता का अगर नाइंसाफी चेहरा दिखा तो कुछ ऐसे नायक भी सामने उभर कर आए, जिनको इतिहास में जगह न मिले, लेकिन इन लोगों ने ऐसे वक़्त में किसी भी महानायक से बड़ा काम किया. ज़िंदगी को अगर बर्बाद करने वाले हैं तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे बचाने और संवारने वाले भी हैं. ऐसे लोगों को सलाम किया जा सकता है. लेकिन जलाने, मारने और आदमी को काट देने का सिलसिला थमा नहीं था. इन सबके बीच भी ज़िंदगी ने किलकारी भरी. इस सबको शिविरों में अंजाम दिया सायरा आपा और उनकी दो बहनों ने. शिविर में इस त्रिमूर्ति ने चालीस बच्चों को जन्म दिलाया. क़रीब सौ गर्भवती महिलाएं उसके बाद भी बच्चे को जनने का इंतज़ार कर रही थीं. सायरा आपा तैयार थीं. बच्चे अव्यवस्था के बीच जन्म ले रहे थे, लेकिन अपना घर–बार छोड़ शिविर दर शिविर भटक रहीं सायरा आपा एक–एक बच्चे के स्वास्थ्य पर नज़र रखे हुए थीं.

अगले अंक में जारी...

feedback@chauthiduniya.com

अखाड़ों का शाही स्नान : जोगी कम, भोगी ज़्यादा

डॉ.कमलकांत बुधकर

हरिद्वार में इस सदी के पहले पूर्ण कुंभ का पहला शाही स्नान महा शिवरात्रि के दिन निर्विघ्न संपन्न हो गया. कोई दुर्घटना नहीं घटी, कोई भगदड़ नहीं मची और सब कुछ ठीकठाक हो गया. पुलिस की सख्ती ने लोगों को परेशान अलबत्ता किया, पर उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं था. यात्री भी परेशान थे और शहरवासी भी. छोटी–छोटी सामान्य दूरियां भी मेले की यातायात व्यवस्था के तहत बहुत लंबी–लंबी कर दी गई थीं. कनखल से हरिद्वार तक के मुख्य मार्ग लगभग बंद थे. उस पर केवल संन्यासियों की शाही शोभा यात्राएं ही चल सकती थीं. दुकानें बंद, दुकानदारी ठप्प. यूं भी सारे शाही जुलूस के मार्ग और पास–पड़ोस की बस्तियों में बिजली गुल कर दी गई थी. कुंभ के मेले में पेशवाइयों और शोभा यात्राओं के समय बिजली विभाग को करंट लग जाता है. वह हर बार सुन्न पड़ जाता है. यह एक कारगर तरीक़ा है कुंभ में सु–प्रशासन का. भारी भीड़ आ जाने के बयान उछालो, रास्ते रोक दो, बम की अफ़वाह फैला दो, आतंकवाद–माओवाद आदि के ख़तरों की चर्चा करो तो यात्री अपने आप कम आएगा. बिजली गुल कर दो तो किसी को करंट लगने का ख़तरा ही जाता रहेगा.

यह पहला शाही स्नान शिवोपासक सात शैव संन्यासियों का था. जिन सात संन्यासी अखाड़ों के रमता पंच और पेशवाइयों का प्रवेश पिछले दिनों हरिद्वार में हो चुका था, वही सात अखाड़े प्रथम शाही स्नान में सम्मिलित हुए. पर यह पहला शाही स्नान अपने साथ कुछ नई परंपरा और नए प्रश्न भी छोड़ गया है, जो लोकमानस में तैर रहे हैं. पहले हम स्नान की चर्चा करें, फिर उन अनुत्तरित प्रश्नों की.

महा शिवरात्रि भूतभावन भगवान शिव के लिंग रूप में प्राकट्य का दिन माना जाता है. इस जन मान्यता को क्षण भर के लिए अलग करके देखें तो शिव का अर्थ होता है कल्याण. भारतीय मनीषा ने न जाने कब से शिवत्व को देवत्व ही नहीं, महादेवत्व का दर्ज़ा दे रखा है. इस नाते भी और भगवान आशुतोष के सर्व व्यापक स्वरूप की बात करें तो उस नाते भी, उनके नाम से जुड़ी यह महा शिवरात्रि दरअसल विश्व के लिए कल्याण–कामना की रात्रि मानी जाती है. हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि शिवत्व का पूजन ही वस्तुत: शिव का पूजन है.

जगदगुरु आदि शंकराचार्य शिवोपासक थे और उनके अनुगामी– अनुयायी तो उन्हें साक्षात शिवरूप ही मानते हैं. आदि शंकराचार्य ने जब संन्यासियों को संगठित करने का उपक्रम करते हुए दशनाम संन्यास की नींव डाली तो दशनामियों के बीच से ही शस्त्रवीर साधु अखाड़ों की और शास्त्रवीर साधु आश्रमों की परंपरा के पोषक बनकर उभरे. ये सभी शैव हैं. इधर कनखल हरिद्वार दक्षपुत्री सती का मायका होने के नाते सती पति औढ़रदानी औघड़नाथ की ससुराल है. यही कारण है कि परंपरा से हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आने वाली महा शिवरात्रि के दिन सारे शैव अखाड़े हर–हर महादेव का जयघोष करते हुए गंगा स्नान के लिए हरकी पौड़ी पर पहुंचते हैं. पर कुंभ वर्ष की महा शिवरात्रि का यह पावन स्नान अनादिकाल से सिर्फ़ और सिर्फ़ संन्यासियों का स्नान ही रहता आया है. संन्यासी अखाड़ों के स्नान के समय कोई अन्य अखाड़ा या गृहस्थ नर–नारी गंगा घाट पर नहाना तो दूर, प्रवेश तक नहीं कर सकता था.

पर अब युग बदल गया है, काल बदल गया है, परिस्थितियां भी बदली हुई हैं और उन्हीं के साथ शाही स्नानों के दृश्य भी बदल गए हैं. इस वर्ष महा शिवरात्रि के महाकुंभ स्नान के दिन कई नई बातें हरिद्वार में दिखाई पड़ीं. पहली बात तो यह थी कि सात संन्यासी अखाड़ों के आगे–आगे अखाड़ा परिषद के बैरागी अध्यक्ष श्रीमहंत ज्ञानदास तेरहों अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ चल रहे थे. वह पहले अखाड़े यानी जूना की जमात के देवता भगवान दत्तात्रेय की पालकी से भी पहले हरकी पौड़ी के गंगा तट पर पहुंचे. उनके बाद अखाड़े के पारंपरिक अस्त्र–शस्त्र और देवता की पालकी वहां पहुंची. यह पहला अवसर था, जब संन्यासी अखाड़ों की अगुवाई अखाड़ा परिषद के बैरागी अध्यक्ष ने की. एक दृष्टि से देखा जाए तो यह शुभ लक्षण भी है कि संन्यासी–बैरागियों के विवादों का इस तरह परस्पर प्रिय समाधान निकालने की कोशिश इस बार हुई. पर संन्यासियों–बैरागियों समेत अनेकानेक लोगों ने इसे परंपराभंजन भी माना. कहा कि जब सारा कुंभ परंपरा के नाम पर ही आयोजित होता है तो उसमें नई परंपराएं नहीं डाली जानी चाहिए.

चर्चा कुंभनगर की

एक और नई बात जो पहले शाही स्नान में दिखी, वह थी साधु–संन्यासियों से ज़्यादा गृहस्थियों का शाही जुलूस में निकलना और साधु–संतों के साथ नहाना. महा शिवरात्रि पर स्नानार्थ हरकी पौड़ी आए जूना अखाड़े में तो ये गृहस्थी कम नज़र आए, पर निरंजनी एवं महानिर्वाणी अखाड़ों में जोगी कम और भोगी ज़्यादा थे. भगवा वस्त्रों से अधिक नज़र आ रहे थे अन्य रंगों के वस्त्रधारी. इन दोनों अखाड़ों की जमातों को देखकर सामान्य स्नानार्थी परस्पर पूछ रहे थे कि अगर साधु–संतों के साथ गृहस्थजन गंगा में डुबकी लगा सकते हैं तो हमें यह अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने क्या पाप किए हैं या इन गृहस्थियों ने क्या विशेष पुण्य किए हैं, जो हमें हरिद्वार की सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है और इन भोगियों को जोगियों के साथ नहलाया जा रहा है?

इन प्रश्नों के उत्तर सब जानते हैं, पर कोई देना नहीं चाहता. दरअसल, संतों के भक्त जान गए हैं कि संतई का सारा कारोबार उन्हीं के दिए धन–धान्य से चल रहा है. वे आश्रम–अखाड़ों पर रजत वर्षा न करें तो उनकी सारी धार्मिक गतिविधियां ठप्प हो जाएं. इस खुले रहस्य को साधु–संत और उनके आश्रम–अखाड़े भी जानते हैं. बस यहीं से परस्पर प्रशंसंति का भाव जाग्रत हो जाता है. भक्त भेंट चढ़ाते हैं और भेंट का वजन देखकर संतश्री उन्हें अकेले–दुकेले या परिवार–मित्रों सहित अपने रथों के पीछे चलने की अनुमति दे देते हैं. परिणाम वही होता है, जो इस बार पहले शाही स्नान में देखने को मिला. सारी पुलिस, सारा प्रशासन और हरकी पौड़ी के सारे प्रबंधक जुटे हुए थे कि साधु–संतों के बीच में कोई गृहस्थी न घुस जाए. कहीं साधु बाबा परिवारों को देखकर नाराज़ न हो जाएं. पर यह क्या? साधु बाबा तो ख़ुद ही एक नहीं, कई–कई गृहस्थियां लिए चले आ रहे हैं अपने साथ शाही स्नान के लिए! तो फिर उन बेचारे लोगों का क्या अपराध, जिन्हें पुलिस हरकी पौड़ी पर पहुंचने के बाद भी वहां नहाने नहीं दे रही है.

यह सरासर ग़लत परंपरा है, जिसे प्रशासन और संत समाज की मिलीभगत से चलाया जा रहा है. संत समाज ऐसा करके कौन सी सनातन परंपरा का निर्वाह कर रहा है? और, अगर ऐसा ही करना है तो फिर संतों और उनके अखाड़ों में इतना साहस भी होना चाहिए कि वे आम आदमी के साथ गंगा नहा सकें. प्रशासन को भी इस पर विचार करना होगा और इतनी हिम्मत जुटानी होगी कि अगर संतों के साथ गृहस्थियों के नहाने की परंपरा नहीं है तो वे उन गृहस्थजनों को भी शाही जुलूसों और शाही स्नानों में आने से रोकें, जो संतों के चरणों में चढ़ावा चढ़ाकर उनके साथ नहाने का सुख लेते हैं.

पर दोनों पक्ष इस विषय पर विचार करने तक को तैयार नहीं हैं, बल्कि अखाड़े तो आम लोगों का एक स्नान और छीन लेना चाहते हैं और प्रशासन उस पर विचार करने को तत्पर दिख रहा है कि वह आम लोगों के लिए सुरक्षित चैत्र पूर्णिमा यानी 30 मार्च के स्नान को भी तेरह अखाड़ों के शाही स्नान में तब्दील कर दे. यह आम लोगों की आस्था के ख़िलाफ़ षड्यंत्र है. उन्हें हरकी पौड़ी–ब्रह्मकुंड पर स्नान करने से रोकने का षड्यंत्र. अगर ऐसा हुआ तो यह एक ग़लत और जन विरोधी परंपरा की शुरुआत होगी. शासन और प्रशासन को इस संबंध में अभी से चिंतन और चिंता करने की ज़रूरत है.

kk@budhkar.in

कुछ साल पहले भी यह कार्यक्रम इस चैनल पर शुरू किया गया था. इसे दोबारा एमएडी मेक ईट ईजी सीज़न-2 के नाम से शुरू किया जा रहा है.

बाएं से दाएं- फ्यूचर ब्रांड के सीईओ एवं एमडी संतोष देसाई, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के एमडी अनिल सिदाना, फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी, टाटा डोकोमो के प्रेसीडेंट दीपक गुलाटी.

टाटा और फ्यूचर का टी-24

टाटा टेली सर्विसेज एवं फ्यूचर समूह के गठबंधन ने जीएसएम प्लेटफॉर्म पर टी-24 नाम से नया टेलीकॉम ब्रांड लांच किया है. टाटा टेली सर्विसेज के डुअल टेक्नोलॉजी ऑपरेटर और फ्यूचर समूह के संयुक्त प्रयासों से लांच हुआ यह ऑपरेशन शुरुआत में सिर्फ़ दक्षिण भारत में चलेगा. उसके बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में बढ़ाया जाएगा. टाटा टेली सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सरदाना ने बताया कि टी-24 का मतलब है टॉक 24. यानी बातें करें चौबीसों घंटे.

दोनों कंपनियों के गठबंधन से जुड़ा यह ब्रांड नेम ग्राहकों को संदेश देता है कि चौबीसों घंटे बातें और शॉपिंग करें. कंपनी के इस ब्रांड लोगों के बारे में फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी कहते हैं कि इस सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बातें एवं रीचार्ज करने पर फ्यूचर समूह के आउटलेट्स पर शॉपिंग से फ़ायदा होगा. पार्टनरशिप के तहत फ्यूचर समूह के सभी आउटलेट्स पर टी-24 के कनेक्शन बिकेंगे. यह कनेक्शन फ्यूचर समूह के रिटेल आउटलेट्स के नियमित ग्राहकों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होंगे. फ्यूचर समूह के रिटेल आउटलेट्स देश के 65 गांवों एवं 73 शहरों में फैले हैं, इनमें बिग बाज़ार, प्लानेट स्पोर्ट्स, फूड बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ई-जोन, होम टाउन, आधार एवं पैंटालूंस आदि हैं.

सारेगामा का जंप स्टार्ट

म्यूज़िक कंपनी सारेगामा ने जंप स्टार्ट के ज़रिए बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क़दम रखा है. जंप स्टार्ट पुरस्कार प्राप्त रोमांचक थ्री डी मल्टी मीडिया प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से बच्चे मनोरंजन के साथ-साथ गणित, अंग्रेजी, भूगोल एवं सामान्य ज्ञान जैसे विषयों को आसानी से सीख सकेंगे.

तीन से लेकर दस साल तक के बच्चों के लिए जंप स्टार्ट ऐसा शिक्षाप्रद खेल है, जिसकी सहायता से बच्चों में आत्मविश्वास का निर्माण एवं मानसिक विकास होगा. साथ ही इसकी मदद से उन्हें स्कूली शिक्षा एवं परीक्षा में भी सफलता मिलेगी. जंप स्टार्ट की शुरुआत जंप स्टार्ट एडवांस्ड प्री स्कूल से होगी. इसके बाद स्टार्ट एडवांस्ड के जी, जंप स्टार्ट एडवांस्ड फर्स्ट ग्रेड, जंप स्टार्ट एडवांस्ड सेकेंड ग्रेड, जंप स्टार्ट एडवांस्ड थर्ड ग्रेड, जंप स्टार्ट एडवांस्ड फोर्थ ग्रेड आदि हैं. यही नहीं, इसके अलावा जंप स्टार्ट एडवांस्ड 4 से 6 ग्रेड भी है.

सारेगामा का मानना है कि इस मल्टी मीडिया के माध्यम से बच्चे मजे से नृत्य एवं संगीत को बहुत प्रभावी तरीक़े से सीख सकेंगे. इस संबंध में कंपनी होम एडू-टेनमेंट प्रोडक्ट लांच कर रही है, जिससे बच्चों में सीखने की कला का विकास होगा. जंप स्टार्ट एडवांस्ड सीरीज़ देश के सभी संगीत एवं पुस्तकों के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है. आप इसे ऑन लाइन भी इस वेबसाइट www.kids.saregama.com पर आर्डर कर सकते हैं. सारेगामा जल्दी ही ड्रीम क्रीम राइम स्कूल भाग-एक शीर्षक से एक एलबम रिलीज़ कर रहा है, जिसमें अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी हैं. संगीतकार ए आर रहमान और रहमान के एम म्यूज़िक के छात्र एवं किड जी, जो भारत का जाना-माना प्री-स्कूल नेटवर्क है, ने मिलकर इस एलबम का निर्माण किया है.

मक्का और चावल की नई प्रजातियां

ड्यूपॉन्ट कंपनी की इकाई पायोनियर हाई-ब्रेड भारत के खेतों के लिए मक्के और चावल की 16 नई संकर प्रजातियां जारी करेगी, जिसे किसान 2010 के बुआई सत्र में प्रयोग कर सकते हैं. उक्त प्रजातियां बेहतर पैदावार पाने का विकल्प देंगी. फ़िलहाल मक्के की पायोनियर प्रजाति सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, लेकिन अब पायोनियर-3501 के रूप में इससे ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजाति एक बेहतर विकल्प होगी. वर्षा से सींचे जाने वाले खेतों में किए गए प्रयोग में पायोनियर-3540 ने अच्छी उपज दी. चावल की संकर प्रजाति पायोनियर 27पी31 की उपज भी ज़्यादा है. यह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ सहित उन सभी उत्तरी और पूर्वी राज्यों के लिए उपयुक्त है, जहां फ़सल चक्र में खेती होती है. ड्यूपॉन्ट के क्रॉप जेनेटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष विलियम एस नीबर ने कहा कि खेतों में क्षेत्रफल के हिसाब से उचित बीजों के प्रयोग से किसान उपज और मुनाफ़ा बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी विश्व स्तर पर भोजन, ईंधन और अन्य वस्तुओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रति समर्पित है. इसके लिए हम किसानों की ज़रूरत पूरी करने वाले नए उत्पाद बनाते हैं. पायोनियर इंडिया बिजनेस लीडर के वी सुब्बाराव ने कहा कि भारत कृषि का प्रमुख बाज़ार है और नए उत्पाद यह अवसर देंगे कि हम विकास की चुनौतियों का सामना संशोधित अनुवांशिकी के साथ कर सकें. उन्होंने कहा कि पायोनियर द्वारा प्रजातियों के बेहतर स्थानीय उत्पादन और जांच को काफ़ी महत्व दिया जाता है. भारत में पायोनियर के आठ अनुसंधानस्थल, उत्पाद मूल्यांकन नेटवर्क और ड्यूपॉन्ट नॉलेज सेंटर हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में भारत में बीज अनुसंधान में होने वाला कुल निवेश 24 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा. पायोनियर 30 सालों से भारत में संकरित बीज बेच रहा है और संशोधित अनुवांशिक बीज का एक अग्रणी विक्रेता है. यह देश में 15 लाख से ज़्यादा किसानों को अपने उत्पाद बेचता है. इसकी गहन बिक्री और कृषि विज्ञान टीम भारतीय किसानों के साथ जुड़कर काम करती है. पायोनियर हाई-ब्रेड विश्व भर के किसानों, पशुधन उत्पादकों, अनाज एवं तिलहन प्रसंस्करणकर्ताओं की समस्याओं का हल प्रदान करने वाली एक अग्रणी स्रोत है. इसका मुख्यालय डेस मोयिंस, आयोवा में है. यह करीब 70 देशों में लोगों को वनस्पति अनुवांशिकी के विकसित संसाधन मुहैया कराती है.

धोखेबाज़ों को तोहफ़ा

वेलेंटाइन डे पर लव कार्ड देने का चलन काफ़ी पुराना है, पर आए दिन फ़िल्मों के नए कांसेप्ट से बहुत कुछ बदलता रहता है. दिबाकर बनर्जी की आने वाली फ़िल्म लव सेक्स और धोखा ने लोगों को नफ़रत करने का नया तरीक़ा सुझाया है. फ़िल्म के प्रमोशन के तहत दिबाकर ने देश के सात शहरों में धोखा कार्ड्स बांटने का मन बनाया है. धोखा कार्ड मुफ्त में बांटे जाएंगे, जिनके ज़रिए लोगों को संदेश दिया जाएगा कि जो रिश्ता किसी भी तरह के धोखे की वजह से टूटने की कगार पर पहुंच गया है, उसे ख़त्म कर देने में भलाई है. धोखा कार्ड्स चुनिंदा कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों, सैलूनों, स्पा सेंटर्स, टैटू पालर्स आदि सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध होंगे. धोखा कार्ड्स बांटने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एवं चंडीगढ़ आदि शहरों को चुना गया है. ग़ौरतलब है, प्रेम में धोखे की बात ज़्यादातर ऐसे ही बड़े शहरों में सुनने को मिलती है. यही वजह है कि फ़िल्म पर आधारित इन धोखा कार्ड्स को इन्हीं शहरों में बांटने का मन बनाया गया है. कई बार धोखा देने वाले लोग दिल दुखाने के बाद दूर चले जाते हैं, ऐसे ही दूर जाने वाले अप्रिय लोगों को भी उनके द्वारा दिए गए धोखे से आपके मन को हुई टीस का एहसास करा सकते हैं. इसके लिए फिल्म यूनिट ने इंटरनेट का सहारा लिया है, दरअसल आप अपने मन के छले जाने का अहसास फेसबुक के ज़रिए करा सकते हैं. इसके लिए ख़ासतौर पर वर्चुअल कार्ड्स बनाए गए हैं, जिन्हें अपना मैसेज टाइप करके आप एक काले गुलाब के साथ भेज सकते हैं. इसके अलावा एक रेडियो नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करके फ़िल्म के नामलव सेक्स और धोखा का एक कांटेस्ट भी होगा, जिसमें जीतने वाले को लव सेक्स और धोखा गिफ्ट हैंपर मिलेगा. इस गिफ्ट हैंपर में अप्रिय लोगों को देने के लिए ख़ासतौर से एक कैक्टस का पौधा एवं लव, सेक्स और धोखा कार्ड होगा. अप्रिय लोगों को गिफ्ट देने की इस योजना का फ़ायदा आप मार्च तक उठा सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बच्चे घर बैठे सीखेंगे आर्ट

कला व्यक्तित्व को निखारने में अहम किरदार अदा करती है, ख़ासकर बच्चों के पर्सनेलिटी बिल्डअप में कला का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पढ़ाई और दूसरी आवश्यक गतिविधियों का दिन-प्रतिदिन बढ़ता बोझ बच्चों को कला से दूर कर रहा है. बच्चों के पसंदीदा चैनल पोगो ने उन्हें कला से जोड़े रखने की योजना बनाई है. पोगो ने छुट्टी वाले दिन यानी सन डे को बच्चों के लिए फन डे बनाने का इंतज़ाम कर दिया है. इस दिन बच्चे पोगो पर कार्टून देखने के अलावा सुबह नौ बजे अपने प्रिय होस्ट रोबो के साथ चित्रकारी और कलाकारी के गुर भी सीख सकेंगे. कुछ साल पहले भी यह कार्यक्रम इस चैनल पर शुरू किया गया था. इसे दोबारा एमएडी मेक ईट ईजी सीज़न-2 के नाम से शुरू किया जा रहा है. इससे बच्चों को लाभ यह होगा कि उन्हे आर्ट सीखने के लिए किसी हॉबी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे बड़े कलाकारों की तरह आराम से अपने बिस्तर पर बैठे-बैठे चित्रकारी कर सकेंगे. अर्नर इंटरनेशनल इंडिया के प्रोग्रामिंग निर्देशक केतन देसाई कहते हैं कि 2005 में हुई शुरुआत के बाद इसे बच्चों का बेहतरीन कार्यक्रम होने के नौ अवार्ड्स मिल चुके हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत में खेल और खिलाड़ियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इसका सबसे दिलचस्प नज़ारा विंटर ओलंपिक में देखने को मिला.

वी वी एस लक्ष्मण यानी वेरी-वेरी स्पेशल

वर्ष 2001 की बात है. ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलने भारत आई थी. इसके पहले वह लगातार 15 मैच जीतने का विश्व कीर्तिमान बना चुकी थी. पहले टेस्ट में भारत को हराकर कंगारुओं ने यह 16 तक पहुंचा दिया. यानी एक तरह से विश्व क्रिकेट में कंगारुओं का एकछत्र राज था. दूसरे टेस्ट में भी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे धुरंधरों से लैस भारतीय टीम की इज़्ज़त दांव पर लगी थी. पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 445 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इसके जवाब में बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम महज़ 171 रनों पर ही लुढ़क गई. यानी भारतीय टीम को फॉलोऑन खेलना पड़ा.

दूसरी पारी में भी 232 रनों तक पहुंचते-पहुंचते भारत के चार खिलाड़ी पैवेलियन लौट चुके थे. इस तरह भारत पर पारी की हार का ख़तरा मंडराने लगा, लेकिन भारत की पहली पारी में सर्वाधिक 59 रन बनाने वाले वांगिपुरप्पा वेंकट साईं यानी वी वी एस लक्ष्मण अभी क्रीज पर डटे हुए थे. जब एक बार लक्ष्मण ने कंगारू गेंदबाज़ों की क्लास लेनी शुरू की तो अगले दो दिनों तक आउट ही नहीं हुए. जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 608 रनों तक पहुंच चुका था. यानी भारत अब इस मैच को किसी भी तरह हारने की हालत में नहीं था. इस दौरान लक्ष्मण ने 281 रनों की मैराथन पारी खेली. इसी का नतीज़ा था कि भारत इस मैच को न सिर्फ़ बचाने, बल्कि कंगारुओं को मात देने में भी कामयाब रहा.

एक बार फिर लक्ष्मण ने अपनी यही उपयोगिता साबित की है. मैदान भी वही यानी कोलकाता का ईडेन गार्डेन. विपक्षी विश्व की नंबर दो टीम दक्षिण अफ्रीका. इस बार भी श्रृंखला का दूसरा टेस्ट. हालांकि इस बार हालात 2001 जैसे नहीं थे, लेकिन यहां भी भारतीय टीम सीरीज़ का पहला टेस्ट हार चुकी थी. दूसरे टेस्ट में भारत को मज़बूत स्थिति में ले जाने में लक्ष्मण का योगदान काफ़ी अहम था. लक्ष्मण ने 143 रनों की नाबाद पारी खेलकर इस श्रृंखला में भारत की वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई.

लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों की अहमियत इसी बात से आंकी जा सकती है कि यदि ये दोनों धुरंधर खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं होते हैं तो भारत की हालत बेहद दयनीय हो जाती है. दक्षिण अफ्रीका के साथ पहला टेस्ट इसका स्पष्ट उदाहरण है. भारत को पारी की हार का मुंह देखना पड़ा. लक्ष्मण की बल्लेबाज़ी की ख़ासियत यही है कि वह दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज़ों और टीम के ख़िलाफ़ बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं. इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके द्वारा खेली गई बेहतरीन पारियां हैं. यही वजह है कि उन्हें वी वी एस लक्ष्मण यानी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण का नाम दिया गया.

लक्ष्मण की बल्लेबाज़ी को क़रीब से देखने वाले कहते हैं कि उनका अंदाज़ दुनिया के बाक़ी खिलाड़ियों से बिल्कुल ज़ुदा है. उनकी तुलना न तो सचिन तेंदुलकर और न ही राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज़ों से की जा सकती है. हां, कहने वाले इतना ज़रूर कहते हैं कि बल्लेबाज़ी में उनकी कलाई का जादू पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन से ज़रूर मेल खाता है. लेकिन, इन सबके बावजूद वह मौजूदा क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान रखते है, जिसकी तुलना किसी भी खिलाड़ी से नहीं हो सकती है. लक्ष्मण की अपनी एक अलग ही बल्लेबाज़ी शैली है.

डेविस कप और भारत की चुनौती

डेविस कप टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित मुक़ाबलों में एक है, लेकिन यह मुक़ाबला भारत एक बार भी नहीं जीत सका. हालांकि 1966, 1974 एवं 1987 में यह उप विजेता रह चुका है. इसके बावजूद भारत ने डेविस कप के विश्व समूह के लिए 1998 में आख़िरी बार क्वालीफाई किया था. यानी कुल 12 साल के बाद भारत एक बार फिर डेविस कप के विश्व समूह में शिरकत कर रहा है. पहले राउंड में भारत के सामने रूस की चुनौती है. इन दोनों देशों के बीच मुक़ाबला पांच से सात मार्च तक होना है. हाल में जिस तरह का खेल भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया-ओसियाना ग्रुप में दिखाया था, उससे तो यही लगता है कि भारत के लिए इस चुनौती को पार पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे लिएंडर पेस ने भी भारत की संभावनाओं को बेहतर बताया है. यदि भारतीय चुनौती की बात करें तो हाल में लिएंडर पेस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित युगल का ख़िताब जीत कर अपनी ज़बर्दस्त फॉर्म का संकेत दिया है. वहीं सोमदेव देवबर्मन से भी भारत की काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसे उन्होंने एशिया-ओसियाना ग्रुप में साबित भी किया. इसके अलावा रोहण बोपन्ना एवं प्रकाश अमृतराज भी भारत की उम्मीदों को आगे ले जाते दिख रहे हैं. ऐसे में उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि रूसी ज़मीन पर उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.

अगर रूसी चुनौती की बात करें तो रूस यह प्रतियोगिता दो बार 2002 एवं 2006 में जीत चुका है. दोनों बार रूस की इस जीत में मरात साफ़िन ने अहम भूमिका निभाई. अब वह भी टेनिस को अलविदा कह चुके हैं. यानी देखा जाए तो हर तरफ़ से भारत का पलड़ा मज़बूत नज़र आ रहा है.

नंबर वन का असली हक़दार

वर्ष 2009 में भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक पायदान पर क़ाबिज़ हुआ. बांग्लादेश को उसी की ज़मीन पर दोनों टेस्ट में मात देकर भारत ने अपनी इस स्थिति को और मज़बूत किया. हालांकि पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने भारतीयों को अहसास करा दिया कि भारत ज़्यादा दिनों तक अपनी इस पोज़ीशन को बरक़रार नहीं रख पाएगा. बांग्लादेश जैसी फिसड्डी टीम ने जिस तरह पहले टेस्ट में भारत को पानी पिलाया, उससे भारत ने ज़रूर सबक सीखा. यानी किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कमतर नहीं आंकना चाहिए. अभी हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैचों की श्रृंखला का समापन हुआ. पहले टेस्ट में दक्षिणी अफ्रीकी टीम ने भारतीय टीम को शर्मनाक पटखनी दी. पारी की हार से भारत को मुंह की खानी पड़ी. ऐसा कोई पहली बार नहीं था, जब भारत को पारी की हार का सामना करना पड़ा. लेकिन, यदि कोई टीम नंबर एक पर क़ाबिज़ हो और सामने चुनौती उसके जूनियर यानी नंबर दो की टीम से हो तो वाकई मुक़ाबला दमदार हो जाता है. लड़ाई प्रतिष्ठा की होती है. इसके अलावा जब किसी श्रृंखला से किसी टीम के वर्चस्व और शीर्ष रैंक का फ़ैसला होना हो तो मुक़ाबला भी दिलचस्प हो जाता है. यही बात भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाल में संपन्न टेस्ट सीरीज़ पर लागू थी. यानी दोनों के बीच जंग टेस्ट सीरीज़ जीतने की नहीं थी, बल्कि इस श्रृंखला से फ़ैसला होना था टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों टीमों में किसी एक की बादशाहत का. पहले टेस्ट में प्रोटियस ने जिस तरह भारतीय टीम को धूल चटाई, उससे यह तो साफ़ हो गया कि भारत कितने पानी में था. अभी तक बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों को हराने वाली भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिली. यह भारतीय टीम के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं था. और, अपने पहले इम्तिहान में भारत फेल हो गया.

दरअसल, भारतीय टीम की ताक़त उसकी बल्लेबाज़ी में है. एक भी ऐसा गेंदबाज़ भारतीय टीम में नहीं है, जिसे विश्व स्तरीय कहा जा सके. नए गेंदबाज़ आते भी हैं तो उनकी सारी क़ाबिलियत दो या तीन श्रृंखलाओं के बाद ग़ायब हो जाती है. ईशांत शर्मा इस बात की बेहतरीन मिसाल हैं. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग को अपनी गेंदबाज़ी की धार से चकमा देने वाले ईशांत की गेंदों की धार कहीं खो गई है. ज़हीर ख़ान भारतीय गेंदबाज़ी का बोझ अकेले ढोते-ढोते थक से जाते हैं. हरभजन सिंह की फिरकी में भी अब वह जादू नहीं रह गया है. वी वी एस लक्ष्मण ने अभी हाल में कहा था कि भारत के पास फ़िलहाल विश्व स्तर का कोई फिरकी गेंदबाज़ नहीं है. यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि भारतीय टीम यदि नंबर एक बनी भी तो अपनी बल्लेबाज़ी के बूते.

दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम पूरी तरह अफ्रीकी टीम पर हावी रही, लेकिन इसकी वजह भी भारतीय बल्लेबाज़ थे. गेंदबाज़ों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन हक़ीक़त यही है कि जब-जब भारतीय बल्लेबाज़ बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद ज़्यादा होती है. ऐसे अवसर भी आए, जब भारतीय गेंदबाज़ों ने जीत दिलाई. लेकिन ऐसे अवसर कितने आए, उन्हें उंगलियों पर आसानी से गिना जा सकता है. जबकि बल्लेबाज़ों ने अधिकांश मर्तबा जीत का सेहरा टीम के सिर पर बांधा है. यानी इसका सीधा मतलब है कि यदि भारत को अपनी बादशाहत बरक़रार रखनी है तो उसे गेंदबाज़ी और क्षेत्ररक्षण में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है. अन्यथा हम महज़ चंद महीनों के लिए ही शीर्ष पर रहेंगे और मज़बूत विपक्षी के सामने आसानी से घुटने टेक देंगे. जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में हुआ.

खेलों की बदहाली और खिलाड़ियों की दुर्दशा

राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां अपने आख़िरी दौर में हैं. यह आयोजन दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर तक होना है. सभी भारतीय खिलाड़ी भी जी-जान से जुट गए हैं. अभी हाल में दक्षिण एशियाई खेलों में भारत की इन्हीं तैयारियों की एक झलक देखने को मिली. भारत इन खेलों में पदकों के लिहाज़ से पहले पायदान पर रहा. भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी और खेल के प्रति भारतीय अधिकारियों के नज़रिए की एक झलक कनाडा के वैंकूवर में संपन्न विंटर ओलंपिक के दौरान भी देखने को मिली. विंटर ओलंपिक में कुल 82 देशों ने हिस्सा लिया. उनमें भारत भी एक था. 28 फरवरी को संपन्न हुए इन खेलों में भारत हमेशा की तरह पिछले पायदान पर रहा. लेकिन, विंटर ओलंपिक में जो घटना भारतीय टीम के साथ हुई, उससे एक बार फिर भारत का सिर शर्म से झुक गया. भारत में खेल और खिलाड़ियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, इसका सबसे दिलचस्प नज़ारा विंटर ओलंपिक में देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों के पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पोशाक तक नहीं थी. यह बात कनाडाई मीडिया में भी सुर्ख़ियों में बनी रही. इसके बाद वहां के कुछ अप्रवासी भारतीय इन खिलाड़ियों की मदद में आगे आए. हालांकि भारतीय ओलंपिक अधिकारियों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को वह ट्रैक सूट पहनने से मना कर दिया गया. और, खिलाड़ियों ने अपनी निजी पोशाक पहन कर समारोह में शिरकत की. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम खेल के मामले में दिनोदिन कितनी तरक्की करते जा रहे हैं.

इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? पर ऐसे मामलों में पहली बार भारत का सिर शर्म से नहीं झुका है. बात 1950 के फुटबॉल विश्वकप की है. उस साल फुटबॉल विश्वकप यानी फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में आयोजित किया गया था. फीफा विश्वकप की शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन इसमें भाग लेने के लिए भारत को पहला अवसर 1950 में मिला. लेकिन, भारतीय टीम ने यह अवसर भी गंवा दिया. वह भी इसलिए कि फुटबॉल खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे. यानी भारतीय टीम नंगे पैर मैच नहीं खेल सकती थी. इस तरह भारत ने यह सुनहरा अवसर भी गंवा दिया. और, आज तक वह फुटबॉल विश्वकप में खेलने के लिए तरस रहा है. पर हालात आज भी नहीं बदले हैं. पहले जूता नहीं था और आज खिलाड़ियों के पास पोशाक नहीं हैं. हम आज राष्ट्रमंडल खेलों के ज़रिए दुनिया को अपनी ताक़त और नेतृत्व क्षमता का अहसास कराने के लिए तैयार हैं. हमने पूरी तरह अपनी कमर कस ली है. कोई कसर बाक़ी न रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. हाल में आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी चाकचौबंद करने की बात कही गई है. भारत ठीक उसी तरह पूरी दुनिया को अपनी ताक़त का अहसास कराना चाहता है, जिस तरह चीन ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान किया था. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसा कर पाने में सक्षम है? क्या वह अपनी श्रेष्ठता साबित कर पाएगा? यह विंटर ओलंपिक में खिलाड़ियों की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है. यदि वहां के अप्रवासी भारतीय उनकी मदद में आगे न आए होते तो हम 1950 के विश्वकप की तरह इस बार विंटर ओलंपिक से बाहर हो जाते. सवाल जब सरकार पर उठने लगे हैं तो उसने भी बयान देना शुरू कर दिया है. वह कह रही है कि उसने विंटर खेलों के लिए खिलाड़ियों पर सात लाख से भी अधिक रुपये ख़र्च किए. यानी भारत में खेलों की बदहाली और खिलाड़ियों की दुर्दशा का दौर बदस्तूर जारी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

VARSHA
Unisex Salon & Spa
•Rebonding •Streaking
•Perm •Color Touch-up
•Hair Spa •Facial
•Bleach •Pedicure
•Manicure •Waxing
•Bridal &
Pre-bridal Make-up
•Party Make-up
14, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi
Tel: 26329688/89/90
Email: varshasalonandspa@gmail.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

अरसे से सोशल इवेंट्स में समाज सेविका के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने के बाद इन दिनों वह अपने फ़िल्मी करियर के बारे में बातें करने लगी हैं.

टीवी छोड़ने का सवाल नहीं उठता : आदित्य नारायण

बतौर बाल कलाकार फ़िल्म *परदेश* और *जब प्यार किसी से होता है* से शुरू हुआ उसका सफ़र सारेगामा पर सीरीज़ तक आते-आते अपने चरम पर पहुंच चुका था. *छोटा बच्चा जानके न कोई आंख दिखाना रे* गाने वाला उदित नारायण का यह बच्चा अब बड़ा हो चुका है और फ़िल्म *शापित* से एक नई पारी खेलने को तैयार है. नाम है आदित्य नारायण. हाल में आदित्य ने ***चौथी दुनिया*** से एक लंबी बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

बाल कलाकार और लीड एक्टर के तौर पर काम करना कितना अलग है?

दोनों में वही फ़र्क़ है, जो लीड रोल्स और साइड रोल्स में होता है. पहले लोग पहचानते नहीं थे और अब टीवी में काम करने के बाद लोग जानने लगे हैं. इस समय लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं. जबकि चाइल्ड एक्टर के तौर पर इतना दबाव नहीं होता.

शापित एक हॉरर जॉनर फ़िल्म है. इस तरह की फ़िल्मों की सफलता का रिकॉर्ड कुछ ख़ास नहीं रहा. करियर की शुरुआत के लिए ऐसा करना क्या ज़ोख़िम भरा नहीं है?

जी देखिए, समय बदल चुका है. पिछले कुछ सालों में बड़े स्टारों की फ़िल्में नहीं चली हैं और कई छोटे बजट एवं डिफरेंट जॉनर की फ़िल्मों ने बड़ी सफलता हासिल की. ऐसे में जॉनर मैटर नहीं करता. सब फ़िल्म की क्वालिटी पर निर्भर करता है. मुझे उम्मीद है कि *शापित* से दर्शक ज़रूर संतुष्ट होंगे.

फ़िल्म में अभिनय के अलावा आपने गीत गाने के साथ-साथ कंपोज किए और लिखे भी हैं? किस चीज में मन ज़्यादा रमता है?

मैं फ़िलहाल अभिनय पर ही ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि इस वक़्त यही मेरी प्राथमिकता है. रही बात म्यूजिक और सिंगिंग की, तो यह ऑडियंस की पसंद पर निर्भर करता है. अगर गीत उन्हें पसंद आते हैं तो मैं आगे भी गाऊंगा.

फ़िल्म कैसे मिली? करियर में पापा का कितना दख़ल रहता है?

सारेगामा के एक एपिसोड के दौरान ही मेरी निर्देशक विक्रम भट्ट से मुलाक़ात हुई थी. उसी दौरान उन्होंने मुझे *शापित* की कहानी सुनाई थी. हालांकि इससे पहले भी मैं 40-50 स्क्रिप्ट सुन चुका था, लेकिन कुछ जच नहीं रहा था. पापा का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, बस इतना ही चाहता हूं.

किस तरह का किरदार है फ़िल्म में?

मैं इस फ़िल्म में एक कॉलेज ब्वॉय अमन का किरदार निभा रहा हूं, जो काया से प्यार करता है. जब उसे पता चलता है कि काया शापित है तो वह उसकी ख़ातिर सारी दुनिया और आत्मा तक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है.

लड़कियों में तो आपका जबरदस्त क्रेज है. फिर भी सिंगल कैसे रह गए?

प्रशंसकों का मैं शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया. रही बात गर्लफ्रेंड की, मैं अभी सिर्फ़ 22 साल का हूं और सोच-समझ कर ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा.

तो फिर वेलेंटाइन डे उदासी में ही गुज़रा!

नहीं, ऐसा भी नहीं है. उस दिन मैं अपनी हीरोइन के साथ था. भले ही फ़िल्म के प्रमोशन के लिए हम साथ थे, लेकिन वेलेंटाइन डे पर मैं अकेला कतई नहीं था.

पिछले दिनों ख़ान कंट्रोवर्सी में बहुत बयानबाज़ी हुई, बॉलीवुड खेमे में बंटा दिखा. क्या सोचते हैं?

मैं तो अभी बहुत छोटा हूं इस पर कोई कमेंट देने के लिए. इतना ज़रूर कहूंगा कि कोई भी फ़िल्म बनाते वक़्त किसी का भी इंटेंशन सिर्फ़ मनोरंजन होता है न कि विवाद.

शापित के बाद सिर्फ़ फ़िल्म ही करेंगे या टीवी पर भी दिखेंगे?

फ़िल्म तो मैं करूंगा ही, लेकिन टीवी ने ही मुझे लोकप्रियता दी है. इसे कभी नहीं छोड़ूंगा. बल्कि आज तो बड़े-बड़े स्टार्स टीवी पर ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में टीवी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.

आने वाली फ़िल्मों और योजनाओं के बारे में बताइए.

अभी तो फ़िलहाल कई टीवी शोज और म्यूजिक कंसर्ट की बात चल रही है. इसके अलावा विक्रम की अगली फ़िल्म भी कर रहा हूं. बॉडी भी बना ली है. बस देखते जाइए.

राजेश एस. कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

प्रियंका का अजब रोमांस

आज के दौर की सबसे वर्सेटाइल अभिनेत्रियों की बात हो तो पिगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा को कैसे दरकिनार किया जा सकता है. फ़ॉर्मूला और कमर्शियल फ़िल्मों में तो वह पहले से ही सुपरहिट थीं, लेकिन फ़िल्म *कमीने* और *फैशन* के बाद उन्हें गंभीर अभिनेत्रियों में शुमार किया जाने लगा. *फैशन* फ़िल्म के लिए तो वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल कर चुकी हैं. अब उनके नए कारनामे की बात करते हैं. हाल में एक फ़िल्म में उनके अपोजिट *जब वी मेट* एवं *लव आजकल* के निर्देशक इम्तियाज अली को साइन करने की बात चल रही थी. फ़िल्म रोमांटिक ड्रामा थी, इसलिए दोनों के बीच कई हॉट दृश्यों का फिल्मांकन होना था. लिहाज़ा दोनों कलाकारों ने आपस में मीटिंग की. लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, इम्तियाज प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांस करने में घबराने लगे. जब इस बाबत फ़िल्म के निर्माता विशाल भारद्धाज ने इम्तियाज से पूछा तो उनका जवाब भी गोलमोल ही था. हालांकि उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि उन्हें प्रियंका के साथ काम करने में शर्म आती है. अब ऐसा क्या हो गया कि *सोचा न था, जब वी मेट* और *लव आजकल* जैसी प्योर रोमांटिक फ़िल्म बनाने वाले इम्तियाज ख़ुद रोमांस करने से इतना घबरा रहे हैं. विशाल भी इस वाकए से सोच में पड़ गए हैं . उनकी इच्छा थी कि वह किसी भी तरह इस रेयर जोड़ी को बिग स्क्रीन पर एक साथ ला सकें. पर इस वाकए ने तो उनका सपना ही तोड़कर रख दिया है. जब विशाल से किसी ने प्रियंका के बजाए किसी और अभिनेत्री को कास्ट करने के लिए कहा तो वे साफ़ मुकर गए. दरअसल वह *कमीने* फ़िल्म में प्रियंका के अभिनय से इतना प्रभावित हैं कि हर हाल में उसे दोहराना ही चाहते हैं. अब चाहे जो भी हो, प्रियंका को सावधान ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि नए-नए अभिनेता अगर ऐसे ही शर्माते रहेंगे तो उनके साथ काम कौन करेगा!

मन्नत ने छुड़ाई चॉकलेट

बॉलीवुड में जहां सभी हीरोइनें चॉकलेट्स जैसी कैलोरी वाली चीज़े खाने से बचती हैं, वहीं प्राची देसाई इसके ठीक उलट हैं. दरअसल, वह एक टफ चॉकलेट गर्ल हैं, जो चॉकलेट खाए बिना रह नहीं सकती हैं. हां, यह भी सच है कि उनकी फिगर से उनके इस शौक़ का पता नहीं लगता. दरअसल वह रेग्युलर एक्सरसाइज़ करके और लो कैलोरी फूड लेकर अपनी छरहरी काया बनाए रखने में कामयाब हैं. उनका मानना है कि चॉकलेट ही सिर्फ़ एक कारण नहीं है, जिससे किसी का वजन बढ़ता है, बल्कि कोई भी कैलोरी वाली खाने की चीज़ वजन बढ़ा सकती है. यदि लोग नियमित ढंग से एक्सरसाइज़ करें तो उन्हें चॉकलेट से तौबा नहीं करनी पड़ेगी. क्या चॉकलेट की इतनी शौक़ीन लड़की चार महीनों तक चॉकलेट खाना बंद कर सकती है? जवाब है हां. आश्चर्यजनक, लेकिन यह सच है. प्राची पिछले दिनों जब वह एकता कपूर की फ़िल्म *वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई* की शूटिंग कर रही थीं, उस दौरान उन्होंने चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया. अगर आप सोच रहे हैं कि यह डिमांड फ़िल्म के कैरेक्टर की थी तो आप ग़लत सोच रहे हैं. दरअसल, उन्होंने अपने निजी जीवन में किसी मन्नत के पूरा होने पर यह प्रण किया था कि वह चार महीनों तक अपने फेवरिट फूड चॉकलेट से दूर रहेंगी. हालांकि वह मन्नत का ज़िक्र नहीं करती हैं. ज़ाहिर है, उनकी वह मन्नत पूरी हुई होगी, तभी उन्होंने अपने शौक़ के साथ समझौता किया. वेल. अच्छा है प्राची, इतना आध्यात्मिक होना सुविचारों की अभिव्यक्ति है.

सेलिना के नए किरदार

चमकदार भूरी आंखों वाली सेलिना जेटली अपनी सोशल अपियरेंस और कॉमेडी किरदारों की वजह से लोगों द्धारा ख़ूब पसंद की जा गई हैं. नो एंट्री, टॉम डिक एंड हैरी, गोलमाल रिटर्न और अपना सपना मनी-मनी जैसी बॉलीवुड फ़िल्मों के अलावा वह अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म *लव हैज नो लैंग्वेज* में भी कॉमिक किरदार अदा कर चुकी हैं. अरसे से सोशल इवेंट्स में समाज सेविका के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराने के बाद इन दिनों वह अपने फ़िल्मी करियर के बारे में बातें करने लगी हैं. फ़िल्मों से काफ़ी समय से गायब रहने की वजह वह अपनी व्यस्तता बताती हैं. दरअसल वह दो सालों से सात फ़िल्मों की शूटिंग में व्यस्त थीं. इसके साथ ही वह विज्ञापन, कैंपेन, प्रोमोशनल इवेंट और प्रोडक्ट एंडोर्समेंट भी कर रही थीं. अब वह इन्हीं फ़िल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन और वॉयस ओवर में व्यस्त हैं. ख़ास बात यह है कि इनमें सिर्फ़ कॉमेडी जॉनर की फ़िल्में नहीं हैं, बल्कि इनमें सेलिना कुछ नए किरदारों में नज़र आएंगी. उनकी आने वाली फ़िल्म तुषार कपूर के साथ *रन भोला रन* है. इसके अलावा उनके पास बड़े बैनरों की कई अन्य फ़िल्में हैं. घूमने और शॉपिंग की शौक़ीन सेलिना को समाज एवं देश सेवा में रुचि है. जानवरों से उनका लगाव जगज़ाहिर है, खाने की चीज़ों में उन्हें दिल्ली की पानी-पूरी पसंद है.

फ़िल्म रिव्यू

अन्याय के ख़िलाफ़ संघर्ष की गाथा

बीमारी और घटना विशेष पर आधारित फ़िल्मों की फ़ेहरिस्त में अपना नाम जोड़ते हुए करण जौहर ने अपने पुराने रोमांटिक जॉनर को पेश किया है. मानसिक विकार ऑटिज़्म के शिकार रिज़वान ख़ान द्वारा अपना प्यार हासिल करने की कहानी है माई नेम इज़ ख़ान. इसे 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से जोड़ते हुए एक अलग फ्लेवर दिया गया है. फ़िल्म के शुरुआती हिस्से में दंगे का चित्रण है, जिससे रिज़वान ख़ान का मन प्रभावित होता है. लेकिन, वह अपनी मां द्वारा मिली सीख कि दुनिया में केवल दो तरह के इंसान होते हैं अच्छे और बुरे, इसके अलावा कोई भी फ़र्क़ इंसान में नहीं होता है, को पूरी ज़िंदगी याद रखता है. जबकि उसका भाई ज़ाकिर (जिम्मी शेरगिल) यह सीख किसी भी स्कूल-कॉलेज में न मिलने से अंधेरे में भटकता रहता है. ऑटिज़्म का शिकार होने की वजह से रिज़वान का बचपन समाज से मिली यातनाओं के दौर से गुज़रता है. उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है. मां द्वारा दी गई प्रेम एवं जीवन की सीख और गांव में ख़ाली बैठे रिटायर्ड शिक्षक उसके स्कूल बन जाते हैं. आम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान रिज़वान मां की मौत के बाद भाई ज़ाकिर के पास अमेरिका चला जाता है, जहां उसकी मुलाक़ात मंदिरा यानी काजोल से होती है. काजोल बाल विवाह और फिर धोख़े का शिकार होती है. वह तेरह साल के एक बच्चे की मां होती है. रिज़वान मंदिरा के साथ उसके बेटे को भी बेहद प्यार करने लगता है. मंदिरा रिज़वान से शादी कर लेती है, जिसके ठीक बाद 9/11 की घटना हो जाती है. इससे अमेरिकी लोगों को दुनिया भर के मुसलमानों से नफ़रत होने लगती है. आश्चर्य तो यह कि रिज़वान और मंदिरा ख़ान का बेटा समीर ख़ान नाम के आगे ख़ान लगा होने की वजह से अपने क़रीबी दोस्त की दोस्ती खो देता है और अपनी जान गंवा देता है. मंदिरा रिजवान को अपने बेटे की हत्या का ज़िम्मेदार मानने लगती है और उससे अपनी ज़िंदगी से तब तक दूर रहने का वायदा लेती है, जब तक कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाकर ख़ान होने की बेगुनाही को साबित न कर दे. अपने वायदा पूरा करने के लिए रिज़वान राष्ट्रपति से मिलने की हरसंभव कोशिश करता है, पर ग़लतफहमी का शिकार होकर जेल चला जाता है. यहां पर मीडिया में अपना नाम रोशन करने की ख्वाहिश रखने वाले हिंदुस्तानी छात्रों द्वारा रिज़वान को मदद मिलती है और उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है. लेकिन, रिज़वान मंदिरा से किया गया वायदा पूरा करने के साथ ही अपने प्यार को भी हासिल करना चाहता है. इसके लिए वह कोशिश में लगा रहता है. उसकी कोशिश सफल रहती है, जिसमें मीडिया की ख़ास भूमिका होती है. प्रेम, सच्चाई, निर्भीकता और सामाजिक ज़िम्मेदारी का एहसास कराती यह फ़िल्म दर्शकों को छू लेने वाली है. मुख्य भूमिका निभा रहे शाहरुख एवं काजोल जैसे दिग्गज कलाकारों की किरदार अदायगी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के हमशक्ल वाले दृश्य ने निराश किया. यह फ़िल्म ख़ास तौर पर मल्टी प्लेक्स दर्शकों का ज़्यादा पसंद आएगी.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

निर्देशक	:	करण जौहर
निर्माता	:	गौरी ख़ान
संगीत	:	शंकर एहसान लॉय
पटकथा	:	शिबानी बथीजा
सितारे	:	काजोल, शाहरुख़ ख़ाान, जिमी शेरगिल

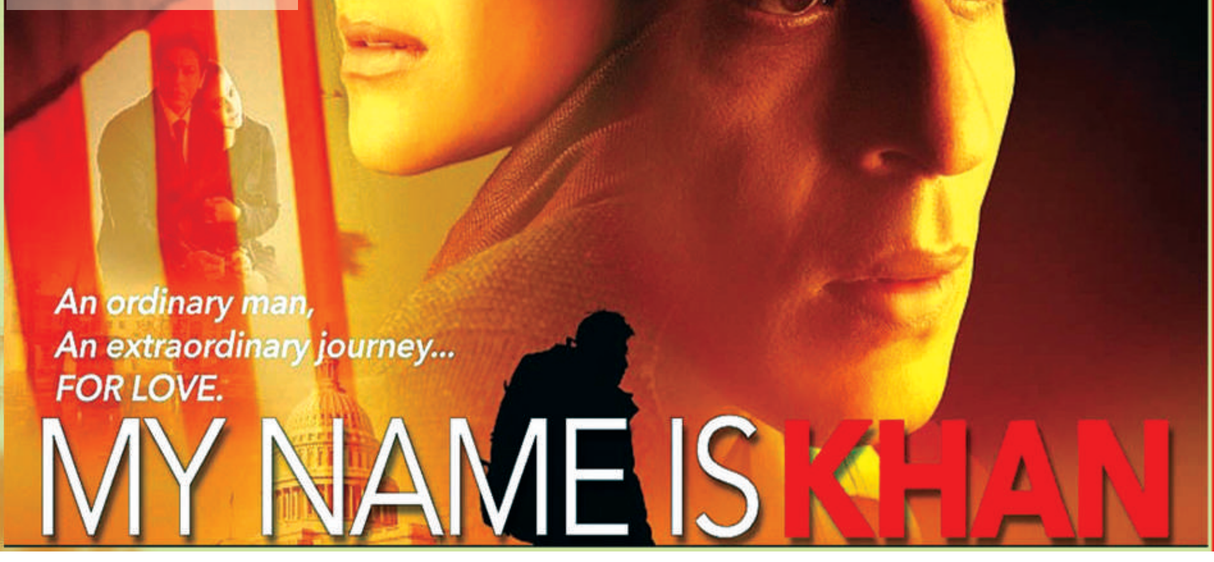

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 1 मार्च–7 मार्च 2010
www.chauthiduniya.com

नीतीश कुमार

सुशासन पर शराब के छींटे

जमशेद अशरफ

ज़मशेद अशरफ की शिकायत अगर सही है तो इसके निश्चित रूप से गंभीर मायने हैं. यह न सिर्फ़ सुशासन पर सवालिया निशान लगाने वाली बात है, बल्कि इसके दूरगामी परिणामों से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. याद रहे कि यह एक चुनावी साल है!

सरोज सिंह

बात निकली है तो दूर तलक जाएगी. बर्ख़ास्त उत्पाद मंत्री ज़मशेद अशरफ अपनी पीड़ा का इज़हार करते–करते यहां तक कह गए कि जिस बिहार को बनाने मैं यहां आया था, शराब माफ़ियाओं और उनको संरक्षण देने वाले अफ़सरों के गठजोड़ ने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया. लेकिन हार नहीं मानूंगा, सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाऊंगा. नीतीश कुमार के लिए एक मुसलमान मंत्री को बर्ख़ास्त करने का फ़ैसला लेना आसान नहीं था, पर सुशासन पर शराब के छींटों ने ज़मशेद अशरफ के भाग्य का फ़ैसला कर दिया. इसके साथ उत्पाद विभाग में पांच सौ करोड़ रुपये के कथित घोटाले की कहानी का पहला अध्याय तो समाप्त हो गया, पर दूसरे अध्याय की पटकथा तैयार हो चुकी है. सरकारी जांच को ख़ारिज़ कर सीबीआई जांच की मांग रख चुके अशरफ क़ानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं. मोनाजिर हसन के बयान से आहत अशरफ को लगता है कि उनकी बिरादरी संघर्ष के इस रास्ते में उनका पूरा साथ देगी. नीतीश से नाराज़ गुट और कांग्रेस भी चाहती है कि अशरफ अपना हमला तेज़ करें, ताकि सुशासन पर पहली बार लगे दाग का दायरा बढ़ता जाए. बताया जाता है कि जल्द ही कुछ और भी मंत्री अशरफ की तर्ज़ पर अफ़सरों को निशाना बनाकर सुशासन की हवा निकाल सकते हैं.

ज़मशेद अशरफ ने दो अहम सवाल उठाए. पहला, अफ़सर मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और दूसरा यह कि छह महीने से कोशिश करने के बावजूद उनकी नीतीश कुमार से मुलाक़ात नहीं हो पाई. अफ़सरों के हावी रहने की बात तो बहुत दिनों से कही जा रही है. मंत्री, विधायक एवं सांसद भी इस मसले को उठाते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करने की बात कह अशरफ ने यह बतलाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के पास सही तथ्यों को नहीं रखा जा रहा है. अपने विभाग के मामले में मुख्य सचिव की जांच पर उंगली उठाते हुए अशरफ ने आरोप लगाया कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है और सही जानकारी नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाई. जनप्रतिनिधियों की राय को दरकिनार कर अफसर फ़ैसले ले ही रहे थे, पर अब ग़लत तथ्यों को परोस कर मुख्यमंत्री से फ़ैसला कराने की गंभीर बात अशरफ ने सामने रखी है. मंत्री से ज़्यादा अफसरों पर भरोसा अशरफ को परेशान करता रहा और जिसकी परिणति उनकी बर्ख़ास्तगी के रूप में हुई. नीतीश कुमार ने पत्र के माध्यम से अशरफ को बताया कि आपका आचरण पद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है. घोटाले की जहां तक बात है तो मुख्य सचिव की जांच से सब कुछ साफ़ हो गया है. सब चीजें नियम के दायरे में हुई हैं. हां, कुछ बातें आपके ही ख़िलाफ़ जा रही हैं. गोपनीय पत्र के मीडिया में लीक होने पर भी नीतीश ने सवाल उठाए. दूसरा सवाल भी बेहद गंभीर है. ज़मशेद अशरफ का कहना कि छह माह तक कोशिश करने के बावजूद उनकी नीतीश कुमार से मुलाक़ात नहीं हो पाई. अगर यह बात सही है तो फिर सुशासन की मान्य परिभाषा में थोड़ा फेरबदल ज़रूरी हो जाएगा. सरकार का एक मंत्री छह माह तक अपने मुखिया से नहीं मिल पाता है और उसके विभाग के फ़ैसले होते रहते हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है. पिछले दिनों प्रभुनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, पर उनकी भी मुलाक़ात नहीं हो पाई. आजकल वह भी पत्रों के माध्यम से अपनी बात नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं.

शरद यादव और विजय चौधरी.

दरअसल चुनावी साल होने की वजह से हर एक की बेचैनी बढ़ गई है. हर कोई ऐसे समीकरण की तलाश में है, जो उसे सत्ता की दहलीज़ तक पहुंचा सके. ललन सिंह एवं नीतीश कुमार के आमने–सामने हो जाने से लड़ाई का मैदान एकदम खुल गया है. पार्टी में रहकर ही कार्यकर्ताओं के मान–सम्मान की लड़ाई का ऐलान कर ललन सिंह ने संकेत दे दिया है कि वह विरोध की लंबी और निर्णायक पारी खेलने के मूड में हैं. न चाहते हुए भी सरकार से नाराज़ सांसदों, विधायकों एवं मंत्रियों की वह धुरी बन गए हैं. ज़मशेद अशरफ ने जब शराब घोटाले की बात कही तो कहा गया कि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है. पर ललन सिंह कहते हैं कि अशरफ ने अपनी बात रखी है. रिमोट कंट्रोल की बात कहां है. यह ज़रूर है कि पार्टी को मज़बूत बनाने और उसकी धर्म निरपेक्ष छवि को निखारने के लिए मैं अशरफ को लेकर आया था, पर इससे क्या होता है. एक मंत्री ने अपनी पीड़ा रखी है. ललन सिंह कहते हैं कि मैं तो विजय चौधरी को भी पार्टी में लेकर आया, आज वह अध्यक्ष हैं. पिछले सप्ताह विजय चौधरी को लेकर भी जदयू के भीतर हाई वोल्टेज नाटक चलता रहा. शरद यादव पटना में दो दिन रहकर विधायकों एवं मंत्रियों का मन टटोलते रहे. इस दौरान दो बार उनकी ललन सिंह से भी मुलाक़ात हुई. कहा गया कि विजय चौधरी के नाम पर ललन सिंह की भी सहमति है, पर बाद में ललन सिंह ने साफ़ किया कि उनकी न सहमति है और न विरोध. जदयू के कई नेताओं ने बताया कि शरद यादव नया अध्यक्ष चुनने नहीं, ललन प्रकरण के बाद पार्टी में उभरे असंतोष की थाह लेने आए थे. इसलिए उन्होंने सभी से मिलकर पार्टी को मज़बूत करने की सलाह दी. जहां तक विजय चौधरी का सवाल है तो उनका नाम काफ़ी पहले ही तय कर लिया गया था.

इधर जदयू और सरकार में छिड़े घमासान का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश में विपक्षी पार्टियां लगी हैं. कांग्रेस ज़मशेद अशरफ जैसे नेताओं पर डोरा डालने में जुट गई है. मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस करेगी कि नीतीश ने ज़मशेद अशरफ के साथ अन्याय किया. जदयू के कई नाराज़ नेता कांग्रेस में जाने को उत्सुक हैं, पर उचित समय का इंतज़ार कर रहे हैं. ऐसे नेताओं की कई दौर की बातचीत कांग्रेसी रणनीतिकारों से हो चुकी है. प्रभुनाथ सिंह जैसे नेताओं का झुकाव लोजपा की तरफ़ बताया जा रहा है. ललन प्रकरण के बाद ज़मशेद अशरफ के इस तरह नीतीश सरकार से बाहर होने से यह साफ़ हो गया है कि चुनावी साल में जदयू को अभी और भी कई झटके झेलने पड़ सकते हैं. जदयू के नाराज़ सांसदों एवं विधायकों की गोलबंदी और तेज़ होने के साथ ख़तरा यह भी है कि उनके कुछ और मंत्री अफ़सरों पर घोटाले का आरोप लगाकर अपना रास्ता अलग कर लें. बजट सत्र के दौरान भी सरकार को परेशान करने की गणित तैयार की जा रही है. विजय चौधरी को जदयू अध्यक्ष बनाकर गुस्से को कुछ कम करने की कोशिश की गई है, पर लगता नहीं कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, यह बात तो दूर तलक जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

वर्तमान में भी यहां भाजपा विधायक के रूप में जवाहर प्रसाद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में जुटे हैं.

प्रबंधन ठीक से न होने के कारण घरों से निकलने वाले कचरे से जल पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

परिसीमन ने तस्वीर बदल दी

चुनावी साल होने के कारण रोहतास ज़िले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चहलपहल दिख रही है. इसका कारण परिसीमन है. नए परिसीमन से कुशवाहा बहुल इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी है. बात चाहे जातीय समीकरणों की हो या मुद्दों की, धीरे–धीरे स्थितियां बदल रही हैं. नए परिसीमन से ग़ैर कुशवाहा उम्मीदवारों को भी उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं. ज़िला मुख्यालय सासाराम के सभी 40 नगर परिषद क्षेत्रों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना मुश्किल है. फ़िलहाल परिदृश्य चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक एवं नए दावेदारों की बेचैनी इस नए विधानसभा क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही दिख रही है.

जवाहर प्रसाद

बात सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल भाजपा से शुरू करना न्यायोचित है, जिसका पिछले कई चुनावों से इस सीट पर क़ब्ज़ा रहा है और वर्तमान में भी यहां भाजपा विधायक के रूप में जवाहर प्रसाद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में जुटे हैं. ख़ासकर, परिसीमन के बाद सासाराम प्रखंड के उत्तरी हिस्से से जुड़े दर्ज़नों गांवों में तो उनका दौरा काफी तेज़ हो गया है. पूछने पर वह बताते हैं कि नए परिसीमन ने उनकी राहें और भी आसान कर दी हैं, क्योंकि पूर्व में यह गांव नोखा विधानसभा क्षेत्र का अंग था, जो भाजपा का गढ़ था. वैसे प्रसाद की बातों में कुछ दम भी दिखता है, लेकिन उन्हीं के गांव के मतदाताओं का हवाला देकर राजद के पूर्व विधायक एवं संभावित उम्मीदवार डॉ. अशोक कहते हैं कि इस गांव में रहने वाले मतदाता अगड़ी जाति से आते हैं, जिनका मोह वर्तमान राज्य सरकार एवं राजग गठबंधन से भंग हो चुका है. उनका दावा है कि नोखा से अलग हुए और सासाराम में जुड़े उत्तरी क्षेत्र के मतदाता राजद के जनाधार को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन गांवों के ज़्यादातर मतदाता राजग गठबंधन के विरोधी हैं.

डॉ. अशोक

यह कहना अतिशयोक्ति भी नहीं है कि कुशवाहा बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में परिसीमन के बाद जुड़े गांवों में अगड़ी जाति के राजपूत एवं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिनका समर्थन पूर्व में एक हद तक नोखा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को मिलता रहा है. अगर यह आधार सत्य है तो आने वाले दिनों में भी पूर्व की कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन कांग्रेस द्वारा यहां सशक्त उम्मीदवार देने की तैयारी राजग गठबंधन को मुश्किल में डाल सकती है. हालांकि अभी चर्चा लोकसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सांसद मीरा कुमार के देवर राज शेखर के नाम पर ज़्यादा चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐन वक्त पर गैर कुशवाहा समीकरणों का ख्याल रखकर पार्टी ने अगर किसी अल्पसंख्यक, राजपूत या ब्राह्मण को अपना उम्मीदवार बना दिया तो हैरानी भी नहीं होगी. यह देखते हुए कई दावेदार सामने आ सकते हैं, जिनमें ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष सलामत अंसारी से लेकर अन्य कई नाम चर्चा में हैं. बताते चलें कि सलामत अंसारी ने फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में लोजपा उम्मीदवार के रूप में सासाराम विधानसभा क्षेत्र से लगभग 22 हज़ार मत प्राप्त किए थे. सासाराम से पूर्व ज़िलाध्यक्ष शीला सिंह भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चर्चा पा रही हैं, जो गत विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं. लोजपा खेमे से भी कभी–कभी यह बात राजनीतिक हलके में छनकर आती है कि यहां से राजद के बदले लोजपा के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसमें अब्दुल सत्तार सहित कई उम्मीदवार अभी से हाथ–पांव मार रहे हैं. बात बसपा की करें तो सासाराम के पूर्व प्रखंड प्रमुख के के सिंह ताल ठोककर कहते हैं कि किसी भी क़ीमत पर बसपा के बैनर तले उन्हें सासाराम से चुनाव लड़ना है, क्योंकि क्षेत्र के दलितों के लिए वह अपना काफ़ी समय गुज़ार चुके हैं और समीकरण के लिहाज़ से राजपूतों के मतों का ध्रुवीकरण उनकी तरफ़ हो सकता है. इधर चेनारी के युवा नेता गुलाम सरवर भी हाथी की सवारी करने की तैयारी में हैं. वह अपनी पैठ मायावती के सबसे क़रीबी खेमे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है, क्योंकि बसपा उम्मीदवार के रूप में सासाराम सीट ही अल्पसंख्यकों के कोटे में है.

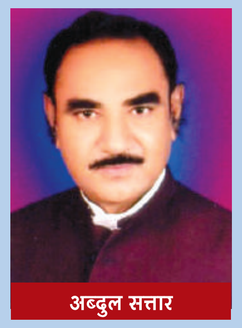

अब्दुल सत्तार

के के सिंह

बसपा के उम्मीदवारों की फेहरिस्त और भी लंबी होती जा रही है, जबकि कांग्रेस में भी कई नामों पर चर्चा बढ़ी है. सपा के ज़िलाध्यक्ष मदन मोहन श्रीवास्तव भी सासाराम से ही उम्मीदवारी जताने में जुटे हैं. वह कहते हैं कि अगर गठबंधन भंग हुआ तो इस बार पार्टी सासाराम से एक सशक्त उम्मीदवार देगी. हालांकि उनके समर्थकों ने उन्हीं के नाम की चर्चा बतौर उम्मीदवार शुरू की है. सासाराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ेगा, जीत किसकी होगी, यह तो बाद में पता चलेगा. फ़िलहाल यहां के संभावित उम्मीदवारों पर नज़र दौड़ाएं तो यह कहा जा सकता है कि यहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या दो दर्ज़न तक पहुंच गई है. नए परिसीमन में सत्ताधारी गठबंधन की राहें कठिन भी हैं, क्योंकि अगड़ी जाति के मतदाताओं की संख्या में कम से कम 15 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हो चुकी है.

नए परिसीमन से किसको फ़ायदा और किसको घटा होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फ़िलहाल सभी उम्मीदवार फ़ायदा उठाने के चक्कर में जी–जान से जुटे हैं. वे अभी से ही अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ़ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ़ हो.

बात बसपा की करें तो सासाराम के पूर्व प्रखंड प्रमुख के के सिंह ताल ठोककर कहते हैं कि किसी भी क़ीमत पर बसपा के बैनर तले उन्हें सासाराम से चुनाव लड़ना है, क्योंकि क्षेत्र के दलितों के लिए वह अपना काफ़ी समय गुज़ार चुके हैं और समीकरण के लिहाज़ से राजपूतों के मतों का ध्रुवीकरण उनकी तरफ़ हो सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कचरे के चलते रोज़ी-रोटी का संकट

नई परियोजनाओं पर आठ महीने के लिए रोक लगना धनबाद में गर्त में जाते उद्योग जगत के लिए एक और चुनौती है. ख़ासकर रोज़गार के दृष्टिकोण से यह निर्णय विकट स्थिति पैदा करने के लिए काफ़ी है. धनबाद ज़िला प्रशासन, कोल कंपनियों के प्रबंधन और राज्य सरकार की अदूरदर्शी सोच के कारण यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई है. अगर तीनों में से किसी ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई होती तो आज इस स्थिति का सामना न करना पड़ता. इतना ही नहीं, अगर अगले आठ महीनों में भी कोई परिवर्तन न हुआ तो निश्चित रूप से लोगों के सामने और भी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी.

मंदी के दौर से गुज़र रहे देश में बेरोज़गारी बड़ी समस्याओं में शुमार है. ऐसे में धनबाद जैसे शहरों में नई परियोजनाओं पर रोक से बेरोज़गारी और बढ़ेगी. हालात ऐसे हो चुके थे कि मंत्रालय को विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 43 औद्योगिक केंद्रों में बढ़ते प्रदूषण के कारण नई परियोजनाएं शुरू करने पर आठ माह की रोक लगा दी है. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने हाल में इन औद्योगिक केंद्रों को गंभीर रूप से प्रदूषण उत्पन्न करने वाला क़रार दिया है. यह प्रतिबंध तत्काल प्रभावी हो गया है और अगस्त 2010 तक लागू रहेगा. दरअसल, धनबाद समेत देश के 43 शहरों में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और यह घातक रूप ले चुका है. धनबाद में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी जनित प्रदूषण के सबसे बड़े कारक कोयले के कण हैं. प्रबंधन ठीक से न होने के कारण घरों से निकलने वाले कचरे से जल पर भी बुरा असर पड़ रहा है. कोयले के कारण कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. जल प्रदूषण के करण कई क्षेत्रों में लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष दमा से पीड़ित लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है. ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव से लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं. इन सभी समस्याओं का कारण शहर में ठोस कचरा प्रबंधन न होना है. विडंबना देखिए कि आज से चार साल पहले धनबाद को नगरपालिका से नगर निगम बना दिया गया, मगर कर्मचारियों की संख्या जस की तस है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, दस हज़ार की आबादी पर 28 सफ़ाई कर्मचारी होने चाहिए. इस प्रकार सिर्फ़ सफाईकर्मियों की संख्या 2800 होनी चाहिए, लेकिन यह संख्या 650 से 750 के बीच है. कुछ मज़दूरों को दैनिक भुगतान के आधार पर रखा जाता है, मगर यह उपाय कारगर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्देश में स्पष्ट किया है कि एक सफ़ाईकर्मी के ज़िम्मे 250 से 300 वर्ग क्षेत्रफल ही आता है. इस अनुपात का पालन धनबाद जैसे शहर में संभव नहीं है. कुल मिलाकर जब तक सरकार सफ़ाईकर्मियों को बहाल नहीं करती, तब तक सफ़ाई के दृष्टिकोण से धनबाद में सुधार होने की संभावना नहीं दिखती है. इन सभी समस्याओं का इलाज ठोस कचरा प्रबंधन के माध्यम से ही संभव है. सामान्य तौर पर कचरा दो प्रकार का होता है. एक ठोस और दूसरा द्रव्य कचरा. उद्योगों से निकलने वाले कचरे रासायनिक नामों से जाने जाते हैं. घरों से निकलने वाले ठोस कचरे को अलग कर रिसाइकिल करने का प्रबंध किया जाता है.

इसके लिए मशीनें लगाई जाती हैं, जो कचरे के ढेर को अलग कर इसे फिर प्रयोग में लाने लायक बना देती हैं. लेकिन, ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर न तो सरकारी स्तर से प्रयास किया गया और न ही कभी तंत्र पर दबाव डाला गया. राजनीतिज्ञों ने तो इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं. अभी भी समय है कि सरकार, प्रशासन और धनबाद की जनता सतर्क हो जाए, अन्यथा देश में औद्योगिक नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके ज़िले के लिए आने वाले दिन कठिनाइयों से भरे होंगे. एक तो पहले से ही उद्योगों की स्थिति मरणासन्न है, जिससे हज़ारों लोगों पर रोज़गार का ख़तरा मंडरा रहा है.

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

समस्या का समाधान कैसे हो

धनबाद नगर निगम में जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए मशीनें लगेंगी. नई जगह की तलाश की जा रही है, लेकिन इन परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रदूषण विभाग से एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी. अब जबकि केंद्र सरकार ने नई परियोजनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया है तो निश्चित रूप से इस परियोजना के लिए भी एनओसी लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. धनबाद को कचरे के ढेर से निजात दिलाने के लिए ठोस प्रबंधन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार पैसा भी उपलब्ध कराएगी. इस कार्य के लिए परामर्शी का चयन कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मशीनें लगाने के लिए पर्यावरण विभाग की एनओसी राह में बाधा बनकर खड़ी है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस संदर्भ में फ़िलहाल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है.

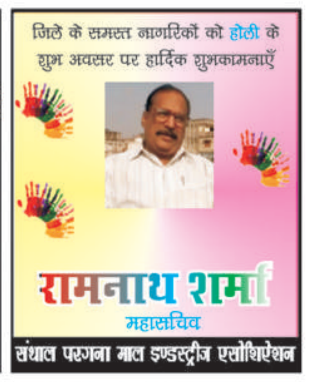

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

यहां मिले प्राचीन शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि आज से क़रीब 1900 साल पहले इस मंदिर में तांडुलम का ही भोग लगता था.

अजब देवर के ग़ज़ब भौजाई

अजब देवर के ग़ज़ब भौजाई. यह नाम सुनकर आपको कुछ याद आया? जी हां, आपको याद आ गई होगी पिछले साल की सुपरहिट फ़िल्म अजब प्रेम की ग़जब कहानी. लेकिन, इस फिल्म का उपरोक्त टाइटल से कोई लेना-देना नहीं है. अजब देवर के ग़जब भौजाई नाम है उस भोजपुरी फिल्म का, जो मार्च 2010 के आसपास रिलीज होगी. इस बड़े बजट की फिल्म में कई बड़े कलाकार नज़र आएंगे, जिसमें मोनालिसा, सिकंदर, उपासना सिंह, शक्ति कपूर एवं मुश्ताक खान आदि प्रमुख हैं. लेकिन, इस फिल्म में एक और बाला भी है, जिसके हुस्न के जलवों के चर्चे अभी से होने लगे हैं. इसका नाम हिना रहमान है. यह हसीना इस फिल्म में ग़ज़ब भौजाई के रोल में क़यामत ढाती नजर आएगी. अब आप सोच रहे होंगे कि यह हिना कौन है? तो हम आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों में आने से पहले यूके में जीटीवी के एक शो में बतौर एंकर काम कर चुकी है. पाकिस्तानी मां और भारतीय पिता की यह संतान सोहेल खान की होम प्रोडक्शन फिल्म *आई प्राउड टू बी अ इंडियन* में भी लीड रोल में नज़र आई थी. फिल्म असफल रही और हिना को नोटिस नहीं किया गया. इसके बाद भी उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें *व्हाई, मनी मनी मनी, घुटन और फन* प्रमुख हैं, लेकिन सही तरीक़े से पब्लिसिटी न मिलने से इन फिल्मों का हश्र भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास नहीं रहा. बावजूद इसके हिना ने हिम्मत नहीं हारी और अगले प्रोजेक्ट पर ध्यान देती रहीं. अब वह अपनी आने वाली भोजपुरी फिल्म अजब देवर के ग़जब भौजाई को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि जो एक्सपोजर उन्हें हिंदी फिल्मों में नहीं मिला, वह इस फिल्म में नॉटी भौजाई के किरदार में मिल रहा है. चलिए तो फिर तैयार रहिए, इस ग़ज़ब भौजाई के दीदार के लिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

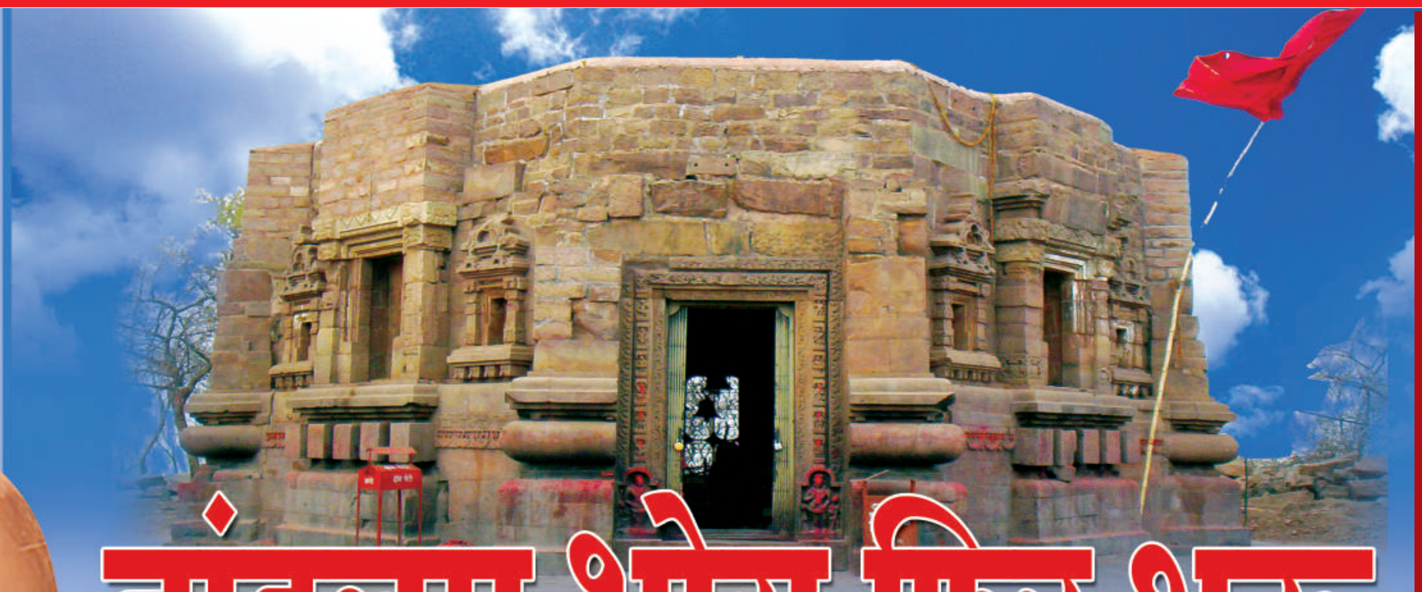

तांडुलम भोग फिर शुरू

कैमूर ज़िले का मुंडेश्वरी मंदिर तांडुलम भोग वितरण की सदियों पुरानी पौराणिक प्रथा के कारण फिर से चर्चा में है. यहां तांडुलम भोग अर्थात चावल का भोग और वितरण की परंपरा पुन: शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इस पौराणिक प्रथा की पुन: शुरुआत किए जाने के बाद अब यहां प्रतिदिन तांडुलम भोग लगता है और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में उसका वितरण किया जाता है. यह प्रसाद पके हुए चावल को देसी घी में भूनकर तैयार किया जाता है. मुंडेश्वरी मंदिर में तांडुलम भोग की परंपरा कब और किसके द्वारा आरंभ की गई, यह कहना कठिन है, लेकिन मंदिर से मिले प्राचीन शिलालेख के आधार पर माना जाता है कि 108 ईस्वी में यहां यह परंपरा जारी थी. शिलालेख में लेखक द्वारा कहा गया है कि मंदिर में प्रतिदिन भोग लगाने हेतु दो प्रस्थ चावल के नैवेद्य का प्रबंध किया जाता था. मंदिर में आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु पचास दीनार का प्रबंध किए जाने की बात भी शिलालेख में कही गई है. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उस समय मुंडेश्वरी मंदिर ज़रूर अस्तित्व में था.

यहां मिले प्राचीन शिलालेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि आज से क़रीब 1900 साल पहले इस मंदिर में तांडुलम का ही भोग लगता था. संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित इस शिलालेख में महाराज उदयसेन का ज़िक्र है और श्री मंडलेश्वर स्वामी के चरणों में जब तक चंद्र-सूर्य स्थित हैं, अक्षय रूप से प्रतिदिन भोग लगाने हेतु दो प्रस्थ चावल का नैवेद्य एवं दीप प्रज्ज्वलित करने हेतु तेल का प्रबंध किए जाने की बात कही गई है. ज़िले के भगवानपुर अंचल में कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर कब और किसने बनवाया, यह निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन हाल के शोधों से ज्ञात हुआ है कि यह देश का प्राचीनतम मंदिर है. मुंडेश्वरी मंदिर से संबंधित दो पुरातात्विक साक्ष्य अब तक मिल पाए हैं. जैसे ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीन शिलालेख और श्रीलंका के महाराजा दुतगामनी की राजकीय मुद्रा. मंदिर के काल निर्धारण का मुख्य आधार वहां से प्राप्त शिलालेख है. इस शिलालेख का एक टुकड़ा 1892 और दूसरा 1902 में मिला था. दोनों टुकड़ों को जोड़कर इसी साल कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम में भेज दिया गया है.

मुंडेश्वरी शिलालेख के आरंभ में ही संवत्सर के तीसवें वर्ष में इसके लिखे जाने की बात कही गई है. शिलालेख को पहली बार 1908 में प्रो. आर डी बनर्जी द्वारा पढ़ा जा सका था. उन्होंने संवत्सर का आशय हर्षवर्धन के काल से लगाते हुए इसके लिखने का समय सन् 636 ईस्वी निर्धारित किया था, लेकिन विख्यात इतिहासकार एन जी मजूमदार ने शिलालेख का गहन अध्ययन करने के उपरांत संवत्सर का आशय गुप्तकाल से लगाते हुए इसके लिखने का समय सन् 349 ईस्वी निर्धारित किया. हालांकि ताज़ा पुरातात्विक शोधों के आधार पर शिलालेख में उल्लेखित संवत्सर को शक संवत् मानते हुए इसे कुषाण युग में हुविश्क के शासनकाल में सन् 108 ईस्वी में उत्कीर्ण माना जा रहा है. इस मान्यता के समर्थकों का कहना है कि गुप्तकालीन अभिलेखों में परिनिष्ठित संस्कृत का उपयोग होने लगा था, जबकि 18 पंक्तियों के मुंडेश्वरी शिलालेख में व्याकरण की 11 अशुद्धियां हैं. इसके अलावा कुषाणकालीन अभिलेखों की पहली पंक्ति में ही अभिलेख की तिथि मिलती है और यही बात मुंडेश्वरी शिलालेख में भी देखने को मिलती है, जबकि गुप्तकालीन अभिलेखों की शुरुआत शासकों की प्रशंसा से होती थी. इन लोगों द्वारा अपने मत के समर्थन में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि मुंडेश्वरी शिलालेख में मास और दिवस के साथ पक्ष (शुक्ल या कृष्ण) की चर्चा नहीं है, जो कुषाणकालीन अभिलेखों की ख़ासियत है. जबकि गुप्तकालीन अभिलेखों में मास व दिवस के साथ पक्ष का भी उल्लेख मिलता है.

यह भी उल्लेखनीय है कि मुंडेश्वरी मंदिर से मिले श्रीलंका की राजकीय मुद्रा को जिस महाराजा दुतगामनी से संबंधित माना जाता है, वह बौद्ध साहित्य के अनुसार ईसा पूर्व 101-77 में श्रीलंका का शासक रहा था. इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर स्पष्ट हो जाता है कि मुंडेश्वरी शिलालेख कुषाणकाल का है. वैसी स्थिति में ज़ाहिर है कि मंदिर का निर्माण शिलालेख लिखे जाने से पहले ही हुआ होगा. इस काल का कोई भी मंदिर भारत में अब मौजूद नहीं है. मुंडेश्वरी मंदिर की प्राचीनता का महत्व इस दृष्टि से और अधिक बढ़ जाता है कि यहां पर पूजा की परंपरा अविच्छिन्न रही है तथा आज भी यह मंदिर पूरी तरह जीवंत है. यहां पिछले 1900 सालों से पूजा भी होती रही है. मुंडेश्वरी मंदिर अहिंसक बलि प्रथा के लिए भी विख्यात है. बकरे को मुंडेश्वरी देवी के सामने लाया जाता है और इस पर पुजारी द्वारा अभिमंत्रित चावल जैसे ही छिड़का जाता है, वह अपने आप अचेत हो जाता है. यहां पर बलि की बस यही पूरी प्रक्रिया है. इसके बाद बकरे को छोड़ दिया जाता है और वह चेतना में आ जाता है. मुंडेश्वरी मंदिर प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित है. स्थानीय जानकार लोगों का कहना है कि इसकी प्राचीनता को ध्यान में रखा जाए तो यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरिटेज) घोषित किए जाने का हक़दार है.

अशोक कुमार पांडेय
feedback@chauthiduniya.com

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग के अंतर्गत कुटीर ग्रामोद्योग योजना प्रारंभ की थी.

राजा भोज के असली चेहरे की तलाश

इतिहास में गर्भ में न जाने कितने राज़ दफ़न हैं. राजा महाराजाओं की विरासत से लेकर विलुप्त हो चुकी संस्कृतियों की जानकारी इसी गर्भ से हासिल होती है. लेकिन कुछ गुत्थियां ऐसी होती हैं जो अनसुलझी ही रह जाती हैं. ऐसी ही एक गुत्थी है राजा भोज की. दसवीं–ग्याहरवीं सदी के इतिहास प्रसिद्ध लोकमान्य राजा भोज के असली चेहरे की तलाश की जा रही है, अब तक भोज के अनेक चित्र और उनकी अनेक मूर्तियां बनाई जा चुकी हैं, लेकिन पुरातत्व विद्वान अब तक किसी एक चित्र या मूर्ति को प्रामाणिक और सर्वमान्य नहीं मान सकें हैं.

भारतीय इतिहास में राजा भोज आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय राजा और लोकनायक के रूप में जन–जन में विख्यात हैं. हिन्दी भाषी क्षेत्र में इस कहावत से सभी परिचित हैं कि कहां राजाभोज और कहां गंगूतेली. दसवीं सदी के अंतिम दशक में जन्मे राजा भोज ने 1010 ईसवी से 1055 ईसवी तक मध्य भारत में राज्य किया. उनकी राजधानी धारा नगरी, जिसे वर्तमान में धार कहा जाता है, थी और उनका राज्य गुजरात तथा मध्यप्रांत के क्षेत्रों में फैला हुआ था. प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉ. रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य पर शोध के दौरान मलयाली भाषा में भोज की रचनाओं की खोज करने के बाद यह माना है कि राजा भोज का शासन सुदूर केरल के समुद्र तट तक था. राजा भोज ने मध्यप्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल नगर की स्थापना की थी. लोक विश्वास है कि भोपाल का नाम भोजकाल में भोजपाल था. राजा भोज ने ही भोपाल में विस्तृत और विशाल प्राकृतिक झील को बांधकर तालाब का रूप दिया था, जो आज भी क़ायम है. राजाभोज द्वारा निर्मित शिवमंदिर, भोपाल के निकट भोजपुर में आज भी अपने विगत वैभव की याद दिलाता है.

राजा भोज ने ही भोपाल में विस्तृत और विशाल प्राकृतिक झील को बांध कर तालाब का रूप दिया था, जो आज भी क़ायम है.

राजा भोज का 9वीं शताब्दी का चित्र.

भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी हिंदूवादी संगठन अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत राजाभोज के बारे में भोपाल वासियों की भावनाओं का दोहन करते रहे हैं. कई बार मांग उठ चुकी है कि जब कई बड़े शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, तब भोपाल का नाम भी बदलकर भोजपाल या भोजपुर किया जाना चाहिए. लेकिन इस मांग को भोपाल की जनता का ज़्यादा समर्थन नहीं मिला. इसके बाद मांग उठाई गई कि भोपाल झील पर राजाभोज की प्रतिभा स्थापित की जानी चाहिए. इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठा कि जिस राजा भोज की आज तक कोई प्रमाणिक और निर्विवाद तस्वीर उपलब्ध नहीं है, उस राजा की विशालकाय मूर्ति किस आधार पर तैयार की जाए. मध्यप्रदेश सरकार और नगर निगम भोपाल ने राजा भोज की प्रामाणिक तस्वीर की खोज का काम पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के ज़िम्मे सौंपा. लेकिन यह काम आसान नहीं था. परमार समाज स्वयं को राजा भोज का वंशज और सजातीय मानता है. समाज के पास राजा भोज का एक रंगीन चित्र भी है और इसी के आधार पर समाज चाहता है कि राजा भोज की मूर्ति इसी चित्र के आधार पर तैयार की जाए. लेकिन प्रसिद्ध पुरातत्वविद् नारायण व्यास का कहना है कि परमार समाज द्वारा उपलब्ध कराया गया चित्र 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मराठा वीर तात्या टोपे के चित्र से मेल खाता है. इसके अलावा समाज ने जो चित्र उपलब्ध कराया है, उसके बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. राजा भोज परमार पंवार समाज संगठन, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष भोजराज पंवार का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम राजाभोज की असली तस्वीर या आकृति तलाश रहे हैं. उनका कोई वास्तविक चित्र नहीं हैं, जो चित्र हमें मिला, उसमें कई विसंगतियां हैं.

आख़िर में राजा भोज के असली चेहरे की खोज का यह अभियान एलिजाबेथ म्यूजियम लंदन में रखी भोजशाला की सरस्वती प्रतिमा पर जाकर थमा. इस प्रतिमा में राजा भोज की अब तक प्राप्त एक मात्र आकृति उकेरी गई है. प्रतिमा लगाने का बीड़ा उठाने वाले पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी. जिसमें पुरातत्वविद् भगवती लाल राजपुरोहित, नारायण व्यास के साथ मूर्तिकार और वास्तुविद राजीव सिंह के साथ पर्यटन विकास निगम के अधिकारी और परमार समाज के प्रतिनिधि शामिल थे. कमेटी ने शोध के आधार पर भोज का स्केच तैयार कराया है. अब इसके आधार पर गन मेटल की दो टन वजनी और बीस फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी. यह प्रतिमा वीआईपी रोड स्थित बुर्ज पर आसीन होगी. पर्यटन विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक बीएम नामदेव बताते हैं कि स्केच कमेटी ने एप्रूव्ड कर दिया है. मंज़ूरी के लिए राज्य शासन के संस्कृति विभाग को भेजा है.

गुजरात के पाटन के नज़दीक रानी की बावड़ी से निकाली भीमदेव सोलंकी की मूर्ति के आधार पर ही राजा भोज की आकृति और उस दौर के रहन सहन के तरीक़े को समझा गया. भोज का कोई चित्र ज्ञात इतिहास में नहीं है. एक मात्र आकृति भोजशाला की सरस्वती प्रतिमा में है. एएसआई के अनुसार मूर्तिकार मंथल द्वारा तैयार इस प्रतिमा को लगभग सौ साल पहले अंग्रेज ब्रिटेन ले गए थे. उज्जैन निवासी प्रसिद्ध पुरातत्वेत्ता पद्श्री डॉ. विष्णु वाकणकर के मुताबिक़ यह प्रतिमा अभी भी लंदन के एलिजाबेथ म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है. लेकिन सच यह है कि राजा भोज के वास्तविक चेहरे पर संशय की धुंध अब भी बरक़रार है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साज़िश ने डुबोया बैंक

बुरहानपुर का सिटीजन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक सुनियोजित और सोची समझी साज़िश के तहत डुबाया गया है. इस बैंक में जमा आम जनता की मेहनत की कमाई डूब गई, लेकिन दिन के उजाले में की गई इस सफ़ेद पोश डक़ैती के लिए अभी तक किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही न होना, आश्चर्य का विषय है.

बुरहानपुर के सिटीजन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बड़े पैमाने पर हुई आर्थिक एवं दस्तावेज़ी अनियमितता को देखते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आर्थिक अनियमितताओं के चलते वर्ष 2005 में सिटीजन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को अपने निर्देशन में लिया था. इस संबंध में अधिवक्ता ईश्वर नवथरे ने बताया कि मई 2009 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश में उल–लेख है कि बैंक ने उद्य श्रेणी के एन.पी.ए. की वसूली के लिए कोई प्रभावशाली क़दम नहीं उठाए, साथ ही 82 ऋण खाते ऐसे है, जिसकी राशि रूपये 1601.75 लाख होकर कुल अग्रिमों का 47.4 प्रतिशत थी उनके विरूद्ध कोई प्रतिभूति नहीं रखी गई थी. बैंक के पास जो दस्तावेज थे वह पूरे नहीं थे. वहीं बैंक के कब्जे में जो संपत्तियां थीं उनके भी पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे. नवथरे ने आगे कहा कि यह सब देखते हुए लगता है कि बैंक के जो कर्मचारी व अधिकारी इस काम को देख रहे थे. उन्होंने सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रचकर लोगों की जमा राशि का दुरूपयोग किया है.

उन्होंने बताया कि जमाकर्ताओं के साथ बैंक ने धोखाधड़ी की तथा नियमों के विरूद्ध जाकर मनमर्जी से कानून की अनदेखी कर जमा धन का दुरुपयोग किया है. वहीं इतनी गंभीर अनियमितता होने के बाद भी बैंक के उद्य पदों पर बैठे व्यक्तियों ने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की. नवथरे ने उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं से बैंक में जो भी घपले हुए एवं इसमें जो भी शामिल हो उन पर कार्यवाही करने की मांग की है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना फ्लॉप

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं सतना ज़िले में फ्लॉप शो साबित हुई हैं. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग के अंतर्गत कुटीर ग्रामोद्योग योजना प्रारंभ की थी. इस योजना के तहत 30 लोगों का एक समूह बनाकर छोटे–छोटे उद्योग स्थापित कराने की मंशा सरकार की थी. इसके लिए शासन ने बाक़ायदा सब्सिडी देने का प्रावधान भी रखा था. लेकिन मौजूदा समय में ग्रामीणों ने इस योजना से मुंह फेर लिया है. एक ओर जहां ग्रामीणों ने इस योजना से दूरी बना ली है वहीं विभाग द्वारा पंजीकृत की गई समितियां भी धीरे–धीरे निष्क्रिय हो रही हैं. हालात कितने बद्तर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दो वर्ष से विभाग द्वारा ज़िले में एक भी समिति का गठन नहीं किया गया. हालांकि समितियों के गठन के लिए विभाग ने कई आकर्षक योजनाएं चालू की जिसमें समिति सदस्यों का एक लाख रूपये का बीमा व सदस्यों का हेल्थ पैकेज प्रमुख है.

‘पिछले दो वर्षों से ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग के माध्यम से समितियों का पंजीयन नहीं हुआ. जहां तक समितियों के निष्क्रिय होने का प्रश्न है तो जो समितियां घाटे में चल रही हैं वही निष्क्रिय हैं.- योगेंद्र मिश्रा, निरीक्षक ग्रामोद्योग हथकरघा’

ग्रामोद्योग के माध्यम से पंजीकृत होने वाली समितियों में अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है. इनके काम अलग–अलग होते हैं. मसलन बुनकर समिति में सदस्य हथकरघा के माध्यम से कपड़े बनाना, सिलाई बुनाई करना तथा औद्योगिक समितियों के सदस्य ईंट भट्टा व अन्य छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं. शासन की ओर से समिति सदस्यों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है. सामान्य वर्ग के सदस्यों को 33 प्रतिशत तथा हरिजन कोटा के सदस्यों को 50 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की गई है. इन सब सुविधाओं के बावजूद इन समितियों का फ्लॉप होना चिंता का विषय है.

मध्य प्रदेश: एड्स के बढ़ते मामले

मध्य प्रदेश में इस समय एड्स की बीमारी का क़हर बढता जा रहा है. सरकार का स्वास्थ्य विभाग राज्य में एड्स रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने से चिंतित है. इसके अलावा राज्य में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा हर साल करोड़ों रूपया एड्स की रोकथाम के प्रचार अभियान पर ख़र्च किया जाता है, फिर भी इस प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग के पास एड्स बीमारी की जांच के लिए न तो पर्याप्त साधन है और न ही अमला है. ज़िला स्तर के और छोटे अस्पतालों में तो हालात और भी बदतर हैं. सरकारी डॉक्टर एड्स रोगियों के उपचार में न तो कोई रुचि नहीं लेते हैं और न ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि यह बीमारी पूरे प्रदेश में अपने पांव पसार रही है. इसके अलावा इनके पास एड्स सुरक्षा किट भी नहीं है.

राज्य में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा हर साल करोड़ों रूपया एड्स की रोकथाम के प्रचार अभियान पर ख़र्च किया जाता है.

मध्यप्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में एड्स की जांच के लिए राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों और 40 ज़िला अस्पतालों में 103 जांच केंद्र है, बाद में सोसाइटी ने 40 नए जांच केंद्र खोलने का फ़ैसला लिया है. मध्य प्रदेश में 1995 तक एड्स प्रभावित मरीज़ों की संख्या 225 थी जो 2009 तक बढ़कर 16 हज़ार से ज़्यादा हो गई है. सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है कि राज्य में हर माह 50 से अधिक एड्स के नए मरीज़ अस्पतालों में जांच और उपचार के लिए आ रहे है. एड्स की रोकथाम के प्रचार अभियान में लगे एक ग़ैर सरकारी स्वयं सेवी संगठन के अध्ययन के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब एड्स रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है. प्रवासी मज़दूरों के असुरक्षित यौन संबंधों के कारण यह बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मरीज़ों से डॉक्टर भी डरते हैं

जानलेवा यौन रोग एड्स से पीड़ित मरीज़ों से वे डॉक्टर भी भय खाते है, जो आम जनता को यह संदेश देते है कि एड्सरोगी को छूने से एड्स रोग नहीं होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वास्तविक स्थिति यह है कि यदि भूले भटके कोई एड्स पीड़ित इलाज के लिए आ जाता है, तो डॉक्टर इसे छूने और इसका इलाज करने से कतराते है.

हाल ही सिवनी के सरकारी ज़िला अस्पताल में एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए भर्ती कराई गई. प्रसव पीड़ा होते ही डॉक्टरों ने इस महिला को लेबर रूम में पहुंचा दिया, लेकिन जब डॉक्टर को मालूम पड़ा कि वह महिला एड्स रोग से पीड़ित है, तो प्रसव वेदना से कराह रही महिला को लेबर रूम में अकेला छोड़कर डॉक्टर और सहायक चिकित्साकर्मी भाग खड़े हुए. इस घटना की सूचना एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी तक पहुंची और उन्होंने तत्काल ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस आर चौहान से पूछताछ की. डॉक्टर चौहान ने मजबूरी बताते हुए कहा कि एड्स सुरक्षा किट न होने के कारण डॉक्टर इस महिला का प्रसव नहीं करा पा रहे है क्योंकि प्रसव के दौरान ख़ून भी निकलता है और ऐसे में एड्स मरीज़ के खून से डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों का सीधा संपर्क होता है. कुछ देर बाद एड्स सुरक्षा किट डॉक्टरों को उपलब्ध करा दिए गये और इस महिला का प्रसव भी सुरक्षित रूप से करा दिया गया. महिला और इसका बच्चा दोनों सुरक्षित है. बाद में बच्चे की जांच से पता चला है कि वह बच्चा एड्स प्रभावित नहीं हुआ है.

सिवनी के डॉक्टर ने बताया कि ज़िला अस्पतालों में एड्स मरीज़ों के इलाज के लिए आवश्यक एड्स सुरक्षा किट डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं कराये जाते. ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसी सुरक्षा किटों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है. प्रसव जैसे मामलों में मरीज़ों की ब्लड रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं होती है. एड्स सुरक्षा किट की क़ीमत 500 रूपये होती है और ये किट राज्य के कुछ बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध है.

दर्द से कराहती ज़िंदगी

दूषित पानी से विकलांग होते ग्रामीण

सुब्रत कुमार भौमिक

यूनीसेफ की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत वर्ष के 20 राज्य के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लाखों लोग फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से फ्लोरोसिस के शिकार हैं. सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में आंध्रप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है, जहां 70 से 100 प्रतिशत ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं, जबकि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तरप्रदेश में फ्लोरोसिस प्रभावित ज़िले 40 से 70 प्रतिशत है.

छत्तीसगढ़ के 51 कस्बों के लगभग 5250 ग्रामीणों के लिए जीवन दायिनी जल ज़हर बन गया है. फ्लोराइड से दूषित हैंड पम्पों और कुंए का पानी पीकर हज़ारों ग्रामीण फ्लोरोसिस के दर्द से कराह रहे हैं. भारत सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से मुक्ति दिलाने के प्रयास तो जारी हैं, लेकिन दर्द से कराह रहे पीड़ितों के लिए दवा सरकार के पास नहीं है. ग़रीबी की मार पहले से ही झेल रहे इन ग्रामीणों का अब बिना दवा के दर्द से लड़ने का हौसला भी समाप्त हो रहा है.

तमाम सरकारी दावे और प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह का तथाकथित चाउर वाले बाबा का नाम उस वक्त बेमानी लगता है, जब फ्लोरोसिस से पीड़ित दर्द से कराहती तीन बच्चों की मां नोनीबाई सबसे मिलने पर कहती है कि दवा तो दूर ग़रीबी रेखा का राशन कार्ड ना बन पाने के कारण दो वक्त के अनाज के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है. पिछले सात सालों से खाट पर लेटी नोनीबाई की ज़िंदगी में अब दर्द ही है. कोरबा ज़िले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के बिझरा ग्राम पंचायत के कौआताल मोहल्ले की निवासी नोनीबाई के हैंडपंप का फ्लोराइड युक्त पानी ज़हर बन गया. अकेले नोनीबाई ही नहीं ग्राम के 21 परिवार फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से फ्लोरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं. फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन ने ना केवल ग्राम की महिलाओं, पुरुषों की हड्डियों को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि उन्हें विकलांग बना दिया है. इस लाईलाज बीमारी फ्लोरोसिस ने लोगों के शरीर में एक ऐसा दर्द दे दिया है, जिससे निजात मिलना अब मुश्किल है. यह दर्द महज़ शरीर की हड्डियों का ही नहीं बल्कि उस ज़िन्दगी का है जो उन्हें दूसरों के सहारे बितानी है. पीने के पानी से मिले इस विकलांगता के शिकार ग्रामीणों को सरकारी मदद के नाम पर मुआवज़ा और विकलांगता प्रमाण पत्र तो दूर अब तक की दवा भी नहीं मिल पाई है.

छत्तीसगढ़ आसाम, जम्मू एवं कश्मीर, केरल तथा पश्चिम बंगाल के 10 से 40 प्रतिशत ज़िले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं. छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में बीजापुर है जहां 31 कस्बों के हज़ारों ग्रामीण फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 7 ग्राम, रायगढ़ में 6 ग्राम कोरबा में 6 ग्राम और बिलासपुर का एक ग्राम इसकी चपेट में है. वहीं मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा, धार, विदिशा, शिवनी, सीहोर, रायसेन, मंदसौर, नीमच, उज्जैन एवं ग्वालियर ज़िले भी फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं.

दरअसल दूषित जल के सेवन के मामले प्रकाश में आने के बाद देश भर में ग्रामीण पेयजल के सर्वेक्षण का कार्य पहली बार राज्य स्तर पर 1991 में शुरू किया गया जिसके बाद लगातार इन रिपोर्टों को अपडेट किया गया. रायगढ़ ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एच.एस. उरांव के मुताबिक ज़िले के तमनार विकासखण्ड के पांच ग्रामों के कुल 43 लोग फ्लोरोसिस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं, जिसके बाद पी.एच.ई. विभाग द्वारा तत्कालिक तौर पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई थी. बाद में दूषित हैंडपंपों को बंद कर दिया गया और नए हैंडपंप लगाए गए हैं. फ़िलहाल ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल रही है, जिसके कारण मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है. श्री उरांव की अगर माने तो वर्तमान में हालात ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि प्रभावित ग्रामों के भूगर्भ में फ्लोराइड की मात्रा है. भविष्य में इन्हीं नए हैंडपंपों से भी फ्लोराइड से दूषित होने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हालात तो फिर भी थोड़े ठीक हैं लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र की दास्तां तो सबसे जुदा है. छत्तीसगढ़ में बीजापुर ज़िले के जिस भोपालपट्टनम ग्राम के सर्वाधिक जल स्त्रोतों को भारत सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र माना है. यहां के पीएचई विभाग के एसडीओ टोप्पो से जब चौथी दुनिया ने हालात की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहां किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि जल परीक्षण के दौरान फ्लोराइड की मात्रा कम पाई गई है. वहीं पीएचई विभाग के ही उमेलिया ने चौथी दुनिया को बताया कि बीजापुर ज़िले के 5 ग्राम भोपालपट्टनम, रालापल्ली, गोल्लागुड़ा, गुल्लापेटा एवं गोटाईगुड़ा क्षेत्र में 3 से 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोरोसिस की मात्रा पाई गई है. जिससे अंशिक रूप से ग्रामीण प्रभावित हैं. वर्तमान में 6 किमी दूर स्थित इंद्रावती नदी से पाईप लाइन बिछाकर प्रभावित ग्रामों में जल आपूर्ति किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है. यहां यह बताना ज़रूरी है कि भारत सरकार ने 1 मिली ग्राम से अधिक मात्रा को शरीर के लिए हानिकारक माना है. दोनों ही अधिकारियों की बातों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी ग्रामीण अब भी दूषित जल का सेवन कर रहे हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्र की वर्षों से दास्तां यही है कि तमाम सरकारी योजनाएं इन इलाक़ों में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं. सूत्रों की अगर मानें तो नक्सलवाद के नाम पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से योजनाओं के रकम की बंदरबांट जारी है. वैसे भी सरकार को नक्सलियों की चिंता है, नक्सलवाद की नहीं.

भारत सरकार के मापदण्ड के तहत दूषित जल स्त्रोतों को प्रति 250 व्यक्तियों के बीच मौजूद जल स्त्रोतों के तहत चिन्हांकित किया गया है. छत्तीसगढ़ में 16 ग्राम पंचायतों के 21 ग्रामों के 51 जल स्त्रोतों को फ्लोराइड से दूषित पाया गया है, इस आधार पर अगर गणना करें तो लगभग 5250 लोग प्रदेश भर में आज भी फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से आंशिक या पूर्णतः प्रभावित हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में विभिन्न धातुओं से दूषित जल के 1658323 स्त्रोत हैं. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश भर में दूषित जल के सेवन से प्रभावित लोगों की संख्या करोड़ों में है.

feedback@chauthiduniya.com

दूषित जल के सेवन से अपंग एक ग्रामीण

महिला और बाल व्यापार

आदिवासी बालिकाओं की तस्करी

मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्डौरी आदि आदिवासी जनसंख्या बहुल ज़िलों में आए दिन आदिवासी बालिकाओं के अचानक ग़ायब हो जाने की ख़बरें अब सामान्य घटना हो गई हैं. पुलिस ज़्यादातर घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज़ नहीं करती और मजबूरी में यदि रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो गुमशुदगी के मद में रिपोर्ट दर्ज़ कर उसे काग़ज़ों में ही दफ़न कर दिया जाता है. मण्डला ज़िले में कार्यरत् एक स्वयंसेवी संस्था निर्माण के स्वतंत्र अध्ययन से पता चला है कि पांच वर्षों में 600 से अधिक अवयस्क आदिवासी बालिकाएं लापता हुई हैं और इनमें से 80 प्रतिशत का आज तक कहीं कोई सुराग तक नहीं लगा है. श्रम और सेक्स के लिए आदिवासी बालाओं को इस क्षेत्र में सक्रिय दलाल बहला–फुसलाकर नगरों, महानगरों में ले जाते हैं और उनका सौदा करते हैं. पुलिस भी क्षेत्र में सक्रिय दलालों की मौजूदगी से इंकार नहीं करती है.

कहानी छुन्नी की

आमगांव में रहने वाली छुन्नी (परिवर्तित नाम) भोपाल अपने भाई के साथ मज़दूरी करने आई थी.

> **मण्डला, बालाघाट, डिण्डौरी ज़िलों में पिछले पांच वर्षों में 600 से अधिक अवयस्क युवतियां ग़ायब हुई हैं और इनमें से 80 प्रतिशत का आज तक कोई पता नहीं चला है.**

गत वर्ष फरवरी माह में जब वह अपने ठिकाने से पाखाना करने घर से निकली, तो दो माह तक वापस नहीं आई. बताते हैं कि भोपाल में उसके भाई के साथ काम कर रहे हीरा नामक व्यक्ति उसे बहला–फुसलाकर राजस्थान के डोकरखेड़ा कस्बे में ले गया. वहां उसे 60 हज़ार रूपए में रमेश को बेच दिया. रमेश ने दो माह तक छुन्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा. घर के कामकाज के अलावा छुन्नी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत मज़दूरी भी करनी होती थी और मज़दूरी का पैसा उसका कथित पति रमेश छीन लेता था. एक दिन छुन्नी एक स्थानीय व्यक्ति अंगद की सहायता से रमेश के चंगुल से निकलने में सफल हो गई. यहां भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. उसका मुक्तिदाता अंगद भी उसे किसी और के हाथों उसे बेचने की कोशिश करने लगा था. छुन्नी एक रात उसके चंगुल से छूटकर निकल भागी और किसी तरह अपने घर आमगांव लौट आई. ऐसा ही डिण्डौरी ज़िले के समनापुर गांव की कलावती के साथ हुआ. कलावती और छुन्नी तो घर लौट आईं, पर सैकड़ों ऐसी अभागी बालिकाएं हैं, जो अब तक वापस नहीं लौटीं.

दलालों का जाल

इन आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार तथा अशिक्षा के कारण ग़रीब जनता रोज़ी–रोटी के लिए हमेशा संघर्षरत् रहती है. इसका फ़ायदा कुछ दलाल उठा रहे हैं. दलाल गांव के किसी व्यक्ति को अपना एजेंट बनाकर मजबूर ग़रीब परिवारों की जानकारी लेते हैं, फिर उनसे मेलजोल बढ़ाते हैं. इसके बाद शहर में अच्छा रोज़–गार दिलाने, अमीर घर में घरेलू नौकर का काम दिलाने या अच्छे खाते–पीते घर में विवाह करा देने का लालच देकर बालिकाओं को अपने साथ ले जाते हैं. कुछ मामलों में तो दलाल परिवार वालों को पैसा भी देते हैं. अक़्सर सौतेली मां या नजदीकी रिश्तेदार पैसे के लालच में बालिकाओं को दलालों के साथ भेज देते हैं.

सीधी ज़िले में कुसमी जनपद पंचायत क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो में डेढ़ दर्ज़न से ज़्यादा अवयस्क युवतियों के ग़ायब होने के पीछे यही कारण रहे हैं.

लिंगानुपात असंतुलन के कारण भी बढ़ा है यह व्यापार

महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और हरियाणा राज्यों में लिंगानुपात असंतुलन बहुत ज़्यादा है. इन राज्यों में कई जातियों और समाजों में तो युवकों के विवाह के लिए युवतियां ही नहीं मिलती हैं. इसलिए विवाह हेतु भी अवयस्क बालिकाओं और कम उम्र की युवतियों की मांग सदा बनी रहती है. इस मांग को पूरा करने के लिए ज़िन्दा गोश्त के व्यापारी ग़रीबी बहुल इलाक़ों में सक्रिय बने रहते हैं. बालाघाट पुलिस ने कुछ माह पूर्व ही चार अवयस्क बालिकाओं को शहर से बाहर ले जाते हुए दलालों के चंगुल से मुक्त कराया है. लेकिन छिन्दवाड़ा कुंवर सिंह पुसाम को दु:ख है कि 2004 से ग़ायब उसकी बेटी की तलाश आज तक पुलिस ने नहीं की है. एक–दो नहीं, मण्डला, बालाघाट, डिण्डौरी ज़िलों में पिछले पांच वर्षों में 600 से अधिक अवयस्क युवतियां ग़ायब हुई हैं और इनमें से 80 प्रतिशत का आज तक कोई पता नहीं चला है. पुलिस केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ करती है और चैन से बैठ जाती है यदि कोई ग़ायब हुई युवती वापस आ जाती है तो पुलिस अपनी पीठ ख़ुद थपथपा लेती है. वास्तव में एक संगठित गिरोह इस इलाक़े में अपना जाल बिछाए हुए है. और पुलिस इनसे बेख़बर है.

छुन्नी, भोपाल से ग़ायब हुई थी और भोपाल में उसकी रिपोर्ट दर्ज़ कराई गई थी. लेकिन पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कोई प्रयास नहीं किए. जब वह लौट आई तो जांच कार्यवाही के लिए पुलिस ने बग़ैर किसी अपराध के उसे तीन दिन तक महिला थाने में रखा. बाद में उसे छोड़ा. इस मामले में ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी मानते हैं कि अपराध गंभीर क़िस्म का है और ऐसे मामले में 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन पुलिस का रवैया संवेदनहीन ही रहा. राजस्थान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि छुन्नी को वधूशुल्क चुकाकर रमेश ने ख़रीदा और उससे विवाह किया. यह परंपरा राजस्थान में कई पिछड़े समाजों में है. छुन्नी मध्यप्रदेश की है और उसे रमेश ने ख़रीदा फिर विवाह किया. इसलिए पुलिस इस मामले में सामाजिक रिवाज़ों के कारण बीच में नहीं पड़ना चाहती. अधिकारी यह भी कहते हैं कि दो माह तक रमेश ने छुन्नी को घर में अच्छे से रखा, इसलिए प्रताड़ना का मामला भी नहीं बनता है और देह शोषण या बलात्कार का मामला तो बनता ही नहीं है, क्योंकि छुन्नी रमेश की विवाहिता पत्नी है. छुन्नी के अवयस्क होने पर पुलिस का तर्क है कि राजस्थान में बाल विवाह प्रचलन में है और छुन्नी की आयु इतनी कम भी नहीं हैं कि वह पत्नी का शारीरिक सुख देने का धर्म पूरा करने में अक्षम हो. कुल मिलाकर छुन्नी के मामले में कुछ भी नहीं हुआ और छुन्नी का सौदा करने वाले और उसका देह शोषण करने वाले चैन से बैठे हुए हैं. इस संवेदनहीन रवैये के कारण ही ग़रीब और अशिक्षित महिलाओं की ख़रीद–फ़रोख्त का कारोबार जारी है.

घरेलू नौकरों का शोषण

सिर्फ़ मुम्बई, दिल्ली ही नहीं, छोटे–छोटे शहरों में भी घरेलू नौकरों की कमी महसूस की जा रही है. इसके लिए ग़रीब और आदिवासी परिवारों की युवतियों को पसंद किया जाता है. कई बार तो मामूली जान पहचान पर ही उनके परिवार वाले घरेलू नौकर बनने के लिए उनके मालिकों को सौंप देते हैं. विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान पहचान वालों के आग्रह पर घरेलू नौकर के रूप में आदिवासी बालिकाओं को उनके हवाले करा देते हैं. इन बालिकाओं के परिवार वाले भोले–भाले और अशिक्षित होते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा भी कर लेते हैं. कई मामलों में नतीजे अच्छे मिलते हैं तो कई मामलों में धोख़ा भी होता है.

बैतूल ज़िले के ठेसका गांव का खेतीहर मज़दूर हल्के ख़ुश है कि साहब के साथ उसकी बेटी शहर गई है. गांव में 8वीं कक्षा तक पढ़ी उसकी बेटी ने पांच साल में 12वीं पास कर ली और नर्सिंग कॉलेज में उसे एडमिशन भी मिल गया. वह साहब गुणगान करता रहता है. कुछ लोग ऐसे प्रचार का अनुचित लाभ उठाते हैं. डिण्डौरी के पास के सूखा गांव की कलिया बताती है कि भिलाई में उसकी बेटी साहब के घर काम करती थी और साहब ने उसका विवाह अपने ड्राइवर से करा दिया. दामाद के पास पक्का मकान, टीवी और स्कूटर भी है. वह साहब की इस कृपा का जब तब बखान करती रहती है, लेकिन हल्के और कलिया भाग्यशाली हैं, जो उन्हें अच्छे और नेक लोग मिले. पर ज़्यादातर मामलों में बालिकाओं के साथ धोख़ा ही होता है.

भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ा रूपया खर्च कर अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं. इसके अलावा अगर रोज़गार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को रोज़गार मिले और नियमित मज़दूरी का भुगतान हो, तो शायद ही कोई आदिवासी गांव छोड़कर जाए. इसी प्रकार यदि सस्ते राशन का पर्याप्त और नियमित वितरण होता तो भी आदिवासी पेट भरने के लिए गांव छोड़कर नहीं जाते. इसी कारण असामाजिक तत्व आदिवासी क्षेत्रों में महिला एवं बाल व्यापार का जाल फैलाए हुए हैं और यह जाल भी सरकार के संवेदनहीन पुलिस और प्रशासन तंत्र की उदासीनता और एक हद तक मिली भगत के कारण मज़बूत होता जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सीता सागर तालाब आज भी सूखा है

दतिया में पेयजल की समस्या दिन–ब–दिन बढ़ती ही जा रही है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार की तरफ़ से कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, पर अब तक इसका सही समाधान नहीं निकल पाया है. वर्ष 2006 में जलाभाव की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2.27 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की गई थी, वर्ष 2008 में 4 करोड़ 36 लाख रूपये की लागत लगाकर रिचार्ज योजना के तहत पेयजल संकट को हल करने की बात कही गई थी. पर करोड़ो रूपये की धनराशि के आवंटन के बाद भी यह समस्या हल नहीं हो पाई है. दरअसल यहां की पेयजल समस्या का मुख्य कारण है यहां के इस ऐतिहासिक तालाब की बदहाली. करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी दतिया का ऐतिहासिक तालाब सीता सागर बदहाली की स्थिति से उबर नहीं पाया है. लगातार हुए धनराशि आवंटन के बाद भी यह तालाब अब तक जलाभाव से ग्रसित है.

बदहाल सीता सागर तालाब

पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 4 करोड़ 36 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत कराकर इस जलाशय को भरने के काम का उद्घाटन किया था. भूमि पूजन के तीस दिन बाद तक कार्य पूरा करने का निर्देश स्थानीय एजेंसी को दे दिया था. संबंधित विभाग ने भी निर्धारित समय सीमा पर मंत्री के आदेशों की पूर्ति करते हुए काम पूरा करने का आश्वासन दिया था. इसके साथ ही विभाग ने यह भी वादा किया था कि सीता सागर तालाब अनुरक्षण के अभाव में कभी खाली नहीं होगा. सीता सागर तालाब के पुनर्भरण की योजना रिचार्ज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और इसके जगह पर उपलब्ध कराए गए करोड़ो रूपए के बजट का उपयोग किसी अन्य कार्य में लग रहा है. दरअसल दतिया के सीतासागर तालाब को पूरी तरह से भरने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत की गई उपरोक्त धनराशि का उपयोग इसके सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा है. मंत्री के आदेश और विभाग के वायदे के विपरीत कुछ ही समय बाद सीतासागर रिचार्ज योजना के ठीक प्रकार से लागू ना किए जाने के कारण यह तालाब पुन: सूख गया है. इस योजना के तहत अंगूरी बैराज से सीतासागर तक पानी लाने के लिए एक योजना तैयार की गई थी जिसमें बैराज से चितुंवा तक एक कच्ची नहर भी खोदी गई थी. इसके बाद एक पम्प हाउस बनाकर 12 इंच वाले पाईप के माध्यम से झांसी रोड़ भारतीय विद्यापीठ तक पानी लाया गया. 4 करोड़ 36 लाख रूपये ख़र्च करके भारतीय विद्यापीठ से बुंदेला कॉलोनी तक एक नहर का निर्माण किया गया था. इस पूरी योजना को स्थानीय एजेंसी ने सीता सागर तालाब में जल की उपलब्धता बनाए रखने का स्थाई हल मान लिया था. और यही दतिया के पेयजल समस्या का हल भी मान लिया गया. पर यह स्थाई उपाय पेयजल की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाई और लोगों को फिर से जलाभाव के दिन देखने पड़ रहे हैं. सीतासागर के आसपास किए गये अतिक्रमण पेयजल के इस संकट के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है.

सुनीता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

नक्सली राजधानी तक आ गए हैं

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों के प्रशासन और पुलिस उन पर सरकार ही नहीं, बल्कि भारत नियंत्रण पाने के लिए पूरी छोटे–छोटे दलों में बंटे नक्सली अपने प्रभाव उनका निशाना है देवभोग क्षेत्र. देवभोग हीरा क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर सरकार से मुक़ाबला नक्सलियों ने इंदा गांव रेंज के एक उप विभाग व अन्य सरकारी कर्मचारियों को के बाद कई छोटे कर्मचारियों ने अपने

हौंसले बुलंद हैं. तमाम कोशिशों के बाद भी नकेल लगाने में सफल नहीं हुई है. राज्य सरकार भी नक्सलवादी गतिविधियों पर कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी क्षेत्र को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं. अब भण्डारों से भरपूर क्षेत्र है और नक्सली इस करना चाहते हैं. कुछ दिन पहले देवभोग में वननिरीक्षक की हत्या कर इस क्षेत्र के वन भयभीत और आतंकित कर दिया. इस घटना परिवारजनों को यहां से दूर भेज दिया है. सूत्र बताते है कि डिप्टी रेंजर गोकुल प्रसाद तांडी को कहीं से यह सूचना मिली थी कि इंदा गांव के आस–पास के जंगलों में कुछ लोग पेढ़ों की कटाई अवैध रूप से कर रहे हैं. सूचना पाकर डिप्टी रेंजर अपने पांच सहयोगी कर्मचारियों के साथ वहां गए. तभी वहां मौजूद नक्सलियों ने उन सभी वनकर्मियों को अपनी गिरफ़्त में ले लिया. डिप्टी रेंजर के अलावा अन्य वनकर्मियों को मार–पीट कर भगा दिया. इसके बाद डिप्टी रेंजर गोकुल प्रसाद को पीट–पीट कर मार डाला गया और उसके शव को सड़क से एक किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया. ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने के 6 घंटे बाद भी पुलिस बल घटना स्थल पर नहीं पहुंचा क्योंकि पुलिस कर्मियों को भी नक्सलियों का भय सताता रहता है. इस घटना से वन और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् दूसरे सरकारी विभागों के छोटे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी है. राज्य के पुलिस महानिदेशक विश्व रंजन भले ही नक्सलियों से आर–पार की लड़ाई लड़ने की बात कहकर पुलिस बल का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के पांव नए क्षेत्रों में जमना इस बात का सबूत है कि पुलिस कार्यवाही से उनके हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं. अगर ऐसी वारदातें होती रहीं तो राज्य में भय और आतंक का माहौल और बढ़ जाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विकास कार्य सिर्फ़ काग़ज़ों में सिमटा

असगर कुरैशी

यूं तो मध्य प्रदेश में विलुप्त होते आदिवासियों के विकास के लिए हर वर्ष सैंकड़ों योजनाएं लागू की जाती हैं, पर हक़ीक़त ये है कि सभी योजनाएं सिर्फ़ काग़ज़ों में सिमट कर रह जाती हैं और इन योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि से सरकारी बाबू अपना वारा–न्यारा करते हैं.

आदिवासी बाहुल्य ज़िलों की आज हालत ये है कि लूट– खसोट से लेकर सैकड़ों बीमारियां इन्हें अपनी गिरफ़्त में लिए हुए हैं और प्रशासन अपने काग़ज़ी विकास से अपनी पीठ थपथपा रहा है. इन ज़िलों में लूट की वारदातें खुलेआम हो रही हैं. जिला प्रशासन के अधिकारी सरकारी योजनाओं का काग़ज़ों में क्रियान्वयन कर ज़िले की विकास योजनाओं के लिए मिलने वाले धन का व्यापक दुरूपयोग करने पर आमादा हैं. अधिकारी खुलेआम स्वीकार करते हैं कि अर्जित की जाने वाली अवैध धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उन्हें ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, यही कारण हैं कि कई केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद भी मंडला अभी तक औसत दर्ज़े का विकसित ज़िला भी नहीं बन पाया है.

मंडला ज़िले में सबसे ताज़ा प्रकरण उस समय सामने आया, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बधाई पत्र ज़िले के कई आदिवासियों को प्राप्त हुआ. 28 दिसम्बर 2009 को भेजे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेतों को सिंचित करने के लिए कपिल धारा योजना के अंतर्गत कूप खनन पर इन आदिवासियों को बधाई दी है. इस पत्र के प्राप्त होने के बाद संबंधित आदिवासियों ने खोज करनी शुरू की, कि उनके खेत में ज़िला प्रशासन ने कुंआ आख़िर खोदा कहां हैं. इस तरह की खोज बिछिया जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत

स्कूल की टूटी हुई छत

खंडहर में तब्दील स्कूल

अंजनिया के श्री आनंद पूरन, कृष्णदयाल शंकर सहित कई लोगों ने प्रारंभ की.

चौथी दुनिया ने इस बारे में जब विस्तार से पड़ताल की तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए, मंडला ज़िले में अब तक रोज़गार गारंटी योजना चालू होने के बाद लगभग 5000 कुंओ का निर्माण किया गया है. जिनकी लागत 64 करोड़ रूपये आंकी गई है. इस 64 करोड़ रूपये के कार्य का कोई रिकॉर्ड ज़मीन पर मौजूद नहीं है. ग्राम अंजनिया के किसानों को मुख्यमंत्री के पत्र के बाद यह ज्ञात हुआ हैं कि कपिलधारा योजना के तहत उनके विकास के लिए ज़िला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में कुंओ का निर्माण भी करना था जो काग़ज़ों में किया जा चुका है.

ज़िला पंचायत के विवादास्पद मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री जगदीश चंद्र जटिया इस प्रकरण से अंजान बनने की कोशिश करते रहे, उन्होंने केवल यही कहा कि हम जांच ज़रूर करवाएंगे. जब यह प्रकरण मुख्यमंत्री की जानकारी में डाला गया तो उन्होंने भी घटना क्रम की जांच का आश्वासन ही दिया. एक जानकारी के अनुसार ज़िला पंचायत मंडला को वर्ष 2006 से 2009 तक 10173 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, पंचायत ने 10052 कार्य प्रारंभ कर दिए और 9025 कार्यों को पूर्ण भी कर दिया. इन कार्यों में पंचायत द्वारा 6445.628 लाख रूपये का व्यय भी कर दिया गया.

मंडला ज़िला जबलपुर से 98 किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण राज्य गठन से ही भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र रहा है. संचार साधनों और आवागमन के साधनों की कमी के कारण और ज़िले के आदिवासी स्वरूप के कारण केंद्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाली करोड़ों रूपये की अनुदान राशि यहां भ्रष्टाचार के लिए एक स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण करती है. यही कारण है कि यहां पदस्थ अधिकतर अधिकारियों ने अर्जित की गई धनराशि को कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में ही स्वयं के हितों के लिए व्यय किया है. वर्तमान ज़िला पंचायत के कार्यपालक अधिकारी के परिवार के भी दो रिसोर्ट इन दिनों निर्माण की अंतिम अवस्था में मंडला ज़िले में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

काग़ज़ों में बनाए गए कुंओ के लाभार्थी आनंद कुमार मरावी के अनुसार उनके खेत में आज तक कोई कुंआ नहीं खोदा गया है, तो बधाई किस बात की. उन्होंने कूप निर्माण के लिए पंचायत में आवेदन ज़रूर दिया है. इसी गांव के कृष्ण दयाल शंकर के अनुसार उन्हें भी एक पत्र मिला है. जिस इंदिरा आवास में वे रह रहे हैं उसमें एक झोपड़ी हैं जिसमें न दरवाजे हैं और न छत. उनके अनुसार वे कई सालों से आवेदन लगा रहे हैं कि इंदिरा आवास में ज़िले में भारी भ्रष्टाचार के वे स्वयं जीते जागते प्रमाण हैं.

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार मंडला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, झाबुआ, धार आदि आदिवासियों ज़िलों में ही होती हैं, इन सब में ही मंडला संभवत प्रथम स्थान पर माना जा सकता है. एक अनुमान के अनुसार विलुप्त होती मानव प्रजाति बैगा के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य शासन ने जितनी राशि का आवंटन किया है, यदि उस राशि को एकत्र करके कुल बैगा संख्या में बराबरी से बांट दिया जाए तो प्रत्येक बैगा परिवार को कम से कम सात लाख रू. की राशि नकद दी जा सकती है. परंतु इस क्षेत्र का बैगा आज भी वस्त्रहीन और प्रकृति के भरोसे अशिक्षित रहकर जीवन यापन करने के लिए बाध्य है.

feedback@chauthiduniya.com

औद्योगिक विकास का अभिशाप भोगता बचपन

युगल किशोर तिवारी

रायगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनी हुई है. यहां इस्पात एवं लौह धातुकर्म उद्योग के साथ ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करने के बाद अब पूरे रायगढ़ ज़िले को ऊर्जा केन्द्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस शहर में औद्योगीकरण से उद्योगपतियों को करोड़ो रूपये की आय हो रही है, हज़ारों लोगों को काम मिला हुआ है और इस क्षेत्र का आर्थिक और भौतिक विकास भी हो रहा है, लेकिन इस विकास के वरदान के लाभ कम है, विकास का अभिशाप कहीं ज़्यादा है. जिंदल और सेनर्जी एण्ड पॉवर कम्पनी जैसे उद्योगों के कारण अब स्कूली बच्चों का जीवन कष्टप्रद हो चला है.

इस क्षेत्र के विकास का अभिशाप प्रकृति, पशुपक्षी और कमज़ोर इंसान सभी भोग रहे हैं. लोहे और इस्पात के कारखानों तथा ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषित और घातक पदार्थों से इस पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बहुत जल्द ख़तरनाक स्थिति तक फैल जाने के स्तर से बढ़ रहा है. यह प्रदूषण वनस्पति और मानव जीवन पर भी अपना घातक असर दिखा रहा है. कहने को तो उद्योगपतियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं और जनता के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि यहां की जनता और बच्चों का बचपन विकास का अभिशाप भोग रहा है.

उद्योगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में शिक्षा प्रसार भी एक कार्यक्रम है. इसके तहत प्रायोगिक तौर पर जिन्दल स्टील उद्योग और इण्ड इनर्जी कंपनी ने ग्राम मंगलूडीपा और चिराईपानी में दो प्राइमरी विद्यालयों का संचालन अपने हाथों में लिया है. रायगढ़ ज़िला मुख्यालय से केवल छ: किलोमीटर दूर ग्राम चिराईपानी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 52 छात्र हैं. लेकिन इस स्कूल की बदतर हालत का वर्णन शब्दों में करना कठिन है. चौथी दुनिया संवाददाता ने इस स्कूल का जायज़ा लिया. यह देखना आश्चर्यजनक है कि स्कूल की बिल्डिंग से तीन–चार फुट दूर 50 से 100 फुट के गड्ढे खुदे हुए हैं और स्कूल भवन से 10 फुट की दूरी पर बड़े–बड़े कारखानों के लिए लोहे के एंगल, गार्डर आदि बनाने का काम किया जाता है. इस तरह के काम से स्कूल से इतनी कम दूरी पर किए जाने से स्कूल के आसपास इतना ज़्यादा शोर होता हैं कि पढ़ना–पढ़ाना संभव नहीं होता है. इतना ही नहीं स्कूल के पास भारी वाहन, क्रेन और कई प्रकार की मशीनों की आवाजाही दिन भर होती रहती है, इससे भी कानफाड़ू शोर मचता रहता है. कई बार तो मशीनों की आवाजाही और भारी सामानों को इधर–उधर शिफ्ट करने के कारण बच्चे स्कूल भवन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है.

ऐसा नहीं है कि बच्चों के इस दर्द का एहसास शिक्षकों को नहीं है. स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं. लेकिन नौकरी जाने के भय से वे मुंह बंद रखना ही उचित समझते हैं. फिर भी, नाम न छापने का आश्वासन के बाद एक शिक्षक ने बताया कि कर्कश शोर, वायु प्रदूषण और असुरक्षित माहौल के कारण स्कूल में पंजीकृत 52 छात्रों में से अधिकतम 25 से 30 छात्र ही प्रतिदिन पढ़ाई के लिए आते हैं, चूंकि स्कूल में पढ़ाई का माहौल भी नहीं हैं, इसलिए कुछ घंटे स्कूल में बिताने के बाद बच्चे घर लौट जाते हैं, बचे रह जाते हैं तो बस ड्यूटी के मारे शिक्षक.

इस स्कूल के छात्र रिंकू चौहान और छात्रा राजकुमारी ने बताया कि उन पर अक्सर ख़ांसी, ख़ुजली और बुख़ार जैसे संक्रमण का आक्रमण हो जाता है. यह परेशानी सिर्फ़ उन्हें ही नहीं है, बल्कि इस स्कूल के कई बच्चों को आए दिन ऐसे संक्रमण एवं बीमारियों के होने की शिकायत है. औद्योगिक प्रदूषण के कारण स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन के साथ अनेक बीमारियों के कीटाणु भी बच्चों को परोसे जाते हैं, लेकिन ग़रीब बच्चे खाना खाने के लिए मजबूर होते हैं और सरकारी नियमों के अनुसार मध्यान्ह भोजन खिलाने के लिए शिक्षक बाध्य होते हैं.

स्कूल के पास से गुज़रने वाले भोले–भाले ग्रामीणजनों और उच्च शिक्षित शहरी नागरिकों का मानना हैं कि यह स्कूल अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित है. अत: बच्चों के हित में इस स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए, या फिर स्कूल के आसपास के माहौल को सुधारा जाना चाहिए. लेकिन उद्योगपति मुफ़्त में मिली इस सरकारी ज़मीन के उपयोग को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है. सच्चाई तो यह है कि स्कूल के आसपास की भूमि पर क़ब्ज़ा करने के लिए ही उद्योगपतियों ने स्कूल संचालन का परोपकार करना स्वीकार किया है.

जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के अपने स्कूलों और उनके क़ब्ज़ों के स्कूलों में आम नागरिकों का प्रवेश आसानी से संभव नहीं है. बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई कार्य में बाधा न आने के नाम पर कंपनी की ओर से स्कूल से बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. स्कूल आने–जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इन सुरक्षाकर्मियों की कड़ी पूछताछ और सघन जांच की लंबी प्रक्रिया से गुज़रना होता है. यहां तक कि सरकारी शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इन सुरक्षाकर्मियों की इजाज़त के बाद ही स्कूल की जांच या शिक्षकों को वेतन देने के लिए स्कूल में प्रवेश करने दिया जाता है.

ऐसा नहीं कि कंपनी इस स्कूल की बदहाल अवस्था से अवगत नहीं है. कंपनी ने अपनी ओर से ही यह प्रस्ताव ज़िला प्रशासन के समक्ष रखा है कि वह अपने ख़र्च से इस स्कूल को किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सकती है. इसके लिए कंपनी ने स्कूल से दूर एक स्थान पर नया स्कूल बनाने के लिए निर्माणकार्य भी धीमी गति से शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन के जानकार बताते हैं कि स्कूल स्थानांतरण के नाम पर जिन्दल कंपनी वर्तमान सरकारी स्कूल और उसके आसपास की भूमि पर क़ब्ज़ा करना चाहती है.

मंगलूडीपा स्कूल की दुर्दशा

रायगढ़ से 12 किलोमीटर दूर कोटमार गांव के मंगलूडीपा स्कूल का संचालन इंड सेनर्जी एण्ड पॉवर कंपनी करती है, लेकिन इस स्कूल और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की हालत चिन्ताजनक है. स्कूल में पढ़ने वाला शायद ही कोई बच्चा पूर्णत: स्वस्थ है. सभी छात्रों को ख़ांसी, ख़ुजली की बीमारियां हैं और यहां का प्रदूषण घातक स्तर तक फैला हुआ है.

स्कूल के शिक्षक और गांव के जनप्रतिनिधि इस स्कूल का स्थान बदलने के लिए ज़िला प्रशासन से बार–बार अनुरोध करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है. हालत यह है कि घर से स्नान करके साफ़ सुथरे बच्चे स्कूल आते है, लेकिन दो–तीन घंटे बाद जब वे घर लौटते हैं तो धूल और धुएं से रंगे हुए, जिन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता है. प्रदूषण से बच्चों की त्वचा के साथ–साथ आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है.

खस्ताहाल स्थिति में स्कूल.

ज़िला प्रशासन के आला अधिकारियों, शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों और सांसद से लेकर ग्राम पंच स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को इन दोनों स्कूलों के बारे में सब मालूम हैं और वे यहां का प्रत्यक्ष जायज़ा भी ले चुके हैं, लेकिन राजनीति में मज़बूत पकड़ रखने वाले थैलीशाहों के ख़िलाफ़ मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है. मासूम बच्चे पढ़ाई और एक वक़्त के मुफ्त भोजन की लालसा में स्कूल तो आते हैं, लेकिन उन मासूमों को अपने भविष्य और स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ का अंदाज़ा शायद ही होगा.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

दिल्ली, 1 मार्च–7 मार्च 2010

स्वर्णिम मध्य प्रदेश सिर्फ़ एक सपना है

राज्य सरकार का सपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश वास्तविकता के धरातल से काफ़ी दूर है. लचर प्रशासन और कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह कभी पूरा हो पाएगा, इसमें संदेह है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है, जहां भ्रष्टाचार एवं अराजकता न हो. ऐसे में कैसे बनेगी बात?

संध्या पांडेय

स्वर्णिम मध्य प्रदेश की योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार पर 58000 करोड़ रूपए का क़र्ज़ हो चुका है और उस पर 6500 करोड़ का ब्याज भी चढ़ चुका है. प्रदेश में बच्चों के प्रति अपराधों का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है. राज्य में 40 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, सरकार की देनदारियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. महिलाओं और कमज़ोर तबके पर बढ़ते अपराध और अत्याचार, प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचारों का खुलेआम नज़र आना. यह सब मिलकर प्रदेश के मनोरम स्वप्न को एक डरावनी हक़ीक़त का रूप देते हैं. मध्य प्रदेश के स्वर्णिम बनने के सपने को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बयान देते रहे हैं कि राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाकर वे मध्य प्रदेश के आने वाले कल को सुनहरा और सुरक्षित बनाएंगे. पर इसके विपरीत लगातार सामने आ रहे आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ता लग नहीं रहा है.

मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मासूम बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों का ग्राफ भी लगभग दुगना हो चुका है. वर्ष 2003 में जहां ये आंकड़ा 2662 पर था, वहीं 2008 में यह बढ़कर 4259 तक पहुंच गया है. वर्ष 2007 और 2008 के मध्य इन अपराधों की संख्या में आंशिक कमी ज़रूर आई है, बस यही राहत की बात है, पर यह कमी स्थाई होगी यह कहना कठिन है. आश्चर्य यह है कि बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में अधिकतर घटनाएं महानगरों में ही हुई है. भोपाल में 174, इंदौर में 123 घटनाएं पंजीबद्ध की गई है, बाक़ी अपंजीकृत घटनाओं के आंकड़े सामने नहीं हैं. स्वर्णिम मध्य प्रदेश के घोषित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नज़र आते हैं, परंतु सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये आंकड़ों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह् भोजन, गणवेश वितरण, साईकिल वितरण जैसी योजनाएं पूरी तरह भ्रष्टाचार की परिधि में घिरी हुई हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वर्णिम प्रदेश का सपना मानवीय दृष्टि से उनकी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है, परंतु मुख्यमंत्री मौजूदा प्रशासन वर्ग के साथ जनहित योजना के क्रियान्वयन में कितने सफल हो पाएंगे यह संदेह के दायरे में ही रहेगा. अबतक मिले परिणामों पर ग़ौर किया जाए तो कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह अपने प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रख पाने में असफल रहे हैं.

बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दावा करने वाली सरकार ने मध्य प्रदेश को 58000 करोड़ रूपये के क़र्ज़ में डुबा दिया है. स्थितियां इतनी ख़राब है कि क़र्ज़ों की अदायगी न होने के कारण क़र्ज़ के बराबर की ही राशि ब्याज के रूप में राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार बनकर आ चुकी है. इस वित्तीय वर्ष में इस ब्याज की राशि कितनी बड़ी है इसका आकलन अभी शेष है. सरकार को प्रतिवर्ष अभी तक 6500 करोड़ रूपये का ब्याज चुकाना है. यह राशि आने वाले दस वर्षों में भुगतान की जानी है. एक ओर राज्य सरकार भारी वित्तीय दबाव महसूस कर रही है, तो दूसरी ओर औद्योगिक इकाईयों पर राज्य सरकार के करोड़ों रूपये बिजली बिल के रूप में बकाया हैं.

अपने सेवा निवृत्त अधिकारियों को विद्युत वितरण कंपनी के सर्वोच्च पदों पर बलात दिखाने पर आमादा राज्य सरकार भिण्ड, मुरैना से लेकर चुलबुली, टीकमगढ़ तक छोटे ज़िलों में करोड़ों रूपये की राशि वसूल कर पाने में अक्षम रही है. इस जानकारी के अनुसार औद्योगिक इकाईयों पर 1740 करोड़ रूपये की राशि बकाया है. औद्योगिक विकास के नाम पर औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली छूट से प्रदेश के वित्तीय तंत्र को भारी नुक़सान हुआ है. वस्तुत: राज्य सरकार वह सामंजस्य शामिल नहीं कर पा रही जिसके तहत प्रदेश के आय और व्यय को संतुलित किया जा सके. दूसरी ओर शासन में सक्रिय दलालों का सक्रिय तंत्र शासन की योजनाओं को जन उपयोगी बनने के पहले ही व्यक्तिगत लाभ के लिए उनके दोहन का पर्याप्त मार्ग खोज पाने में सफल रहा है.

स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना तब और कमज़ोर नज़र आया जब राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारियों के घर छापों के दौरान करोड़ों रूपये की राशि मिली, पर यह केवल शिवराज सिंह चौहान के समय का हाल नहीं है. आरोप है कि आज भ्रष्टाचार पंचायत स्तर तक फैल गया है. इसी का परिणाम है कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हर ग़ैर क़ानूनी कार्य को पूरा करने के लिए उतने ही तत्पर है जितना वे काग़ज़ों और भाषणों में प्रदेश के विकास के प्रति समर्पित नज़र आते है. मुख्यमंत्री से लेकर राज्य मंत्रिमण्डल के आधे से अधिक सदस्य लोकायुक्त भ्रष्टाचार की सीमाओं में क़ैद हैं. सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूक होने का दावा भले ही करे पर वास्तविकता यह है कि स्वयं सरकार आगे बढ़कर राज्य के शोषण के लिए ज़िम्मेदार बन रही है.

स्वर्णिम मध्यप्रदेश की परिकल्पना को खंडित करते हुए सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में करोड़ो रूपये के भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक कमान सरकार के पास उपलब्ध है जिसपर जांच की जानी शेष है. मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंच पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए दोषी बताए जाते हैं. सरकार की एक सभा में बिहार के युवकों को मध्य प्रदेश में नौकरी न देने की बात करके वह बदनाम हो चुके हैं, हालांकि बाद में उन्होंने इसके बारे में सफ़ाई दे दी थी. अभी तक इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 में 29 साम्प्रदायिक घटनाएं पंजीबद्ध हुई हैं. सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के लिए भाजपा के अन्य संगठन भी ज़िम्मेदार हैं. इन संगठनों के द्वारा की गई कार्यवाही का परिणाम ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना के रूप में सामने आया है. पुलिस तंत्र में व्याप्त जातिगत द्वेष की भावना राज्य की शांति व्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हुई है.

आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों में राज्य में व्यापक वृद्धि हुई है. हर महीने 80 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं राज्य में एक तरह का नया रिकॉर्ड है. वर्ष 2006 में जहां 829 महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध पंजीबद्ध हुए, वहीं 2008 में इनकी संख्या 892 बताई जाती है. अपंजीकृत अत्याचारों और शोषण के आंकड़े अलग से हैं. राज्य शासन महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर विभिन्न उपायों का उल्लेख ज़रूर करता रहा है पर अभी तक इस संदर्भ में कोई ठोस क़दम सरकार की ओर से नहीं उठाए गए हैं.

आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं.

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति राज्य सरकार का रवैया बहुत प्रभावशाली नहीं है. नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत आम हो चुकी है. पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को स्थापित करने में नरेगा की भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता है. राज्य के समस्त पिछड़े ज़िलों में नरेगा से संबंधित सभी शिकायतें लगभग लंबित है. राज्य सरकार के पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गये मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने नरेगा को एक स्थाई अवैध आमदनी का ज़रिया बना दिया है. पिछले पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार से सड़क निर्माण के नाम पर मिली हुई राशि का पूरा उपयोग कर पाने में सरकार असफल रही है. सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बनवाई जा रही सड़कें मापदण्ड से विपरीत केवल अस्थाई रूप में नज़र आती हैं. निर्माण के बाद होने वाली पहली बरसात में इन सड़कों का अस्तित्व संकट में पड़ना तय है.

स्वजलधारा योजना के तहत राज्य के आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों मे किया जा रहा काम पूरी तरह काग़ज़ी है. इस योजना में अब तक 25 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी की बात सामने आई है. राज्य में स्वीकृत 28900 स्व जल धाराएं योजनाओं में से अब तक केवल 728 योजनाएं ही पूरी की गई हैं. पूरी की गई योजनाओं के संदर्भ में ही यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ये योजनाएं सफल नहीं मानी जा सकती हैं. राज्य सरकार द्वारा स्वयं क़र्ज़े में डूबे रहने के बाद दूसरों को गारंटी देने की प्रवृत्ति राज्य को भीषण तंगी की ओर ले गई है. सरकार द्वारा इस तरह की गारंटी देने के बावजूद राज्य पर लगभग 60 करोड़ का क़र्ज़ चढ़ चुका है. सरकार ने 13000 करोड़ के ख़र्च पर बैंक गारंटी दे रखी है. यह गारंटी कुछ निजी कंपनियों के अलावा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं और निगम मण्डलों की वजह दी गई है.

स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना शिवराज के निजी फ़ायदे के रुप में तब्दील हो गया है. राज्य के नाकारा विपक्ष कांग्रेस द्वारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के विरोध में कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया गया. वस्तुत: कांग्रेस के कई नेता इस बहती गंगा में स्वयं हाथ धो रहे है. कमज़ोर विपक्षी नेता की उपस्थिति से प्रदेश में सुशासन की बात सोच पाना या उसके पक्ष में कोई आंदोलन खड़ा कर पाना असंभव हो चुका है. मध्यप्रदेश एक सर्वकालिक बीमार राज्य बने की ओर बढ़ रहा है. दिग्विजय सिंह के दस वर्ष के शासन काल के दौरान जिस भ्रष्टाचार के तंत्र की बुनियाद रखी गई थी वही आज केवल सपने और उसके क्रियान्वयन के फ़र्ज़ी आंकड़ों का कंकाल बनकर खड़ा दिख रहा है.

feedback@chauthiduniya.com